किसी भी तरह के विज्ञापन एवं समाचार के लिए संपर्क करें मो0: 9891706853

दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

RNI: UPHIN/2021/84200

समाज जागरण

नोएडा उत्तर प्रदेश,दिल्ली एनसीआर, हरियाणा,पंजाब बिहार,मध्य प्रदेश, छतीसगढ, झारखण्ड असम से प्रसारित

दैनिक हिन्दी समाचार · समाज जागरण · RNI NO. UPHIN/2021/84200

वर्षः 4 अंकः 272 नोएडा, (गौतमबुद्धनगर) शनिवार 11 जुलाई 2026 http://samajjagran.in पृष्ट - 12 मूल्य 05 रुपया

आगरा में 11 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

समाज जागरण

आगरा। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत थाना खेरागढ़ पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 अतिरिक्त मैग्जीन, एक महिंद्रा थार, दो मोबाइल फोन तथा 5,850 नकद बरामद किए हैं। मामले का खुलासा अपर पुलिस आयुक्त सचिन्द्र पटेल ने प्रेस वार्ता में किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।

मेरठ एसएसपी का अनोखा संदेश: 'विरोधी दो पेड़ लगाएं, समर्थक एक पेड़'

मेरठ समाज जागरण

मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अविनाश पांडेय का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने कहा कि "जो भी कार्रवाई हुई है, वह अपराधियों के खिलाफ हुई है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई करती है। एसएसपी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा, "जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, वे दो पेड़ लगाएं और जो लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, वे एक पेड़ लगाएं।" उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

दिल्ली-रेवाड़ी, शकूरबस्ती-बठिंडा समेत प्रमुख रेलखंड होंगे अधिक सुरक्षित; रायपुर में 175 करोड़ से विकसित होगी इलेक्ट्रिक लोको की नई होमिंग सुविधा

680 किमी रेलमार्ग पर लगेगा 'कवच 4.0', 206 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

नई दिल्ली समाज जागरण ब्यूरोः भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल में 680 रूट किलोमीटर रेलमार्ग पर स्वदेशी 'कवच 4.0' सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए 206 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना दिल्ली-रेवाड़ी, शकूरबस्ती-बठिंडा रेलखंडों सहित फीडर शाखा लाइनों पर लागू की जाएगी।

रेल मंत्रालय के अनुसार यह पहल देशभर के व्यस्त और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलमार्गों पर स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली के विस्तार अभियान का हिस्सा है। 'कवच 4.0' के लागू होने से रेल संचालन पहले से अधिक सुरक्षित, आधुनिक और तकनीक आधारित होगा।

दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम

'कवच' भारत में विकसित अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली है, जो सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) जैसी घटनाओं और ट्रेनों की टक्कर को रोकने में सक्षम है। यह प्रणाली ट्रेनों की रियल-टाइम निगरानी करती है और आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाकर दुर्घटना की आशंका को समाप्त करती है। साथ ही निर्धारित गति सीमा का पालन सुनिश्चित करती है तथा घने कोहरे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुरक्षित रेल संचालन में मदद करती है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद संबंधित रेलखंडों पर यात्री एवं मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल होगा।

रायपुर में 175 करोड़ से मजबूत होगा इंजन रखरखाव

रेलवे ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर उच्च अश्वशक्ति (एचएचपी) डीजल शेड में 250 तीन-फेज विद्युत इंजनों के लिए अतिरिक्त होमिंग सुविधाएं विकसित करने हेतु 175 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की है।

रेलवे के अनुसार 'होमिंग' का अर्थ किसी लोकोमोटिव को एक निर्धारित लोको शेड से जोड़ना होता है, जहां उसकी नियमित मरम्मत, सुरक्षा जांच और तकनीकी रखरखाव किया जाता है। इस परियोजना से बढ़ते इलेक्ट्रिक इंजन बेड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप रायपुर डिपो की क्षमता भी बढ़ेगी।

मुख्य बिंदु

680 रूट किमी रेलमार्ग पर लगेगा कवच 4.0

परियोजना पर खर्च होंगे 206 करोड़ रुपये

दिल्ली-रेवाड़ी और शकूरबस्ती-बठिंडा रेलखंड होंगे शामिल

ट्रेन टक्कर और सिग्नल उल्लंघन रोकने में मदद करेगी स्वदेशी तकनीक

रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए 175 करोड़ की नई होमिंग सुविधा को भी मंजूरी

40 साल बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने दी शुभकामनाएं

पीएम ने जताया आभार, ऑकलैंड एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने किया गर्मजोशी से स्वागत

समाज जागरण

ऑकलैंड/नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक न्यूजीलैंड दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने भारत-न्यूजीलैंड संबंधों की प्रगति और मित्रता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ली के संदेश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मित्र देशों से मिलने वाले ऐसे स्नेहपूर्ण संदेश हमेशा विशेष होते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। दोस्तों की ओर से मिले ऐसे स्नेहभरे संदेश हमेशा खास होते हैं।"

राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने भी 'एक्स' पर भारत और न्यूजीलैंड की दोस्ती एवं समृद्धि की कामना करते हुए वह वीडियो साझा किया, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ऑकलैंड एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते नजर आ रहे हैं।

40 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। करीब 40 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचा है। विशेष सम्मान के तौर पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन स्वयं एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री लक्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देने पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि शनिवार को वह ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध भी हो रहे मजबूत

उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने इसी वर्ष अप्रैल में भारत की राजकीय यात्रा की थी। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा था। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों का उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी भारत आया था। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई थी।

प्रो बॉक्सिंग लीग 2026 के ग्रैंड फिनाले में जुटे भाजपा के शीर्ष नेता

तालकटोरा स्टेडियम में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह, बोले- भारत में बॉक्सिंग प्रतिभाओं की नहीं है कमी

समाज जागरण

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन (IABF) की प्रो बॉक्सिंग लीग (PBL) 2026 के ग्रैंड फिनाले में खेल और राजनीति जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। इस दौरान नेताओं ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए लीग को भारतीय बॉक्सिंग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने मुकाबलों का आनंद लेने के बाद कहा कि इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का यह प्रयास देश में बॉक्सिंग की नई संस्कृति विकसित करने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले चार दिनों में चार टीमों के 32 खिलाड़ियों ने जिस स्तर का प्रदर्शन किया है, उससे स्पष्ट है कि भारत में प्रतिभाशाली मुक्केबाजों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी पेशेवर लीग खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर मंच और तैयारी उपलब्ध कराती हैं।

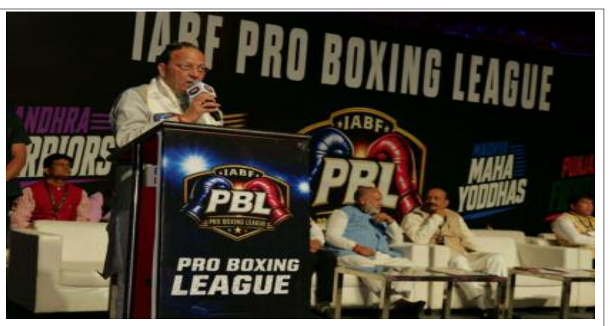

इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी ग्रैंड फिनाले में पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज इस मंच पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे खिलाड़ी भविष्य में एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों से पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में दिल्ली के विधायक अशोक गोयल, दिल्ली के पूर्व महापौर जयप्रकाश तथा असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल भी मौजूद रहे। अशोक सिंघल ने ईस्टर्न टाइगर्स टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि पूर्वी भारत के खिलाड़ियों ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है और इस लीग में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है।

पूर्व महापौर जयप्रकाश ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर भी प्रदान करती हैं।

चार दिनों तक चली इस फ्रेंचाइजी आधारित प्रो बॉक्सिंग लीग में देशभर के 32 मुक्केबाजों ने चार टीमों का प्रतिनिधित्व करते हुए रोमांचक मुकाबले खेले। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन तकनीक, फिटनेस और जुझारूपन का प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में नेमीषशरण पीठ के रंजीत शास्त्री भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

'एक पेड़ माँ के नाम 3.0' अभियान: नोएडा में 11 जुलाई तक मिलेंगे निःशुल्क पौधे

नोएडा समाज जागरण ब्यूरो

'एक पेड़ माँ के नाम 3.0' वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत नोएडा प्राधिकरण 9 जुलाई से

11 जुलाई 2026 तक शहर के विभिन्न स्टोर एवं नर्सरियों से नागरिकों को निःशुल्क पौधों का वितरण कर रहा है।

प्राधिकरण के अनुसार नागरिक सेक्टर 122, 60, 44, 50, 82, 142, 135, 8, 32, 39 और 150 स्थित नर्सरियों से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में पौधे लेकर उनका रोपण करने तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।

50-60 किमी का रोजाना चक्कर कब होगा खत्म ? मड़वा घाट मार्ग बना हजारों लोगों की जीवनरेखा

सड़क नहीं बनने से मरीज, किसान और विद्यार्थियों की बढ़ी मुश्किलें, ग्रामीण बोले- अब नहीं वादे, चाहिए निर्माण

समाज जागरण जिला संवाददाता : उदय सिंह लोधी

पन्ना/रैपुरा। पन्ना जिले का बहुप्रतीक्षित मड़वा घाट मार्ग अब केवल सड़क निर्माण का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह हजारों ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा जनआवश्यकता का बड़ा प्रश्न बन चुका है। वर्षों से लंबित इस मार्ग के निर्माण की मांग अब तेज होती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनने के कारण उन्हें प्रतिदिन 50 से 60 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे समय, ईंधन और धन—तीनों की भारी बबार्दी हो रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार मड़वा घाट मार्ग बनने से रैपुरा सहित आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क पन्ना जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सीधा और सुगम हो जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी।

ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने में अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे परिवहन लागत बढ़ जाती है। वहीं, विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज आने-जाने में रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बरसात के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जिससे लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं।

क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि मड़वा घाट मार्ग के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उनका कहना है कि इस सड़क के बनने से हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को नई गति मिलेगी।

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से यह मांग केवल आश्वासनों तक सीमित रही है।

अब समय आ गया है कि सरकार इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर ठोस निर्णय लेकर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करे, ताकि क्षेत्र की जनता को अनावश्यक चक्कर, अतिरिक्त खर्च और दैनिक परेशानियों से स्थायी राहत मिल सके।

मुख्य बिंदु

मड़वा घाट मार्ग नहीं बनने से रोजाना 50-60 किमी अतिरिक्त सफर।

मरीज, किसान, विद्यार्थी और आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित।

सड़क बनने से रैपुरा सहित कई गांवों की कनेक्टिविटी होगी बेहतर।

ग्रामीणों ने सरकार से मार्ग निर्माण को प्राथमिकता देने की मांग की।

लोगों का कहना—यह सड़क नहीं, क्षेत्र के विकास की जीवनरेखा है।

20 घंटे की बारिश के बाद नोएडा प्राधिकरण अलर्ट, जलभराव वाले क्षेत्रों में चलाया विशेष अभियान

समाज जागरण ब्यूरो

नोएडाः लगातार लगभग 20 घंटे हुई बारिश के बाद उत्पन्न जलभराव की शिकायतों पर नोएडा प्राधिकरण ने सभी 10 वर्क सर्किलों में विशेष अभियान चलाकर जल निकासी कराई। जेसीबी, हाइड्रा, पोकलेन, सुपर सकर समेत विभिन्न मशीनों की मदद से सड़कों, नालों और अंडरपासों से पानी निकालकर यातायात को सुचारु बनाया गया। प्राधिकरण के अनुसार जल विभाग द्वारा चिन्हित 28 लो-लाइंग क्षेत्रों में डीजल पंपसेट लगाकर जलभराव की स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। बेसमेंट में

जलभराव की शिकायतों का भी तत्काल निस्तारण किया गया। साथ ही शहर के प्रमुख नालों की लगभग 80 प्रतिशत डिसिल्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए 24.7 कॉल सेंटर (0120-2423795) तथा क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) लगातार सक्रिय है और शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई कर रही है।

इसके अलावा शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण और सी एंड डी वेस्ट के नियमित निस्तारण का कार्य भी लगातार जारी है।

यूपी वक़्फ बोर्ड में हिन्दुओं की एंट्री 'ऐतिहासिक न्याय'

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वक़्फ बोर्ड में दो हिंदू (गैर-मुस्लिम) सदस्यों की नियुक्ति के फैसले ने देश की सियासत और सामाजिक विमर्श में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर लिए गए इस फैसले को जहां एक पक्ष 'ऐतिहासिक न्याय', पारदर्शिता और बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता में दखल और मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है। वैसे, नए वक़्फ बोर्ड में हिंदू ही नहीं, महिलाओं और पसमांदा समाज के मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह मुद्दा केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसके तार जमीनी विवादों, ऐतिहासिक दावों, वक़्फ कानून की असीमित शक्तियों और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार और हिंदू विचारकों का मानना है कि यह फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि एकतरफा फैसलों पर रोक लगाने और वक़्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में 'चेक एंड बैलेंस' (संतुलन) स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है कि किसी भी विवाद में दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अब तक स्थिति यह थी कि यदि वक़्फ बोर्ड किसी हिंदू की जमीन या किसी प्राचीन मंदिर पर अपना दावा ठोकता था, तो उस विवाद का निपटारा करने वाली कमेटी में सभी सदस्य मुस्लिम होते थे। ऐसे में पीड़ित पक्ष (हिंदू) को हमेशा यह मलाल रहता था कि बोर्ड के भीतर उसका पक्ष रखने या समझने वाला कोई नहीं है। दो हिंदू सदस्यों की मौजूदगी से बोर्ड के भीतर एक बहु-सांस्कृतिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित होगा। वक़्फ एक्ट, 1995 (विशेषकर 2013 के संशोधनों के बाद) के तहत बोर्ड को किसी भी संपत्ति को 'वक़्फ की संपत्ति' घोषित करने के बेहद व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। यदि बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति मान लेता है, तो पीड़ित व्यक्ति सीधे दीवानी अदालत नहीं जा सकता; उसे वक़्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील करनी होती है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि जब बोर्ड के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं, तो उसका स्वरूप पूरी तरह एकतरफा नहीं होना चाहिए, खासकर तब, जब विवाद गैर-मुस्लिमों की संपत्तियों से जुड़ा हो।

इस पर योगी सरकार और समर्थकों का आरोप है कि दशकों से राजनीतिक दलों ने वक़्फ बोर्ड को एक स्वायत्त साम्राज्य की तरह काम करने की छूट दे रखी थी, ताकि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। इस व्यवस्था में सुधार करना तुष्टिकरण को खत्म कर 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र को धरातल पर उतारना है। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विरोध कर रहे मौलानाओं का तर्क है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। वक़्फ मूल रूप से इस्लाम के 'अल्लाह की राह में दान' के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था है। उनका कहना है कि जिस तरह तिरुपति देवस्थानम, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या अन्य हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में किसी गैर-हिंदू को सदस्य नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह वक़्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति करना इस्लामी कानूनों और परंपराओं के खिलाफ है।

विपक्षी दलों (जैसे सपा, कांग्रेस और ओवैसी की एआईएमआईएम) का आरोप है कि सरकार वक़्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने या उसकी शक्तियों को कमजोर करने के लिए यह कदम उठा रही है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इसे समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा करने और बहुसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा मानता है। उनका कहना है कि यदि बोर्ड में कोई विसंगति थी, तो उसे कानूनी सुधारों या मुस्लिम समाज के ही ईमानदार विशेषज्ञों को शामिल करके सुधारा जा सकता था। इस प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसे समझने के लिए उन विवादों पर नजर डालना जरूरी है, जहां वक़्फ बोर्ड के दावों के कारण गैर-मुस्लिमों को ऐसा लगा कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ समय पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के थिरुचेंथुरई गांव में एक बड़ा विवाद सामने आया था। वहां एक हिंदू व्यक्ति जब अपनी कृषि भूमि बेचने गया, तो उसे पता चला कि पूरे गांव की जमीन (जिसमें 1500 साल पुराना सुंदरेश्वरर मंदिर भी शामिल है) वक़्फ बोर्ड की है। ग्रामीणों का तर्क था कि उनके पास सदियों पुराने दस्तावेज हैं, लेकिन वक़्फ के एकतरफा दावे के कारण वे अपनी ही जमीन बेचने या ट्रांसफर करने में लाचार हो गए। ऐसे मामलों ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक डर और असंतोष का माहौल पैदा किया।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में ऐसी शिकायतें आम रही हैं, जहां प्राचीन टीलों, सार्वजनिक पार्कों या ग्राम समाज की जमीनों पर रातों-रात मजारें खड़ी हो गईं और बाद में उन्हें वक़्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करा लिया गया। जब स्थानीय हिंदू आबादी या पंचायत ने इस पर आपत्ति जताई, तो बोर्ड के स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों को भी वक़्फ एक्ट की पेचीदगियों के कारण कार्रवाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ताजमहल से लेकर कई राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों (जो मूल रूप से प्राचीन हिंदू स्थापत्य काल से जुड़ी मानी जाती हैं या एएसआई के अधीन हैं) पर भी समय-समय पर वक़्फ बोर्ड द्वारा मालिकाना हक या नमाज पढ़ने के अधिकार के दावे किए जाते रहे हैं। इन विवादों में मध्यस्थता या निष्पक्ष समीक्षा के लिए बोर्ड के भीतर किसी भी गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व का न होना हमेशा खटकता रहा है।
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक सुधार और सामाजिक संतुलन की दृष्टि से एक बड़ा प्रयोग है। बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों के आने से कम से कम उन मामलों में पारदर्शिता आएगी, जहां हिंदू संपत्तियों या विवादित स्थलों का मामला फंसा हुआ है। यह बोर्ड को अधिक जवाबदेह बनाएगा और एकतरफा फैसलों के आरोपों से बचाएगा। उधर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम समुदाय के भीतर फैले अविश्वास को दूर करना होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सदस्यों की भूमिका वक़्फ के धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों में दखल देने की न होकर केवल प्रशासनिक, वित्तीय पारदर्शिता और भूमि विवादों के निष्पक्ष निपटारे तक सीमित रहे। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में संस्थाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जो समाज के सभी वर्गों में विश्वास पैदा कर सके।
यदि यह निर्णय केवल राजनीति से ऊपर उठकर जमीनी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का जरिया बनता है, तो इसे भविष्य में एक सकारात्मक सुधार के रूप में याद किया जाएगा। वैसे कुछ लोग वक़्फ बोर्ड की तुलना राम मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि वक़्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, या फिर वे जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं।

संजय सक्सेना, लखनऊ

अखिलेश से नाराज साइलेंट मुस्लिम वोटर बड़ा खतरा

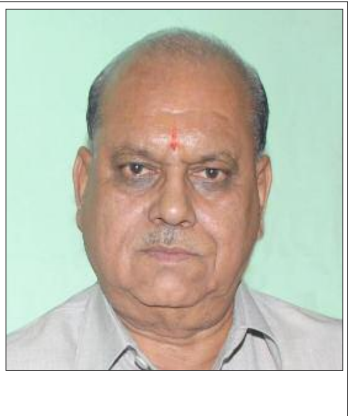

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बेहद खामोश लेकिन गहरा वैचारिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी धुरी समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के इर्द-गिर्द घूम रही है। पारंपरिक रूप से 'एम-वाई' (मुस्लिम-यादव) समीकरण के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुँचने वाली समाजवादी पार्टी की हालिया रणनीतियों को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच यह सवाल तैर रहा है कि क्या अखिलेश यादव को हिंदू वोटरों की नाराजगी का डर सताने लगा है? यह सवाल बेवजह नहीं है। पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का रुख उन मुद्दों पर बेहद नपा-तुला और रक्षात्मक रहा है, जो कभी उनके मुख्य वोट बैंक यानी मुस्लिम समुदाय से सीधे जुड़े माने जाते थे। मुस्लिम समाज के कई कार्यक्रमों से दूरी बनाना, संवेदनशील सांप्रदायिक या समुदाय-विशेष के मुद्दों पर तीखे बयानों के बजाय चुप्पी साध लेना या बेहद सामान्य प्रतिक्रिया देना, इस बात का साफ संकेत है कि पार्टी अपनी पुरानी 'मुस्लिम तुष्टिकरण' वाली छवि से पीछा छुड़ाना चाहती है। अखिलेश यादव भली-भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में अगर बहुसंख्यक हिंदू समाज में यह संदेश गया कि सपा केवल एक खास वर्ग की राजनीति करती है, तो वोटों का भारी नुकसान तय है। 2014 के बाद से देश और प्रदेश की राजनीति में जो 'कम्युनल कंसोलिडेशन' यानी बहुसंख्यक वोटों का एकतरफा झुकाव भाजपा की तरफ हुआ है, उसने विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। इसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव अब अपनी छवि को सॉफ्ट हिंदुत्व और सर्वसमावेशी 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के लिफाफे में लपेटकर पेश कर रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक (मुस्लिम) सिर्फ एक हिस्सा हैं, न कि पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु।

इस रणनीतिक बदलाव का सीधा असर मुस्लिम समुदाय के भीतर महसूस किया जा रहा है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और आम वोटरों का एक बड़ा धड़ा अब खुलकर यह कहने लगा है कि समाजवादी पार्टी संकट के समय उनके साथ खड़ी नहीं दिखती। चाहे वह दंगों या विवादों के बाद की कानूनी कार्रवाइयां हों या फिर समुदाय से जुड़े अन्य भावनात्मक मुद्दे, अखिलेश यादव की सधी हुई चुप्पी ने इस पारंपरिक वोट बैंक के भीतर एक असुरक्षा और उपेक्षा का भाव भर दिया है। इसी खालीपन का फायदा उठाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार सक्रिय हैं। ओवैसी जनसभाओं में बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब वह समय चला गया, जब 'अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे और अब्दुल्ला दरी बिछाएगा'। ओवैसी का यह तंज सीधे तौर पर मुस्लिम समाज की उस राजनीतिक चेतना को झकझोरता है, जो खुद को सिर्फ एक 'वोट बैंक' के रूप में इस्तेमाल होते देखकर थक चुकी है। ओवैसी की यह दलील मुस्लिम युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो अब केवल भाजपा को हराने के नाम पर सपा को एकतरफा वोट देने की मजबूरी से बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि, ओवैसी पर अक्सर भाजपा की 'बी-टीम' होने का आरोप लगता है और उनका वोट बैंक सीमित है, लेकिन यदि वह मुस्लिम वोटों में पांच से दस प्रतिशत की भी सेंधमारी करने में कामयाब रहे, तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी।

राजनीति की इस बिसात पर केवल ओवैसी ही अखिलेश यादव की मुश्किलें नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि पर्दे के पीछे एक और बड़ा बदलाव आकार ले रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक ऐसा धड़ा भी सामने आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की विकासवादी नीतियों से प्रभावित नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जैसे- मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुँचा है। इस 'लाभार्थी वर्ग' के भीतर एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण जन्म ले रहा है। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने से मुस्लिम महिलाओं और गरीब तबके में एक सुरक्षा और संतुष्टि का भाव आया है। भले ही यह वोटर सार्वजनिक रूप से या सामाजिक दबाव के कारण भाजपा का झंडा लेकर मैदान में न उतरे, लेकिन वोटिंग के दिन ईवीएम का बटन दबाते समय यह वर्ग 'साइलेंट वोटिंग' के जरिये भाजपा के पक्ष में खड़ा हो सकता है। यह सच है कि भाजपा के कोर एजेंडे और उसकी विचारधारा के कारण मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे दूरी बनाए रखता है, लेकिन लाभार्थियों का यह नया साइलेंट ग्रुप अगर दो से चार प्रतिशत भी भाजपा की तरफ शिफ्ट होता है, तो वह सपा के पारंपरिक गणित को पूरी तरह बिगाड़ सकता है।

अखिलेश यादव की इस नई रणनीति को राजनीतिक विश्लेषक एक सोची-समझी मजबूरी मानते हैं। अखिलेश जानते हैं कि केवल मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई जा सकती। उन्हें गैर-यादव ओबीसी और सवर्णों के एक हिस्से का समर्थन हर हाल में चाहिए। यही कारण है कि वह खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सभी वर्गों की बात करता है। वह मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, हिंदू त्योहारों की शुभकामनाएं प्रमुखता से देते हैं, लेकिन साथ ही मुस्लिम मंचों पर जाने से कतराते हैं, ताकि बहुसंख्यक समाज में कोई गलत संदेश न जाए। लेकिन इस 'संतुलन बनाने की कला' में वह एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। यदि मुस्लिम वोटरों को यह यकीन हो गया कि समाजवादी पार्टी उन्हें केवल टेकन फॉर ग्रांटेड (यानी सुरक्षित मानकर उपेक्षित) ले रही है, तो वे अन्य विकल्पों की तलाश तेज कर देंगे। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होना और बसपा का अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ना भी मुस्लिम वोटों के बिखराव का कारण बन सकता है। ऐसे में, यदि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का बिखराव ओवैसी, कांग्रेस और भाजपा के साइलेंट वोटर्स के रूप में हो गया, तो समाजवादी पार्टी को भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और अखिलेश यादव की 'हिंदू नाराजगी से बचने' की यह कवायद उनके अपने ही सबसे मजबूत किले को ढहाने का कारण बन सकती है।

समुद्र पर बनेगा भारत का पहला हवाई अड्डा

भारत की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार उसकी आधुनिक अवसंरचना है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने सड़क, रेल, बंदरगाह, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार देखा है। अब इसी श्रृंखला में एक और ऐतिहासिक पहल जुड़ने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के निकट पालघर जिले के कोरे बीच के पास भारत का पहला ऑफशोर अर्थात समुद्र आधारित हवाई अड्डा विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यदि यह परियोजना निर्धारित योजना के अनुसार साकार होती है तो यह केवल एक नया एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि भारत की विमानन क्षमता, समुद्री इंजीनियरिंग, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास का नया प्रतीक बनेगा। यह परियोजना देश को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर सकती है जिन्होंने समुद्र से भूमि तैयार कर विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण किया है।

ऑफशोर एयरपोर्ट का विचार अपने आप में अत्यंत आधुनिक और दूरदर्शी है। सामान्यतः हवाई अड्डे विशाल भूमि पर बनाए जाते हैं, लेकिन महानगरों में भूमि की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। बढ़ती आबादी, तेजी से फैलते शहर और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सामाजिक तथा कानूनी चुनौतियां नई परियोजनाओं को कठिन बना देती हैं। ऐसे में समुद्र के भीतर कृत्रिम भूमि तैयार कर उस पर एयरपोर्ट का निर्माण एक व्यावहारिक विकल्प बनकर उभरा है। जापान का कंसाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस अवधारणा के सफल उदाहरण हैं। भारत में भी अब इसी दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। अरब सागर में पुनः प्राप्त भूमि पर बनने वाला यह एयरपोर्ट भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता की नई पहचान बनेगा।

प्रस्तावित एयरपोर्ट की क्षमता इसे विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों की श्रेणी में ला सकती है। योजना के अनुसार यहां प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ यात्रियों के आवागमन और लगभग 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो की आवाजाही की व्यवस्था होगी। दो समानांतर रनवे विकसित किए जाने की भी योजना है, जिससे बड़ी संख्या में विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। यह क्षमता केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की मांग को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जा रही है।

मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। यहां

स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के बावजूद भविष्य में यात्रियों और माल परिवहन की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रस्तावित ऑफशोर एयरपोर्ट इस चुनौती का दीर्घकालिक समाधान बन सकता है। इससे न केवल मुंबई क्षेत्र के हवाई यातायात का दबाव कम होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और माल परिवहन के लिए भी नई संभावनाएं खुलेंगी।

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका बहुआयामी संपर्क तंत्र है। प्रस्तावित एयरपोर्ट को वधावन बंदरगाह, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे तथा प्रस्तावित उत्तन विरार सी लिंक से जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त समर्पित माल गलियारे और अन्य सड़क संपर्क भी विकसित किए जाएंगे। इससे हवाई, समुद्री, रेल और सड़क परिवहन का ऐसा समन्वित नेटवर्क तैयार होगा जो भारत में मल्टीमॉडल परिवहन का उत्कृष्ट उदाहरण बन सकता है। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और माल परिवहन की लागत तथा समय दोनों में कमी आएगी।

वधावन बंदरगाह स्वयं भारत की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री परियोजनाओं में गिना जा रहा है। यदि उसके साथ विशाल कार्गो क्षमता वाला एयरपोर्ट भी विकसित हो जाता है तो पश्चिमी भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नया केंद्र उभर सकता है। समुद्री मार्ग से आने वाला माल कम समय में हवाई मार्ग से देश और विदेश भेजा जा सकेगा। इसी प्रकार हवाई मार्ग से आने वाला उच्च मूल्य का सामान सीधे बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे निर्यात और आयात दोनों क्षेत्रों को गति मिलेगी तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका और मजबूत होगी।

पालघर जिला लंबे समय तक मुंबई महानगर क्षेत्र के बाहरी हिस्से के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी हैं, फिर भी इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। ऑफशोर एयरपोर्ट बनने के बाद इस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क, होटल, पर्यटन, आवासीय परियोजनाएं और सेवा क्षेत्र तेजी से विकसित हो सकते हैं। हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। स्थानीय युवाओं को निर्माण, विमानन, आतिथ्य, सुरक्षा, परिवहन और तकनीकी सेवाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन भी कम हो सकता है।

इतनी विशाल परियोजना के साथ कई तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। समुद्र से भूमि तैयार करना अत्यंत जटिल इंजीनियरिंग कार्य है। समुद्री धाराओं, ज्वार भाटा, तटीय पारिस्थितिकी, समुद्री जीवों, मछुआरा समुदाय और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक पहलुओं का गहन अध्ययन आवश्यक होगा। इसलिए सरकार ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें तकनीकी, वित्तीय और पर्यावरणीय पहलुओं का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी बड़े विकास कार्य में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। यदि इन पहलुओं की अनदेखी की गई तो दीर्घकाल में परियोजना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक दृष्टि से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से इस्पात, सीमेंट, मशीनरी, इंजीनियरिंग, परिवहन और निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना पूर्ण होने के बाद विमानन, पर्यटन, व्यापार, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और निर्यात आधारित उद्योगों में नई ऊर्जा आएगी। विदेशी निवेशकों के लिए भी यह क्षेत्र अधिक आकर्षक बन सकता है क्योंकि आधुनिक परिवहन अवसंरचना निवेश का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। इससे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे पश्चिमी भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।

भारत ने पिछले दशक में विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। छोटे शहरों तक हवाई सेवाएं पहुंचाने की योजनाओं से लेकर नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण तक अनेक प्रयास किए गए हैं। आज भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है। ऐसे समय में ऑफशोर एयरपोर्ट जैसी परियोजना यह संकेत देती है कि देश केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक योजना बना रहा है। यह दृष्टिकोण विकसित भारत की अवधारणा के अनुरूप भी है।

विश्व स्तर पर देखा जाए तो ऑफशोर एयरपोर्ट केवल परिवहन सुविधा नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता और राष्ट्रीय क्षमता का प्रतीक भी होते हैं। ऐसे प्रकल्पों के लिए उच्च स्तरीय समुद्री इंजीनियरिंग, उन्नत निर्माण तकनीक, पर्यावरणीय संतुलन तथा दीर्घकालिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। भारत यदि इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो वह वैश्विक स्तर पर अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का नया परिचय देगा। इससे भविष्य में अन्य तटीय क्षेत्रों में भी ऐसी परियोजनाओं की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

हालांकि परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योजना निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक सभी चरणों में पारदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। स्थानीय समुदायों की चिंताओं को समझना, पर्यावरणीय प्रभावों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और समयबद्ध निर्माण करना उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना स्वयं एयरपोर्ट का निर्माण। यदि इन सभी पहलुओं पर संतुलित ढंग से कार्य किया गया तो यह परियोजना केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए विकास का नया मॉडल बन सकती है।

भारत आज उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां अवसंरचना केवल सुविधाओं का विस्तार नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का आधार बन चुकी है। पालघर के समुद्र में प्रस्तावित यह ऑफशोर एयरपोर्ट उसी बदलते भारत की कहानी कहता है जो सीमित संसाधनों में भी नए समाधान खोजने का साहस रखता है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में पश्चिमी भारत के आर्थिक भूगोल को बदल सकती है, लाखों लोगों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है और भारत को वैश्विक विमानन तथा लॉजिस्टिक्स मानचित्र पर और अधिक प्रभावशाली स्थान दिला सकती है। यदि यह सपना साकार होता है तो यह केवल समुद्र पर बना एक हवाई अड्डा नहीं होगा, बल्कि भविष्य के भारत की दूरदृष्टि, तकनीकी क्षमता और विकास के संकल्प का जीवंत प्रतीक बनकर उभरेगा।

महेन्द्र तिवारी

हाथों में किताबें, राह में दलदल...!

हाथों में किताबें, आँखों में उजियारा,
पर राह में फैला कीचड़ इतना सारा।

नन्हें-नन्हें कदमों का यह कैसा सफर,
हर मोड़ पे है ठहरा विकास बेअसर।

कंधों पे बस्ता, मन में दौड़ते अरमान,
फिर भी 'मुश्किलों' से होती पहचान।

जहाँ सड़क होनी थी, वहाँ दलदल है,
बचपन का हर कदम आज घायल है।

कहते हैं शिक्षा से बदलता रहा हैं देश,
फिर क्यों बच्चों को मिले संघर्ष शेष?

क्या यही 'तरक्की', क्या यही विकास,
जब राह बन जाए प्रतिदिन का त्रास?

आओ मिल के हम ऐसी तस्वीर बदलें,
हर गाँव की राहों को पक्की सड़क दें।

शिक्षा बने सचमुच सभी का अधिकार,
ताकि हरेक बच्चे के सपने हों साकार।

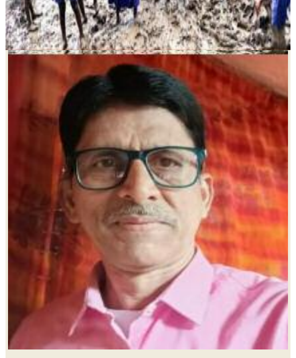

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)
मो. 98260 25986

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक रमन कुमार झा द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस बी-42 सेक्टर 07 नोएडा से मुद्रित कराकर नियर दुर्गा पब्लिक स्कूल श्याम लाल कॉलोनी बरौला सेक्टर 49 नोएडा 201304, गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।
संपर्क 9891706853, संपादक- रमन कुमार झा, समस्त विवादों का निपटारा गौतमबुद्धनगर न्यायालय मे होगा। Website: https://samajjagran.in/ Email: vatankiawaz@gmail.com UPHIN/2021/84200

टीसीएस के सहयोग से युवाओं के लिए विशेष प्लेसमेंट ड्राइव होगी, रोजगार सृजन को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर

जिला सेवायोजन कार्यालय की कार्यशाला में उद्योगों और शिक्षण संस्थानों ने साझा किए रोजगार के नए अवसर

नोएडा समाज जागरण ब्यूरोः जिला सेवायोजन कार्यालय, गौतमबुद्धनगर एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को जीएनआईओटी, ग्रेटर नोएडा में एक दिवसीय कौशल एवं रोजगार उन्मुख कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास, रोजगार के बदलते स्वरूप तथा रोजगार के नए अवसरों की जानकारी देना था।

कार्यक्रम में दिल्ली टेक्निकल कैंपस, मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राम-ईश इंस्टीट्यूट, एक्यूरेट इंस्टीट्यूट, आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, द्रोणाचार्य ग्रुप, जीएल बजाज, एनआईईटी, लॉयड ग्रुप सहित जनपद के कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न एमएसएमई इकाइयों, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए), इंडियन बिजनेस एसोसिएशन (आईबीए) तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों

ने भी सहभागिता कर उद्योगों में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता पर अपने विचार रखे।

जिला सेवायोजन अधिकारी मनीषा अत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी महीनों में टीसीएस के सहयोग से स्नातक एवं गैर-तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए विशेष कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल एवं टीसीएस आयन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

कार्यशाला के दौरान विभिन्न उद्योगों ने कुशल कर्मचारियों की कमी की समस्या उठाई। इस पर जिला सेवायोजन कार्यालय ने उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।

इसी अवसर पर जिला सेवायोजन कार्यालय एवं आर्या फैशन के बीच रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षण संस्थानों, उद्योग संगठनों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने का संकल्प लिया गया।

बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, सभी विभागों को समय रहते तैयारियां पूरी करने के निर्देश

एडीएम ने अधिकारियों से मांगी 14 जुलाई तक सत्यापित रिपोर्ट, यमुना-हिंडन के संभावित प्रभावित क्षेत्रों की हुई समीक्षा

समाज जागरण

नोएडा : अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जूम ऐप के माध्यम से बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की भौगोलिक स्थिति, यमुना एवं हिंडन नदी से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों तथा राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

सिंचाई विभाग ने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने पर जेवर एवं दादरी तहसील के कई गांव प्रभावित हो सकते हैं। वहीं हिंडन नदी में जलस्तर बढ़ने और यमुना में अधिक पानी आने की स्थिति में बैक वाटरिंग के कारण आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की आशंका रहती है। इसे देखते हुए सभी विभागों को समन्वित कार्ययोजना तैयार रखने के निर्देश दिए गए।

एडीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों की बाढ़ चौकियों, बाढ़शालाओं एवं प्रमुख नालों का भौतिक निरीक्षण करने तथा संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। प्राधिकरणों को नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की जांच तथा लो-लाइन क्षेत्रों एवं रिवर बेल्ट में संभावित अवैध निर्माण के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग को रैपिड रिस्पांस टीम, मेडिकल टीम, एंबुलेंस एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की गौशालाओं का चिन्हीकरण कर पशुओं के लिए पर्याप्त चारे एवं वैकल्पिक ठहराव की व्यवस्था करने को कहा गया। वहीं विद्युत विभाग को टूटे विद्युत पोल, लटके तार एवं अन्य संभावित खतरों को तत्काल दुरुस्त करने तथा बाढ़ चौकियों पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अपर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी कर 14 जुलाई 2026 तक सत्यापित रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाए रखें और कंट्रोल रूम सक्रिय रखें, ताकि जनपद में बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

सोरखा के कैफे और रेस्टोरेंटों में आबकारी विभाग की छापेमारी

विशेष अभियान के दौरान कहीं नहीं मिली अवैध शराब

समाज जागरण : संदीप गर्ग

नोएडा। अवैध शराब की बिक्री एवं परोसने पर रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने सेक्टर-115 स्थित सोरखा क्षेत्र के कई कैफे एवं रेस्टोरेंटों में विशेष जांच अभियान चलाया। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी टीम ने फुरसत के पल, रसोइया, पफ एंड स्पाई सहित अन्य कैफे एवं रेस्टोरेंटों की सघन जांच की। जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान से अवैध शराब बरामद नहीं हुई।

आबकारी विभाग ने बताया कि जनपद में होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं अन्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनपदभर में शराब की दुकानों और बारों पर आबकारी विभाग की सघन चेकिंग

सीसीटीवी, पीओएस मशीन और टेस्ट परचेज की जांच, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

समाज जागरण संवाददाता : संदीप गर्ग

नोएडा। जनपद गौतमबुद्धनगर में अवैध शराब की बिक्री एवं आबकारी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान देशी शराब की दुकानों, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल शॉप एवं बारों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त के निर्देश तथा जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में 9 जुलाई को जनपद के आबकारी निरीक्षकों एवं संबंधित थाना पुलिस ने विभिन्न मदिरा दुकानों और बारों की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान दुकानों के काउंटर पर ब्रांडवार शराब का नियमानुसार प्रदर्शन सुनिश्चित कराया गया। साथ ही कैंटीनों की सघन चेकिंग की गई तथा दुकानों पर गोपनीय टेस्ट परचेज कर बिक्री व्यवस्था का परीक्षण किया गया। आबकारी टीम ने सभी अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं को निर्देश दिए कि दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे रियल टाइम संचालित रहें तथा पीओएस मशीन के माध्यम से शत-प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने की भी हिदायत दी।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं आबकारी नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों एवं अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यीडा का अलीगढ़ में बड़ा एक्शन, 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

मरोरगढ़ी समेत कई गांवों में डेढ़ लाख वर्गमीटर भूमि से हटाया अतिक्रमण, ध्वस्तीकरण अभियान जारी

समाज जागरण : संदीप गर्ग

नोएडा/अलीगढ़। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने जनपद अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। अभियान के दौरान ग्राम मरोरगढ़ी सहित आसपास के गांवों में विकसित अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर करीब डेढ़ लाख वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

प्राधिकरण के अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हरित वाटिका मरोरगढ़ी सहित अन्य अवैध कॉलोनियों में की गई। मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 450 करोड़ रुपये बताया गया है। यह कार्रवाई यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी का विकास अथवा अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

यह अभियान यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया। कार्रवाई का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी (आईएएस) शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया। अभियान में उप जिलाधिकारी अभिषेक शाही, तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अधिकारी तथा अलीगढ़ पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम मौजूद रही।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा, ताकि नियोजित विकास कार्यों को बाधारहित गति मिल सके और सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से सुरक्षित रखा जा सके।

दनकौर में अवैध शराब बेचते युवक को दबोचा, 29 पव्वे देशी शराब बरामद

आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

समाज जागरण : संदीप गर्ग

नोएडा। जनपद गौतमबुद्धनगर में अवैध मदिरा की बिक्री एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग और थाना दनकौर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है।

उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त के निर्देश तथा जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत 9 जुलाई को दनकौर क्षेत्र में विशेष चेकिंग की गई। अभियान के दौरान मनीष पुत्र रामकिशन को अवैध रूप से देशी शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया

गया। आबकारी विभाग ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 'मिस इंडिया' ब्रांड की उत्तर प्रदेश मार्का 29 पव्वे (200 एमएल प्रति पव्वा) देशी मसाला शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कुल मात्रा 5.80 बल्क लीटर है।

संयुक्त टीम ने आरोपी के खिलाफ थाना दनकौर में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में अवैध शराब की बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जनपद में अवैध मदिरा के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

दादरी में अवैध शराब बेचते युवक को पकड़ा, 45 पव्वे देशी शराब बरामद

आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

समाज जागरण : संदीप गर्ग

नोएडा। जनपद गौतमबुद्धनगर में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग और थाना दादरी पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है।

उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त के निर्देश तथा जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत 9 जुलाई को दादरी क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान

हरीश पुत्र पतराम को अवैध रूप से देशी शराब बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

संयुक्त टीम ने आरोपी के कब्जे से इंडियन टाइगर ब्रांड की उत्तर प्रदेश मार्का 45 पव्वे (200 एमएल प्रति पव्वा) देशी मसाला शराब बरामद की। बरामद शराब की कुल मात्रा 9.00 बल्क लीटर है।

आबकारी विभाग ने आरोपी के विरुद्ध थाना दादरी में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जनपद में अवैध मदिरा के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का मुख्य आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा

एक लाख रुपये का इनामी अपराधी लखनऊ से गिरफ्तार, हत्या से पहले की थी विस्तृत रेकी

समाज जागरण संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में वांछित एक लाख रुपये के इनामी आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है।

एसटीएफ के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का पुरस्कार घोषित था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अभियुक्तों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश पहले से ही रच रखी थी।

जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने घटना को अंजाम देने से पहले पीड़ित के घर, कार्यालय, आने-जाने के मार्ग तथा उसके वाहनों की कई दिनों तक विस्तृत रेकी की थी। पहचान छिपाने के उद्देश्य से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की विशेष रूप से व्यवस्था की गई और उसकी नंबर प्लेट भी हटा दी गई थी।

एसटीएफ के अनुसार 27 मई 2026 को आरोपियों ने उपयुक्त अवसर मिलने पर मोटरसाइकिल से पीड़ित का पीछा किया। इसके बाद शूटर ने नजदीक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

एसटीएफ ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

'नो पावर कट जोन' में बिजली संकट पर एनसीएफ का सवाल, मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन

अघोषित कटौती, जर्जर विद्युत व्यवस्था और जलभराव से प्रभावित बिजली आपूर्ति पर जताई चिंता

समाज जागरण संवाददाता : संदीप गर्ग

नोएडा। उत्तर प्रदेश की 'शो विंडो' और 'नो पावर कट जोन' कहे जाने वाले नोएडा में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और जर्जर विद्युत व्यवस्था को लेकर सामाजिक संस्था नोएडा सिटीजन फोरम (एनसीएफ) ने बिजली विभाग के समक्ष गंभीर चिंता व्यक्त की है। एनसीएफ की कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी सिंह ने यूपीपीसीएल/पीवीवीएनएल के मुख्य अभियंता संजय कुमार जैन से औपचारिक बैठक कर शहर की विद्युत समस्याओं से संबंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि नोएडा के विभिन्न सेक्टरों, औद्योगिक क्षेत्रों, आवासीय सोसायटियों और ग्रामीण इलाकों में लगातार अघोषित बिजली कटौती, बार-बार फॉल्ट, जर्जर एवं नीचे लटकते बिजली के तार, खुले ट्रांसफॉर्मर, करंट उतरते बिजली के पोल तथा रात्रिकालीन फॉल्ट के समय अधिकारियों की अनुपलब्धता आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

एनसीएफ ने डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। शालिनी सिंह ने कहा कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार, बुजुर्ग और बच्चे निवास करते हैं, लेकिन उन्हें आज भी नियमित बिजली जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इन बस्तियों को वर्षों तक बसने दिया गया, तो अब इन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना उचित नहीं है।

बैठक के दौरान मुख्य अभियंता संजय कुमार जैन ने बताया कि हाल की भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर और विद्युत उपकेंद्र जलभराव से प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा जांच पूरी किए बिना बिजली आपूर्ति बहाल करना दुर्घटना का कारण बन सकता है। उन्होंने बताया कि जलभराव की स्थायी समस्या के समाधान के लिए नोएडा प्राधिकरण को भी पत्र भेजा गया है।

मुख्य अभियंता ने एनसीएफ की सभी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और नागरिकों से विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 9193301659 का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।

एनसीएफ ने नोएडा के लिए दीर्घकालिक विद्युत मास्टर प्लान तैयार करने, नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने, जर्जर लाइनों को बदलने, खुले ट्रांसफॉर्मरों को सुरक्षित करने, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, रात्रिकालीन आपातकालीन व्यवस्था मजबूत करने तथा अवैध बिजली कनेक्शन और बिजली माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा प्रत्येक विद्युत उपकेंद्र पर 24 घंटे वरिष्ठ अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई।

शालिनी सिंह ने कहा कि करोड़ों रुपये का राजस्व देने वाला नोएडा आज बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया तो नोएडा सिटीजन फोरम जनहित में आगे की रणनीति तय करेगा।

सेक्टर-73 में बेसमेंट खुदाई के दौरान धंसी सड़क और नाला, नोएडा प्राधिकरण ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

भारी बारिश के चलते हुआ हादसा, आवंटी अपने खर्च पर करा रहा पुनर्निर्माण

समाज जागरण : संदीप गर्ग

नोएडा। सेक्टर-73 स्थित व्यावसायिक भूखंड संख्या सी-01 पर निर्माण कार्य के दौरान बेसमेंट की खुदाई के समय हुई भारी बारिश के कारण सर्विस रोड और उससे सटे नाले का एक हिस्सा धंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही नोएडा प्राधिकरण ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित आवंटी एम/एस एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

नोएडा प्राधिकरण के अनुसार यह व्यावसायिक भूखंड 5,315.275 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है, जिसका आवंटन 22 नवंबर 2022 को किया गया था। भूखंड की लीज डीड 17 मार्च 2023 को निष्पादित हुई, जबकि भवन मानचित्र को 26 नवंबर 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पांच वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

प्राधिकरण ने बताया कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान लगातार हुई अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी खिसकने से भूखंड से सटी सर्विस रोड एवं नाले का हिस्सा धंस गया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद आवंटी ने अपने खर्च पर क्षतिग्रस्त सड़क और नाले के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि मरम्मत कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी एवं इंजीनियरिंग टीम लगातार मौके पर मौजूद रहकर पुनर्निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की निगरानी कर रहे हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

अपने व्यापार का करें प्रचार प्रसार
दैनिक समाज जागरण मे खबर और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करे।
न्यूज पोर्टल पर चलवाये मात्र 200 रुपये रोज मे।

ग्राम धुरैटा में 12 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण शिविर का शुभारंभ, संस्कृत के प्रचार-प्रसार की अनूठी पहल

समाज जागरण

संभल। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ द्वारा संचालित "गृहे-गृहे संस्कृतं" योजना के अंतर्गत जनपद सम्भल के ग्राम धुरैटा में दिव्यलोक गार्डन में आज 10 जुलाई से 12 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण शिविर का शुभारंभ बड़े उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में हुआ। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन एवं जन-जन तक उसके प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर सराहनीय प्रयास कर रही है। "गृहे-गृहे संस्कृतं" योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य संस्कृत को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर दैनिक जीवन की व्यवहारिक भाषा बनाना है।

शिविर का प्रशिक्षण संस्कृत प्रशिक्षिका उर्वशी आर्य द्वारा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को सरल एवं सहज तरीके से संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा। इस शिविर में किसी भी आयु वर्ग के महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चे भाग ले सकते हैं। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है तथा आगामी 12 दिनों तक नियमित रूप से संचालित किया जाएगा।

संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक परंपरा की आधारशिला है। विश्व की अनेक भाषाओं की जननी कही जाने वाली संस्कृत अपने वैज्ञानिक स्वरूप, शुद्ध उच्चारण और समृद्ध साहित्य के कारण आज भी पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। आधुनिक वैज्ञानिक भी संस्कृत की संरचना को अत्यंत तार्किक और कंप्यूटर-अनुकूल भाषा मानते हैं।

ऐसे संस्कृत सम्भाषण शिविर समाज में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान, नैतिक मूल्यों के विकास तथा नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत से जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं। ग्राम धुरैटा में प्रारंभ हुआ यह शिविर निश्चित रूप से संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार तथा सांस्कृतिक जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी पहल सिद्ध होगा।

बारिश में विद्यालय की दीवार गिरी बड़ा हादसा टला

समाज जागरण मुस्कान खान

जनपद बिजनौर मंडावर तीन दिन से लगातार हो रही बारिश ने चारों तरफ बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है इसी बारिश में एक कम्पोजिट विद्यालय की बाउंड्री की दीवार भरभरा कर गिर गयी जिसमें एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। विकास क्षेत्र ब्लाक मोहम्मद पुर देवमल न्याय पंचायत जहानाबाद के गांव रामजीवाला गांव में कम्पोजिट विद्यालय है जिसमें 212 की संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं कल गुरुवार को किसी समय सुबह सवेरे विद्यालय की बाउंड्री की दीवार बारिश के चलते भरभरा कर गिर गयी जिसमें गनीमत रही कि विद्यालय समय पर दीवार गिर जाती और कोई बच्चा वहा खेलता हुआ होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था इससे पहले भी इसी विद्यालय की बाउंड्री की एक पच्चीस मीटर के करीब दीवार गिर चुकी है विद्यालय के चारों ओर भी जल भरा हुआ है जो विद्यालय के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक धर्मेन्द्र कुमार और सहायक अध्यापक पवन कुमार ने बताया कि बाउंड्री की दीवार गिरने की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। वही ग्राम प्रधान सतीश कुमार से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले जो विद्यालय बाउंड्री की दीवार गिरी थी उसकी सुचना सेक्रेट्री के माध्यम से बीडियो बिजनौर को दी थी लेकिन उन्होंने कह दिया था की जल्दी ही सही करा दी जायेगी कल सुबह जो और दीवार बारिश के चलते गिरी है इसकी सूचना भी कल बेसिक शिक्षा अधिकारी को जाकर

बरसात के चलते मालन नदी के रपटे पर आया पानी, यातायात पूरी तरह बंद

समाज जागरण मुस्कान खान

जनपद बिजनौर मंडावर। पहाड़ी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से शुक्रवार सुबह मालन नदी के रपटे (पुल) पर तेजी से पानी आ गया जिससे यातायात पूरी तरह से बद हो गया।

पानी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि नवीन रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में भी पानी घुस गया। स्थिति को देखते हुए मंडावर थाना प्रभारी विपिन कुमार अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने रपटे के दोनों ओर बैरियर लगाकर यातायात को बंद कर दिया।

मालन नदी के रपटे पर पानी तेजी से बह रहा है पुल पार करना खतरनाक हो गया है।

आसपास के इलाकों में पानी भराव की आशंका बनी हुई है। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया, पुलिस द्वारा दोनों तरफ से आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से नदी क्षेत्र की ओर न जाएं। बारिश जारी रहने की संभावना को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मंडावर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया, पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत रास्ता बंद कर दिया गया है। पानी कम होने के बाद ही यातायात बहाल किया जाएगा। बारिश रुकने के बाद स्थिति का जायजा लिया जाएगा। फिलहाल नागरिकों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और नदी किनारे से दूर रहें।

जिन्हें कब्रिस्तान प्यारा, वे ही कर रहे राम मंदिर का विरोध: मुख्यमंत्री

- सीएम योगी ने बांदा व बबेरू विधानसभा क्षेत्र के लिए 710 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास

- मुख्यमंत्री की जनता से अपील- नकारात्मक व विकास विरोधी सोच वालों को खारिज कीजिए

- सीएम योगी ने 9 साल पहले के बुंदेलखंड की दुर्दशा और अब आए परिवर्तन का भी किया जिक्र

- बांदा के विधायक विकास में रुचि लेते हैं और बबेरू वाले गरीबों को प्रताड़ित करने मेः सीएम योगी

समाज जागरण

बांदा, 9 जुलाईः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फिर निशाने पर रखते हुए इन सरकारों के कार्यों का अंतर बताया। इशारों-इशारों में उन्होंने कहा कि कुछ लोग विरासत को अपमानित करते हैं। उन्होंने हिंदू परंपरा व सनातन को कोसना जीवन का ध्येय बनाया है। वे वैभवशाली व विकसित भारत नहीं देखना चाहते। हमारी सरकार जो पैसा मंदिरों के विकास व धामों के सुंदरीकरण के लिए देती है, समाजवादी पार्टी के समय यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल के लिए जाता था। उन्हें कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मां विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट, नैमिषारण्य धाम के विकास का विरोध करते हैं। सपा व कांग्रेस वाले भाजपा के प्रतिनिधियों द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों को पचा नहीं पाते। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की कि जिनकी सोच नकारात्मक व विकास विरोधी है, उन्हें खारिज कीजिए।

सीएम योगी ने गुरुवार को बांदा व बबेरू विधानसभा क्षेत्र के लिए 710 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण /शिलान्यास किया। सीएम ने लोकार्पण व शिलान्यास की गईं कई योजनाओं को गिनाकर इसका श्रेय जनता व जनप्रतिनिधियों को दिया।

कभी डकैतों व माफिया का था आतंक, आज प्रगति देखकर होती है प्रसन्नता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड की दुर्दशा के दौर को भी बयां किया। बताया कि सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि पहला दौरा बुंदेलखंड का हो और वहां के लिए कुछ किया जाए। नौ- साढ़े 9 साल पहले जब आया तो देखा कि पिछड़ापन यहां का पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। खनन, लैंड, सैंड, वन, भूमाफिया व डकैतों का ऐसा आतंक था, जिससे किसान भी खेत में जाने से डरता था। पाठा का यह क्षेत्र डकैतों के लिए फिरौती व वसूली का माध्यम बन गया था। कनेक्टिविटी, सिंचाई, पेयजल, सुरक्षा, रोजगार नहीं था। थाने में एफआईआर तक नहीं होती थी। बुंदेलखंड अस्तित्व के लिए जूझ रहा था परंतु अब बुंदेलखंड की प्रगति को देखकर अंतःकरण से प्रसन्नता होती है। हर किसी को 9 वर्ष पहले और आज के बांदा में परिवर्तन दिखेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि विकास व विरासत के संरक्षण के लिए शासन के संज्ञान में जो भी प्रोजेक्ट आएगा, उसे लागू कर बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाएंगे।

भाजपा सरकार ने हर वर्ग के सपनों को किया साकार

सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली तो आशा की किरण जगी। 2017 में यूपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद यहां भी कनेक्टिविटी, पेयजल, हर खेत को पानी और बांदा के युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने सभी के सपनों को साकार किया है।

वर्ष 2017 के पहले जिसे रखवाली की जिम्मेदारी मिली, वही प्रदेश को लूटते थे

सीएम योगी ने कहा कि जनता ने श्रीप्रकाश द्विवेदी, रामकेश निषाद व ओममणि वर्मा जैसे अच्छे जनप्रतिनिधियों को जिताया है तो यहां विकास की परियोजनाएं आ रही हैं। बुंदेलखंड भी डकैत, माफिया, कर्फ्यू, उपद्रव व दंगामुक्त हो गया। अब यहां महारानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधा मिल रही है।

असमोली विधायक पिंकी यादव किसानों की जमीन का 2016 वाला सर्किल रेट लगा रहा प्रशासन, 3 गुना बढ़ाने की मांग

समाज जागरण पबांसा

असमोली विधानसभा क्षेत्र की विधायक पिंकी सिंह यादव ने जनपद संभल में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर सर्किल रेट बढ़ाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि किसान की 8 साल पुराने रेट पर मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे किसान भूमिहीन होने के कगार पर हैं।विधायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जनपद संभल की तहसील संभल सहित कई गांवों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। जमीनों का बाजार मूल्य लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प समर्पित मूल्यांकन नियमावली 1997 के नियम 4 के अनुसार सर्किल रेट में प्रतिवर्ष वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन अभी भी वर्ष 2016 के सर्किल रेट के आधार पर ही किसानों को मुआवजा दे रहा है।

पिंकी यादव ने कहा कि जनपद में अधिकांश किसान छोटी जोत वाले हैं। इतना कम मुआवजा मिलने से कई परिवारों का जीवन संकट में आ जाएगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम कार्यालय और जिलाधिकारी संभल को टैग करते हुए मांग की है कि प्रभावित गांवों की जमीन का सर्किल रेट कम से कम 3 गुना बढ़ाकर नए रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सके।

गंगा एक्सप्रेसवे के समीप स्थित ग्रामों में ग्राम समाज एवं आरक्षित भूमि का होगा सत्यापन

समाज जागरण

बहजोई। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देशन में सत्यप्रिय सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), सम्भल की अध्यक्षता में गंगा एक्सप्रेसवे के समीप स्थित ग्रामों के सम्बन्धित राजस्व लेखपालों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) द्वारा जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के फलस्वरूप बढ़ रही औद्योगिक एवं विकासात्मक गतिविधियों के दृष्टिगत संबंधित ग्रामों में उपलब्ध ग्राम समाज एवं अन्य आरक्षित शासकीय भूमि की अद्यतन स्थिति का विस्तृत परीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी संबंधित राजस्व लेखपालों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामों में उपलब्ध ग्राम समाज एवं आरक्षित भूमि का मौके पर जाकर सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही वर्तमान खतौनी का आधार वर्ष की खतौनी से मिलान कर यह परीक्षण किया जाए कि शासकीय भूमि की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन तो नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की विसंगति अथवा अनियमितता परिलक्षित होती है तो उसका स्पष्ट विवरण सहित समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शासकीय भूमि का अभिलेखीय एवं स्थलीय सत्यापन पूर्ण गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ किया जाए, जिससे भविष्य में औद्योगिक, आधारभूत संरचना एवं अन्य जनहितकारी परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता का यथार्थ आकलन किया जा सके तथा शासकीय भूमि का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित हो।

पालतू कुत्ते को टहलाते समय किशोर को सांप ने डसा, समय पर उपचार से बची जान

समाज जागरण मुस्कान खान

जनपद बिजनौर नहटौर गांव जलालपुर तुर्क में पालतू कुत्ते को टहलाने निकले एक किशोर को सांप ने डस लिया। परिजनों की सतर्कता और चिकित्सकों द्वारा समय पर एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) दिए जाने से उसकी जान बच गई। प्राथमिक उपचार के बाद किशोर को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत में लगातार सुधार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गांव जलालपुर तुर्क निवासी 16 वर्षीय आर्यन बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे अपने पालतू कुत्ते को लेकर घर के पास टहल रहा था। अंधेरा होने के कारण उसका पैर अनजाने में एक सांप पर पड़ गया। इससे सांप ने उसके पैर में डस लिया। कुछ ही देर में आर्यन की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन बिना समय गंवाए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) लगाकर उपचार शुरू किया। हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. भानू प्रताप सिंह ने बताया कि सर्पदंश के मरीज के लिए समय पर अस्पताल पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आर्यन को तुरंत एंटी स्नेक वेनम देकर आवश्यक उपचार किया गया, जिससे उसकी स्थिति स्थिर हो गई। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है और वह स्वस्थ हो रहा है।

दहेज की मांग पर विवाहिता को मासूम बेटी समेत घर से निकाला, पांच पर मुकदमा

समाज जागरण ब्यूरो शमीम सिद्दीकी

जनपद बिजनौर नहटौर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को उसकी सात माह की मासूम बच्ची समेत घर से निकालने के मामले में पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के गांव धनुपुरा मच्छमार निवासी फिरदौस खातून ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उसका निकाह थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव ढकिया निवासी सुहेल से हुआ था। आरोप है कि निकाह के समय कार समेत पर्याप्त दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करता रहा। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई और सात माह की बच्ची सहित घर से निकाल दिया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने पति समेत पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेचना अधिकारी राकेश मोहन ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, बिजनौर में कक्षा-6 प्रवेश हेतु आवेदन 31 जुलाई तक

समाज जागरण ब्यूरो शमीम सिद्दीकी

जनपद बिजनौर प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, सैंद्वार (जनपद बिजनौर) में शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा-6 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है।

उन्होंने जनपद के सभी कक्षा-5 के पात्र एवं पंजीकृत विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है, ताकि कोई भी पात्र छात्र इस अवसर से वंचित न रहे।

उन्होंने बताया कि चयन परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अधिसूचना का भली-भांति अध्ययन कर लें।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 मई, 2015 से 31 जुलाई, 2017 (दोनों तिथियाँ सम्मिलित) के मध्य होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी एवं अभिभावक मोबाइल नंबर 9412957628, 9758865451 एवं 9452243717 पर संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय प्रशासन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन करना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

योगी सरकार में समस्याओं का त्वरित समाधान, 89.41 लाख रुपये के जीपीएफ का कराया भुगतान

-सीएम योगी की पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था का दिखा असर

-"संध्या संवाद" में मंडलायुक्त के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं तेजी से पूरी कराकर दिलाया भुगतान

समाज जागरण

लखनऊ, 9 जुलाईः योगी सरकार प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे आम नागरिकों के साथ-साथ कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों की समस्याओं का भी त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में देवीपाटन मंडल में मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने "संध्या संवाद" कार्यक्रम के जरिये लोगों की समस्याओं का समाधान कराया।

मुख्यमंत्री योगी की निदेर्शों के तहत शीघ्र की गई कार्यवाही

देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती में आयोजित संध्या संवाद कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आए, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ एवं अन्य सेवा संबंधी देयों का भुगतान कराया गया। इस पहल के तहत कुल 89 लाख 41 हजार 612 रुपये की जीपीएफ धनराशि संबंधित कर्मचारियों के खातों में पहुंचाई गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरे भुगतान मिलने के बाद खुशी से खिल उठे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं कि जनशिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न बनकर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किया जाए। उनकी प्राथमिकता है कि आम जनता से लेकर कर्मचारियों तक किसी भी व्यक्ति को अपने वैधानिक अधिकारों के लिए भटकना न पड़े। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मंडल में संध्या संवाद कार्यक्रम की शुरूआत की गई है, जिसके माध्यम से प्रशासन सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है।

कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सेवा संबंधी देयों का भुगतान कराया गया

"संध्या संवाद" कार्यक्रम में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शिकायत रखी कि उनका जीपीएफ तथा अन्य सेवा संबंधी भुगतान लंबित है। इस पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी श्रावस्ती अन्नपूर्णा गर्ग ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया। जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं तेजी से पूरी कराईं।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक

समाज जागरण

असमोली। मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को असमोली थाना पुलिस ने महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, कानून और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया।

थाना असमोली क्षेत्र के मील चौराहे पर उपनिरीक्षक विजेंद्र कुमार, महिला आरक्षी रीनू,महिला आरक्षी छवि तथा महिला आरक्षी आरती ने अभियान चलाकर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी दी। इस दौरान वूमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

पुलिस टीम ने महिलाओं को साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताते हुए किसी भी आपात स्थिति में बिना झिझक संबंधित हेल्पलाइन पर संपर्क करने और अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया।

हरेवली मार्ग के ऊपर से बह रहे पानी से नगीना हरेवली का सपर्क टूटा

समाज जागरण ब्यूरो शमीम सिद्दीकी

जनपद बिजनौर नगीना। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नदी वह पाधोई नदी का जल स्तर बढ़ने से हरेवली मार्ग के ऊपर से बह रहे पानी से नगीना हरेवली का सपर्क टूटा। खेत खलियान हुए जल मग्न, जमीन के कारोबारियो ने पाधोई के सामने दीवार निर्माण कराया।

पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही झमाझम वर्षा से क्षेत्र की खो नदी और पाधोई नदिया उफान पर है। नगीना से हरेवली मार्ग स्थित पाधोई की पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, वैसे तो यह बरसात के मोसम में यह समस्या खड़ी होती रही है, लेकिन इस बर यह समस्या कुछ बड़ी हो गई है जमीन का कारोबार करने वालों ने पाधोई पुलिया के पास जंगल में जमीन लेकर उस पर दीवार का निर्माण करा देने से पाधोई के पानी का बाहाव बाधित होने से जहां नगीना हरेवली मार्ग बाधित हो गया है। साथ ही दूर तक खेत खलियान पानी पानी हो गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की सभावनाएं है। और राहगीरों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहां तक की स्कूल छात्र/छात्राओं को मौत का सफर पानी मे चलकर स्कूल आना जाना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे कर किसी बड़ी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं।

दस लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार

समाज जागरण मुस्कान खान

जनपद बिजनौर नगीना। जनपद बिजनौर में नवागत जिला आबकारी अधिकारी आर बी सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत से आबकारी विभाग एक्शन मोड मे। लगातार अवैध शराब के तस्करों पर कसा जा रहा शिकंजा बताया जाता है हाल ही में आरबी सिंह द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत से जनपद बिजनौर में अबैध शराब तस्करों पर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी क्रम में आबकारी निरीक्षक देवेश कुमार सोती, क्षेत्र नगीना तहसील एवं कुसुमाकर, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र चांदपुर व पुलिस थाना बढ़ापुर की टीम द्वारा संयुक्त दबिश देकर गुरुवार को ग्राम टांडा साहूवाला थाना बढापुर मैं 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में थाना बढ़ापुर में अभियोग दर्ज कराया गया आबकारी विभाग की विगत दिनों से लगातार हो रही प्रभावी कार्रवाई शराब के तस्करों के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि समय रहते सुधर जाए वरना आबकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों को किसी भी दिशा में बक्शा नहीं जाएगा।

कारखाने में करंट लगने से मजदूर की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

समाज जागरण ब्यूरो शमीम सिद्दीकी

जनपद बिजनौर नहटौर-धामपुर मार्ग पर स्थित एक बूरा-बताशा बनाने की फैक्ट्री में शुक्रवार (आज) सुबह काम करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम फरीदनगर निवासी मनोज सैनी (पुत्र ओमप्रकाश) नहटौर नगर के धामपुर मार्ग पर स्थित बूरा-बताशा बनाने के कारखाने में काम करता था। शुक्रवार (आज) प्रातः जब वह कारखाने में काम कर रहा था, तभी अचानक वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब कारखाने के अन्य कारीगर वहां काम करने पहुंचे। मनोज को मृत अवस्था में पड़ा देख कारीगरों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कारखाना मालिक, पुलिस और मृतक के परिजनों को दी। मजदूर की मौत की खबर मिलते ही रोते-बिलखते परिजन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गए।

शिव सैनिकों ने किया नवागंतुक थाना प्रभारी अफजलगढ का अभिनन्दन

समाज जागरण ब्यूरो शमीम सिद्दीकी

जनपद बिजनौर अफजलगढ शिव सेना यूबीटी के मण्डल प्रमुख आर.के.सिंह आर्य एवं जिला प्रमुख चौ.संजय राणा के नेतृत्व में कोतवाली अफजलगढ के नवागंतुक प्रभारी निरीक्षक मृदुल सिंह को कोतवाली अफजलगढ का कार्यभार

संभालने पर श्रीराम दरबार का प्रतिरूप भेंटकर अभिनन्दन किया। शिव सेना जिला प्रमुख चौ.संजय राणा ने नवागंतुक थाना प्रभारी से अपेक्षा की कि वह राम राज्य की परिकल्पना के अनुरूप पीड़ित को यथोचित न्याय दिलाने एवं अपराधी प्रवृति एवं अनैतिक कार्य में संलिप्त दोषी अपराधियों को विधि सम्मत दण्ड दिलाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान शिवसेना मण्डल प्रमुख आर.के. आर्य, जिला प्रमुख चौ.संजय राणा, हरपाल सिंह राणा , सरदार कुलदीप सिंह, महेन्द्र सिंह सिरोही, सुरेन्द्र सिंह आदि शिव सैनिक मौजूद रहे।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए संजय राणा होंगे कम्मू राष्ट्र गौरव सम्मान - 2026 से सम्मानित

समाज जागरण बागपत/बडौत। जनपद बागपत के प्रख्यात पर्यावरणविद् एवं एनवायरनमेंट एंड सोशल रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन (एस्रो) के निदेशक संजय राणा का चयन राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित "कम्मू राष्ट्र गौरव सम्मान-2026" के लिए किया गया है। चयन समिति द्वारा जारी अंतिम सूची में उनका नाम पर्यावरण श्रेणी में शामिल किया गया है। यह सम्मान 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमलादेवी जनसेवा संस्थान (पंजीकृत), सीकर (राजस्थान) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदान किया जाएगा। संजय राणा विगत लगभग दो दशकों से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन एवं युवा जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। वर्ष 2013 में स्थापित एन वायरनमेंट एंड सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ESRO) के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों विद्यालयों,

महाविद्यालयों और ग्रामीण समुदायों में पर्यावरण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े अनेक नवाचार पूर्ण कार्यक्रम संचालित किए हैं। उनके नेतृत्व में हजारों युवाओं को प्रकृति संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के प्रति प्रेरित किया गया है। संजय राणा इससे पूर्व भी पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। उनका मानना है कि "प्रकृति से मानव है, न कि मानव से प्रकृति", और इसी विचार को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वे निरंतर कार्य कर रहे हैं। सम्मान के लिए चयनित होने पर संजय राणा ने चयन समिति एवं कमलादेवी जनसेवा संस्थान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि उन सभी सहयोगियों, स्वयंसेवकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और नागरिकों का सम्मान है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता के इस अभियान को जनआंदोलन बनाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और अधिक ऊर्जा एवं समर्पण के साथ समाज और प्रकृति की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा।

24 घंटे के अंदर रुड़की से बरामद हुआ 8 वर्षीय रिहान, पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर गांव ने किया सम्मान

सरूरपुर कला चौकी इंचार्ज कुलजीत सिंह और टीम को ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने फूलमाला, शाल और मिठाई से किया सम्मानित

समाज जागरण

बागपत। सरूरपुर कला पुलिस की त्वरित कार्रवाई से खेड़की गांव से लापता हुआ 8 वर्षीय बालक रिहान सकुशल घर लौट आया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही बच्चे को उत्तराखंड के रुड़की से बरामद कर परिवार को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार 8 जुलाई को खेड़की गांव निवासी दिल पुकार का 8 वर्षीय बेटा रिहान अचानक घर से लापता हो गया था। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज कुलजीत सिंह और सरूरपुर कला चौकी की पूरी टीम ने तत्काल तलाश शुरू की। पुलिस के अथक प्रयासों से रिहान को रुड़की से बरामद कर लिया गया और परिजनों

को सौंप दिया गया। बालक के सकुशल मिलने पर ग्राम प्रधान आशीष शर्मा, गांव के सम्मानित लोग और रिहान के परिजनों ने चौकी इंचार्ज कुलजीत सिंह व उनकी टीम का सम्मान किया। इस दौरान उन्हें फूलमाला, शाल और मिठाई भेंटकर आभार व्यक्त किया गया।

ग्रामवासियों ने पुलिस प्रशासन की इस तत्परता और संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद किया।

बड़ौत में वंदे मातरम चौक के नामकरण की मांग, नगर पालिका अध्यक्ष ने दिया आश्वासन

विश्व हिंदू महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने पालिका अध्यक्ष अश्विनी तोमर से की शिष्टाचार भेंट

समाज जागरण

बड़ौत। विश्व हिंदू महासंघ, उत्तर प्रदेश, जनपद बागपत के पदाधिकारियों ने बड़ौत नगर पालिका अध्यक्ष श्री अश्विनी तोमर से शिष्टाचार भेंट कर "वंदे मातरम चौक" के नामकरण की मांग की। जिला अध्यक्ष कृष्णपाल शर्मा और जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने नगर पालिका अध्यक्ष से अनुरोध किया कि इस मांग को शीघ्र स्वीकृति प्रदान

की जाए। इस पर अश्विनी तोमर ने आश्वासन दिया कि आगामी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। प्रस्ताव पारित होने पर "वंदे मातरम चौक" के नामकरण की घोषणा कर दी जाएगी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र बाजवा, नगर अध्यक्ष रवि कश्यप, जिला उपाध्यक्ष कैलाश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष मनोज कटारिया, नगर उपाध्यक्ष नवीन कश्यप सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि "वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव और भारतीय अस्मिता का प्रतीक है। इस चौक का नामकरण जनपद बागपत के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण निर्णय सिद्ध होगा।

नई बस्ती कूड़े के ढेर पर , दुर्गंध से बेहाल लोग

मुख्य मार्ग पर फैला कचरा बना मुसीबत, मोहल्लेवासियों ने कूड़ाघर हटाने की उठाई मांग

समाज जागरण

बड़ौत। स्वच्छता के दावों की हकीकत नई बस्ती के मुख्य मार्ग पर साफ दिखाई दे रही है। आबादी के बीच बने कूड़ाघर से बाहर तक फैला कचरे का विशाल ढेर न केवल प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजाना परेशानी का कारण भी बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को नाक पर रुमाल रखकर इस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। नई बस्ती के मुख्य मार्ग पर स्थित कूड़ाघर में आसपास के कई मोहल्लों का कचरा डाला जाता है। समय पर उठान न होने के कारण कूड़ा सड़क तक फैल जाता है, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है और आवागमन बाधित होता है। सड़ते कचरे से उठने वाली दुर्गंध और गंदगी के कारण स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। मोहल्लेवासी अतुल शर्मा, वीरेंद्र वैद्य, पिंटू गुप्ता, अजीत, संजय शर्मा, महेंद्र उपाध्याय, विनोद उपाध्याय, संजय गुप्ता, दिनेश जैन, सुनील पांचाल

और रामवीर पांचाल ने बताया कि इस समस्या की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि कूड़ाघर से बाहर फैला कचरा बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले में जब किसी परिवार में शादी या अन्य मांगलिक कार्यक्रम होता है, तब सड़क पर फैला कचरा और दुर्गंध मेहमानों के सामने शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। लोगों का कहना है कि स्वच्छ शहर का दावा करने वाला प्रशासन इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा। मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि आबादी के बीच स्थित इस कूड़ाघर को तत्काल किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए तथा नियमित रूप से कचरे का उठान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को गंदगी, दुर्गंध और संक्रमण के खतरे से राहत मिल सके।

डाक बंगले में लगे बाबा काले सिंह और वीरांगना किशनदेई की प्रतिमा: सुभाष शर्मा ने सरकार से की मांग

ब्राह्मण समाज 84 देश खाप के चौधरी ने कहा- 1857 की क्रांति के नायकों को मिले सम्मान, शहादत दिवस मनाता है क्षेत्र

समाज जागरण बड़ौत। बड़ौत शहर के जाने-माने समाजसेवी एवं ब्राह्मण समाज 84 देश खाप के चौधरी पंडित सुभाष शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि महान क्रांतिकारी बाबा पं. काले सिंह और वीरांगना दादी किशनदेई की प्रतिमा बड़ौत के डाक बंगले में स्थापित की जाए। पंडित सुभाष शर्मा ने कहा कि हमारे पूर्वज बाबा काले सिंह भारतीय क्रांतिकारी सेना के मुखिया थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाइयां लड़ीं और 10 अप्रैल 1858 को बड़का गांव, बागपत में वीरगति को प्राप्त हुए। इतिहास इस बात का गवाह है। इसके बाद उनकी पत्नी दादी किशनदेई ने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व संभाला। उन्होंने

अंग्रेजी सेना से मोर्चा लिया, कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया और अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए मजदूरों व क्रांतिकारियों को कारागार से मुक्त कराया। इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने वीरांगना किशनदेई को पकड़ लिया और 12 जुलाई 1858 को बड़ौत के डाक बंगले में पत्थर के कोल्हू में पिलवा दिया। साथ ही क्रांतिकारियों और मजदूरों के घरों में आग लगा दी गई। सुभाष शर्मा ने बताया कि क्षेत्रवासियों को उनकी शहादत पर गर्व है। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बड़ौत की कुछ सरकारी संस्थाओं को हमारे पूर्वजों द्वारा जमीन भी दान में दी गई थी, जिसके साक्ष्य अभिलेखों में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बाबा काले सिंह और दादी किशनदेई की बड़ौत में प्रतिमा लगाई जाए। क्षेत्रवासी उनका शहादत दिवस और जन्मदिवस भी मनाते हैं।

30 जुलाई से शुरू होगा सावन, पुरा महादेव मंदिर पर 9 से 12 अगस्त तक लगेगा कावड़ मेला

इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे, लाखों शिवभक्त करेंगे जलाभिषेक; प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

समाज जागरण बड़ौत।

पुरा महादेव मंदिर परिसर के पुजारी अक्षय भारद्वाज ने बताया कि इस वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश व उत्तरी भारत में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा।उन्होंने बताया कि इस बार सावन माह में कुल चार सोमवार पड़ेंगे, जिनकी शुरूआत 3 अगस्त

से होगी। सावन के दौरान भगवान परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर पर लाखों की संख्या में शिवभक्त पहुंचकर भगवान आशुतोष के शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाले कावड़िए मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का गुणगान करते हुए अपनी मन्नतें मांगेंगे।पुजारी ने बताया कि पुरा महादेव मंदिर पर 9 अगस्त से 12 अगस्त तक सावन माह का कावड़ मेला आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन का जमावड़ा भी मंदिर परिसर में लगना शुरू हो गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों कावड़िए पुरा महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे।

रटौल आम महोत्सव में थाईलैंड की राजदूत समेत सैकड़ों मेहमानों ने उठाया लुफ्त

150 किस्मों के आमों की प्रदर्शनी, डीएम बोलीं- रटौल आम विश्व प्रसिद्ध, सरकार देगी बागानों को बढ़ावा

समाज जागरण

चांदीनगर। नगर पंचायत रटौल और जिला प्रशासन बागपत के सौजन्य से निगार फार्म हाऊस में आयोजित आम महोत्सव में देश-विदेश से आए मेहमानों ने जमकर रटौल आम का स्वाद लिया। महोत्सव में भारत में थाईलैंड की राजदूत सुश्री चवानर्ट थांग सुम्फान ने शिरकत की। जिलाधिकारी अस्मिता लाल और विधायक योगेश धामा का नगर पंचायत अध्यक्ष हाजी मुंतजिर और ईओ आस्था पाठक ने फूल देकर स्वागत किया। महोत्सव में आम उत्पादक हबीब खान, निसार, जावेद, इमरान सहित 20 किसानों ने रटौल, लंगड़ा, चौसा, फजरी, हाथीझूल, मकसूद, हुस्न आरा सहित 150 वैरायटी के आमों की प्रदर्शनी लगाई। डीएम और थाईलैंड की राजदूत ने प्रत्येक किस्म की जानकारी ली और रटौल आम की जमकर सराहना की। सैय्यद फहाद ने राजदूत को रटौल आम की विशेषताओं से अवगत कराया। खरीदारी के लिए खादी ग्रामोद्योग,

अचार और सराय के स्टाल भी लगाए गए। महोत्सव को यादगार बनाने के लिए बागपत के प्रसिद्ध घेवर, बालूशाही, आम पन्ना और देशी पान भी परोसे गए। सलमा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और सेल्फी पॉइंट पर लोगों ने खूब फोटो खिंचवाईं। प्रेस वार्ता में डीएम अस्मिता लाल ने कहा कि रटौल आम विश्व प्रसिद्ध है। सरकार आम उत्पादकों को समय-समय पर योजनाओं का लाभ दे रही है। घटते आम बागानों के क्षेत्रफल पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि बागानों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। थाईलैंड की राजदूत ने भी रटौल आम की तारीफ की। विधायक योगेश धामा ने महोत्सव को सफल बनाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष की सराहना की।इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री कुलदीप उज्जवल, गन्ना समिति चेयरमैन कृष्णपाल, सुधीर चौधरी, जिला उद्यान अधिकारी निधि, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुब्बसिर चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन-2026 को संबोधित किया

इस सम्मेलन से समग्र सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण को संस्थागत रूप मिला है आने वाले समय में तटीय सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में भी हम समग्रता से आगे बढ़ेंगे

इस सम्मेलन में सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा, निराकरण की चिंता और इस दिशा में उपयुक्त उपायों को नीतिगत स्वरूप देने का काम होगा

मोदी सरकार, संबद्ध सीमा रक्षक बल, राज्य एवं ज़िला प्रशासन, भारत सरकार के संबंधित हितधारक तथा स्थानीय नागरिकों के परस्पर जुड़ाव के साथ एक मजबूत चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण कर रही है

स्मार्ट बॉर्डर की कल्पना पर आधारित भारत की बॉर्डर सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में विश्व में सबसे आधुनिक होगी सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत और सजग समाज के साथ ही देश सुरक्षित हो सकता है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को जम्मू कश्मीर और नॉर्थईस्ट में आतंकवाद

और नक्सलवाद से निजात मिली है जो हमारी साझी सफलता का सूचक है आने वाले 3 सालों में हम नारकोटिक्स की समस्या को गंभीर क्षति पहुंचाकर इस पर विजय प्राप्त करेंगे देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और घुसपैठ हो ही न सके, इसके लिए एक मजबूत तंत्र का निर्माण कर रहे हैं पहले समस्याएं स्थायी और समाधान अस्थायी थे, मोदी सरकार में समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर समाधानों को स्थायी बनाया जा रहा है मोदी सरकार ने बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर में 400 प्रतिशत वृद्धि कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसे आगे बढ़ाया है मोदी जी ने वायब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत देश के अंतिम गांव को देश का प्रथम गांव कहा है, इसके तहत पलायन रोकने, रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है मोदी जी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करने, उसमें असामान्य कारणों से हो रही वृद्धि को चिन्हित करने और भविष्य में इसे रोकने के उपाय सुझाने के लिए डेमोग्राफी मिशन की शुरूआत की है रूथलैस अप्रोच के साथ जनसांख्यिकी में असामान्य कारणों से हो रही वृद्धि को रोकना मोदी सरकार का संकल्प है सीमांत क्षेत्रों में हो रहे जनसंख्यिकी परिवर्तन का मूल कारण घुसपैठ है

सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए मोदी सरकार ने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण किया है जिससे हमने अपनी अप्रोच को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में बदला है मोदी सरकार आइसोलेटेड सीमा चौकी की व्यवस्था से एकीकृत सुरक्षा ग्रिड का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है

गृह मंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में असामान्य कारणों से जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव की सूचना जल्द से जल्द नीचे से उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के महत्व पर बल दिया

मोदी सरकार 31 हजार करोड़ से 1610 किलोमीटर लंबे म्यांमार बॉर्डर पर बाड़बंदी कर रही है

प्रॉक्सी वार, घुसपैठ, कट्टरपंथ का प्रसार, नारकोटिक्स, तस्करी, ड्रोन, साइबर अपराध, संगठित अपराध और जनसांख्यिकीय परिवर्तन रोकना, सीमा को रहने लायक बनाना और वहां से पलायन रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे उद्देश्य हैं केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन-2026 को संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री बंडी संजय कुमार, केन्द्रीय गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो और सीमांत राज्यों के पुलिस महानिदेशकों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस सम्मेलन से समग्र सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण को संस्थागत रूप मिला है और आने वाले समय में तटीय सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में भी हम समग्रता से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा, निराकरण की चिंता और इस दिशा में उपयुक्त उपायों को नीतिगत स्वरूप देने का काम होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर की कल्पना पर आधारित भारत की बॉर्डर सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में विश्व में सबसे आधुनिक होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, संबद्ध सीमा रक्षक बल, राज्य एवं ज़िला प्रशासन, भारत सरकार के संबंधित हितधारक तथा स्थानीय नागरिकों के परस्पर जुड़ाव के साथ एक मजबूत चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत और सजग समाज के साथ ही देश सुरक्षित हो सकता है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को जम्मू कश्मीर और नॉर्थईस्ट में आतंकवाद

और नक्सलवाद से निजात मिली है जो हमारी साझी सफलता का सूचक है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 सालों में हम नारकोटिक्स की समस्या को गंभीर क्षति पहुंचाकर इस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और घुसपैठ हो ही न सके, इसके लिए एक मजबूत तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि पहले समस्याएं स्थायी और समाधान अस्थायी थे, मोदी सरकार में समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर समाधानों को स्थायी बनाया जा रहा है। श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर में 400 प्रतिशत वृद्धि कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसे आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत देश के अंतिम गांव को देश का प्रथम गांव कहा है, इसके तहत पलायन रोकने, रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का शत

प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करने, उसमें असामान्य कारणों से हो रही वृद्धि को चिन्हित करने और भविष्य में इसे रोकने के उपाय सुझाने के लिए डेमोग्राफी मिशन की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि रूथलैस अप्रोच के साथ जनसांख्यिकी में असामान्य कारणों से हो रही वृद्धि को रोकना मोदी सरकार का संकल्प है। गृह मंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में हो रहे जनसंख्यिकी परिवर्तन का मूल कारण घुसपैठ है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए मोदी सरकार ने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण किया है जिससे हमने अपनी अप्रोच को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में बदला है। मोदी सरकार आइसोलेटेड सीमा चौकी की व्यवस्था से एकीकृत सुरक्षा ग्रिड का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में असामान्य कारणों से जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव की सूचना जल्द से जल्द नीचे से उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के महत्व पर बल दिया।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार 31 हजार करोड़ से 1610 किलोमीटर लंबे म्यांमार बॉर्डर पर बाड़बंदी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वार, घुसपैठ, कट्टरपंथ का प्रसार, नारकोटिक्स, तस्करी, ड्रोन, साइबर अपराध, संगठित अपराध और जनसांख्यिकीय परिवर्तन रोकना, सीमा को रहने लायक बनाना और वहां से पलायन रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे उद्देश्य हैं।

श्री भूपेंद्र यादव ने कोयंबटूर में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की

बैठक में भारत के बाघ क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने, प्रबंधन के तरीकों को बेहतर बनाने और संरक्षण पर चर्चा की गई

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 29वीं बैठक आज केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी (सीएएसएफओएस), कोयंबटूर, तमिलनाडु में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और एनटीसीए के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र यादव ने की। बैठक में संसद सदस्यों, श्री राजीव प्रताप रूडी और श्री हरीश चंद्र मीना, प्राधिकरण के अन्य सदस्यों के अलावा, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, बाघ वाले राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और बाघ अभयारण्यों के क्षेत्र निदेशक शामिल हुए। इस बैठक में देश में बाघों के संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन से जुड़े अहम नीतिगत, प्रबंधन और संस्थागत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। यह चर्चा मुख्य रूप से भारत के बाघ क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने, प्रबंधन के तौर-तरीकों में सुधार लाने और संरक्षण के परिणामों को बेहतर बनाने पर केंद्रित रही। प्राधिकरण ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और बाघों तथा उनके आवासों के संरक्षण को और मजबूत करने के उद्देश्य से लाए गए प्रस्तावों पर विचार किया।

बैठक के दौरान, मंत्री महोदय ने दो महत्वपूर्ण एनटीसीए प्रकाशन जारी किए: रोडमैप टू रेस्क्यू: बाघ परिदृश्यों में जंगली जानवरों के बचाव-पुनर्वास-मुक्ति के लिए अस्थायी/पारगमन सुविधाओं की स्थापना के लिए रणनीतिक रोडमैप: यह भारत के बाघ परिदृश्यों में वन्यजीवों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें सुरक्षित रूप से छोड़े जाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक वैज्ञानिक और रणनीतिक फ्रेमवर्क है। यह रोडमैप उभरती हुई संरक्षण चुनौतियों और मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने की तैयारियों को बेहतर बनाएगा; और,

'स्ट्राइड्स' 2026: स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व्स-इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजी एंड सोशल पैरामीटर्स: यह भारत के बाघ अभयारण्यों में किए गए संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों का एक व्यापक मूल्यांकन है। यह रिपोर्ट बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए साक्ष्य-आधारित योजना, अनुकूलनीय प्रबंधन और सोच-समझकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करेगी।

प्राधिकरण ने वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार किया और उसे मंजूरी दी, साथ ही एनटीसीए की 28वीं बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में प्राधिकरण की तकनीकी समिति और प्रशासनिक समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया गया। प्रमुख एजेंडा में, प्राधिकरण ने बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के छठे चक्र को शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। यह बाघ अभयारण्यों में प्रबंधन के तौर-तरीकों की प्रभावशीलता का आकलन करने और अनुकूलनीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बैठक में 'बाघ सम्मेलन' को एक राष्ट्रीय मंच के तौर पर आयोजित करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य कॉर्पोरेट संस्थाओं, परोपकारी संगठनों

और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर 'टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन' के माध्यम से बाघ अभयारण्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने 'स्ट्राइप्स' - (सिम्पोजियम ऑन टाइगर रिसर्च, इनोवेशन, पॉलिसी, इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी) के आयोजन पर भी विचार-विमर्श किया।

सीएक्यूएम ने निरीक्षण अभियान के दौरान ने पाया कि एमसीडी की 79 में से 78 सड़कें मानक ढांचे के अनुरूप हैं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में "ऑपरेशन क्लीन एयर" के अंतर्गत एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण किए गए 79 सड़क खंडों में से 78 में पूरी तरह से पक्की सड़क पाई गई जो आयोग द्वारा निर्धारित शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियाली के मानक ढांचे के अनुपालन को दर्शाती है। यह निरीक्षण 07.01 .2025 को जारी और जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्य सरकारों को अधिसूचित शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियाली के लिए मानक ढांचे के अनुसार किए गए सड़क पुनर्विकास कार्यों की स्थिति का आकलन करने के लिए किया गया था। आयोग ने इस अभियान के लिए 10 फ्लाइंग स्क्वाड को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सड़क खंडों का निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया था। इसमें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फैले लगभग 13 किलोमीटर के 79 सड़क खंडों को शामिल किया गया। इस निरीक्षण के दौरान 79 सड़क खंडों में से 78 पर पूर्ण रूप से पक्की सड़क बनी हुई थी। शेष एक सड़क खंड पर सड़क निर्माण और पुनर्विकास कार्य प्रगति पर था। इससे पहले 18.06.2026 को आयोग ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जीएनसीटीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लगभग 69 किलोमीटर के 48 सड़क खंडों का निरीक्षण करने के लिए नौ फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए थे। इसमें विभिन्न राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) श्रेणियों, अर्थात 10 मीटर से कम, 10-15 मीटर और 15 मीटर से अधिक की सड़कों को लक्षित किया गया था। निरीक्षण के दौरान लगभग 66 किलोमीटर लंबी 41 सड़क खंडों पर पक्की सड़क पाई गई। हालांकि सात सड़क खंडों पर पूरी तरह से पक्की सड़क नहीं थी जबकि नौ सड़क खंडों पर पक्के रास्ते या तो नहीं थे या बिल्कुल नहीं थे।

21 सड़क खंडों पर पक्की पट्टी नहीं थी। इससे निर्धारित ढांचे के अनुसार और सुधार की आवश्यकता स्पष्ट होती है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन विभाग (पीडब्ल्यूडी) से गलत रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है।

अपने व्यापार का करें प्रचार प्रसार
दैनिक समाज जागरण में खबर और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।
न्यूज पोर्टल पर चलवायें मात्र 200 रुपये रोज में।

पाँच प्रतिशत आबादी वाले भूखंडों की क्रमबद्ध नंबरिंग की जाए : अशोक चौहान

सेक्टर-130 के निवासियों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सेक्टर मानचित्र लगाने की मांग

समाज जागरण: संदीप गर्ग

नोएडा। सेक्टर-130 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के उपाध्यक्ष अशोक चौहान के नेतृत्व में शुक्रवार को पाँच प्रतिशत आबादी वाले भूखंडों के निवासियों ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, सेक्टर-96 में आयोजित जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सेक्टर-130 सहित सभी पाँच प्रतिशत आबादी वाले सेक्टरों में भूखंडों की अव्यवस्थित नंबरिंग को क्रमबद्ध करने तथा प्रत्येक मुख्य प्रवेश द्वार पर विस्तृत सेक्टर मानचित्र स्थापित करने की मांग की गई।

अशोक चौहान ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित पाँच प्रतिशत आबादी वाले सेक्टरों, विशेषकर सेक्टर-130 में भूखंडों की नंबरिंग अत्यंत अव्यवस्थित है। विभिन्न ग्रामों के भूखंडों को डब्ल्यूए, डब्ल्यूपी, एसपी, केयू, सीएम, एचएल, एसएच तथा एनएल जैसे संक्षिप्त संकेतों के आधार पर अंकित किया गया है। परिणामस्वरूप एक ही श्रेणी के भूखंड अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं और उनका कोई क्रमबद्ध अनुक्रम नहीं है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि डब्ल्यूपी-282 मुख्य मार्ग पर स्थित है, तो डब्ल्यूपी-285 सेक्टर के भीतर कई गलियों के बाद मिलता है। इस कारण नए आगंतुकों, परिजनों, डाक वितरकों, पार्सल वितरण कर्मियों, एम्बुलेंस, सेवा प्रदाताओं तथा अन्य नागरिकों को संबंधित पते तक पहुँचने में

अत्यधिक कठिनाई और समय की हानि का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने यह भी कहा कि सेक्टर-130 तीन अलग-अलग स्थानों पर विकसित है तथा इसे किसी खंड (ब्लॉक) में विभाजित भी नहीं किया गया है। यही समस्या सेक्टर-145 सहित अन्य पाँच प्रतिशत आबादी वाले सेक्टरों में भी देखने को मिलती है।

आरडब्ल्यूए ने मांग की कि सेक्टर-130 सहित सभी पाँच प्रतिशत आबादी वाले सेक्टरों के प्रत्येक मुख्य प्रवेश द्वार पर स्पष्ट एवं विस्तृत सेक्टर मानचित्र स्थापित किए जाएँ, जिससे कोई भी व्यक्ति प्रवेश करते ही संबंधित भूखंड की स्थिति आसानी से जान सके और बिना भटकाव के अपने गंतव्य तक पहुँच सके।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण के नियोजन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा भूखंडों की नंबरिंग व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध बनाया जाए।

इस अवसर पर धर्मपाल चौहान, सत्येंद्र गुर्जर सहित अनेक स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। निवासियों ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो हजारों लोगों को प्रतिदिन होने वाली अनावश्यक असुविधा से राहत मिलेगी और सेक्टरों में आवागमन अधिक सुगम होगा।

एक ही बारिश में डूबी राजधानी, जलभराव ने खोली व्यवस्थाओं की पोल

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, दो बच्चों की मौत, कई इलाकों में रेड अलर्ट जैसी स्थिति

समाज जागरण संवाददाता : बादल हुसैन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पिछले तीन दिनों से रुक-रुककर हो रही भारी वर्षा ने एक बार फिर जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। मानसून की तेज बारिश के बाद राजधानी के अनेक प्रमुख मार्ग, आवासीय क्षेत्र और निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़कों पर जलभराव, उखड़े पेड़ और कई स्थानों पर घंटों तक लगे यातायात जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इस दौरान दिल्ली में मानसून की अब तक की सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण राजधानी ही नहीं, बल्कि एनसीआर के कई हिस्सों में भी हालात बिगड़ गए। अधिकारियों ने पूरे दिन जल निकासी, यातायात बहाल करने और गिरे हुए पेड़ों को हटाने का कार्य जारी रखा। बारिश के दौरान हुए हादसों में गाजियाबाद में तीन वर्षीय बच्ची तथा दिल्ली में सात वर्षीय बालक की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। इन घटनाओं ने वर्षा के दौरान सुरक्षा और जलभराव की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है।

दिल्ली सरकार में मंत्री एवं सोनिया विहार क्षेत्र के भाजपा विधायक कपिल मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र में भी जलभराव की गंभीर स्थिति देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। पिछले वर्ष मानसून के दौरान क्षेत्र में नाले का निर्माण कर स्थायी समाधान का दावा किया गया था, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी हालात में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। पहली ही तेज बारिश में थाना परिसर, आसपास की सड़कें तथा कच्ची खजूरी का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। सड़क पार स्थित खजूरी खास के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घुटनों से लेकर कई स्थानों पर कमर तक भरे पानी से होकर विद्यालय पहुंचना पड़ा।

स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को भी भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था।

लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि देश की राजधानी में हर वर्ष मानसून के दौरान जलभराव की समस्या आखिर कब समाप्त होगी और करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नागरिकों को राहत कब मिलेगी।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिवस पर भाजपा ने किया हवन-पूजन

उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना, जिला कार्यालय में मिष्ठान्न वितरित

समाज जागरण : संदीप गर्ग

नोएडा। भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर द्वारा शुक्रवार को सेक्टर-116 स्थित जिला कार्यालय में भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर हवन-पूजन एवं मिष्ठान्न वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष महेश चौहान के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन में आहुति अर्पित कर रक्षामंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य, दीर्घायु तथा राष्ट्रसेवा के लिए निरंतर ऊर्जा एवं यशस्वी जीवन की कामना की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि राजनाथ सिंह का सार्वजनिक जीवन सादगी, ईमानदारी, राष्ट्रनिष्ठा एवं कुशल नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने संगठन और सरकार दोनों में अपने कार्यों से देशवासियों का विश्वास अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि रक्षामंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में भारत की सैन्य शक्ति निरंतर सुदृढ़ हुई है तथा देश की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विनोद त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रक्षामंत्री के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके मार्गदर्शन में

देश निरंतर विकास और आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।

कार्यक्रम में जिला महामंत्री अमित त्यागी एवं चंदगीराम यादव, ओमबीर अवाना, विनोद शर्मा, उमेश त्यागी, सुशील शर्मा, राजकुमार बंसल, पंकज झा, पुष्पा रावत, मीनाक्षी चौहान, हरिओम जाटव, बबलू यादव, राहुल शर्मा, रामकिशन यादव, शशिधर उपाध्याय, सत्यनारायण महतर, उमेश पहलवान, मुक्तानंद प्रधान, लोकेश यादव, इंदराज खटाना, अनुज शर्मा, दीपक शर्मा, संतोष सिंह, राजश्री गुप्ता, लालिमा मिश्रा, प्रमोद शर्मा, अनिमेष सिंह, पी.सी. पंचोली, जितेंद्र तोमर, देसराज सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सभी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

पत्रकारों को रेल यात्रा में नि:शुल्क अथवा रियायती सुविधा मिले : अश्वनी वालिया

ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से की मांग

समाज जागरण संवाददाता

कुरुक्षेत्र। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी वालिया एवं मुख्य प्रदेश संरक्षक दलबीर सिंह मलिक ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भारतीय रेल में निःशुल्क अथवा विशेष रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

संयुक्त बयान में दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज, सरकार और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। समाचार संकलन, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, चुनावों, सामाजिक गतिविधियों तथा सरकारी कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग के लिए उन्हें निरंतर विभिन्न स्थानों की यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में रेल यात्रा की विशेष सुविधा मिलने से वे अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि पत्रकार जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने,

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने तथा सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सरकार को पत्रकारों के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी यात्रा संबंधी सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए।

अश्वनी वालिया और दलबीर सिंह मलिक ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि मान्यता प्राप्त एवं पात्र पत्रकारों के लिए पारदर्शी व्यवस्था के तहत भारतीय रेल में निःशुल्क अथवा विशेष रियायती यात्रा सुविधा लागू की जाए। उनका कहना है कि इससे पत्रकारों को राहत मिलेगी और वे अधिक समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार पत्रकारों की इस मांग पर सकारात्मक विचार कर शीघ्र उचित निर्णय लेगी।

यीडा का अतिक्रमण पर बड़ा प्रहार, 250 करोड़ की सरकारी भूमि कराई कब्जामुक्त

चपरगढ़ में 50 हजार वर्गमीटर ग्रीन बेल्ट से हटाया अवैध कब्जा, आगे भी अभियान रहेगा जारी

समाज जागरण : संदीप गर्ग

नोएडा। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाते हुए ग्राम चपरगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 60 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर लगभग 50,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 250 करोड़ रुपये बताया गया है।

यह कार्रवाई यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर तथा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित भूमि यीडा की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। प्रवर्तन दल ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया और भूमि को पुनः प्राधिकरण के कब्जे में ले लिया।

प्राधिकरण ने बताया कि यह कार्रवाई अधिसूचित क्षेत्र में नियोजित विकास कार्यों को बाधारहित गति देने तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। अभियान

में उप जिलाधिकारी हरी प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी शिव अवतार सिंह, प्राधिकरण के परियोजना विभाग, भूलेख विभाग एवं प्रवर्तन दल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी एवं भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। प्रशासन के सहयोग से पूरा अभियान शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, अवैध निर्माण अथवा अवैध कॉलोनी का विकास किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में भविष्य में भी लगातार प्रवर्तन अभियान चलाकर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया टीएमयू के प्रो. एस.के. सिंह की पुस्तक का लोकार्पण

लखनऊ में आयोजित दीक्षांत समारोह में 'ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट' का हुआ विमोचन

समाज जागरण संवाददाता

मुरादाबाद/लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के 11वें दीक्षांत समारोह में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय (टीएमयू), मुरादाबाद के कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज के प्राचार्य प्रो. सुशील कुमार सिंह की संपादित पुस्तक 'ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट' का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने किया। समारोह में राज्यपाल ने एक दर्जन शैक्षणिक पुस्तकों का विमोचन किया, जिनमें प्रो. सिंह की पुस्तक भी शामिल रही।

यह पुस्तक पर्यावरण संरक्षण, मानव-पर्यावरण संबंधों तथा सतत विकास जैसे समकालीन विषयों पर केंद्रित है। पुस्तक की भूमिका असम के राज्यपाल के सलाहकार एवं टीएमयू के विधि संकाय के डीन प्रो. हरबंश दीक्षित ने लिखी है। पुस्तक के सह-संपादक डॉ. प्रशांत कुमार वरुण और सुश्री तान्या सागर हैं, जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अध्यापन कार्य से जुड़े हैं।

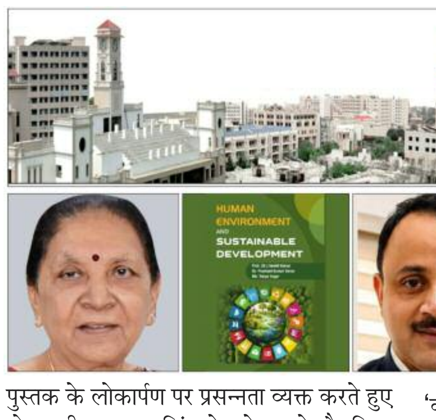

पुस्तक के लोकार्पण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रो. सुशील कुमार सिंह ने इसे अपने शैक्षणिक जीवन का गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों तथा नीति-निमार्ताओं के लिए उपयोगी संदर्भ ग्रंथ सिद्ध होगी। उन्होंने पुस्तक के निर्माण में सहयोग देने वाले प्रो. हरबंश दीक्षित, डॉ. प्रशांत कुमार वरुण और सुश्री तान्या सागर के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि 'ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट' प्रो. सुशील कुमार सिंह की नौवीं पुस्तक है। इससे पूर्व वे विधि एवं संवैधानिक विषयों पर 'लॉ एंड मीडिया', 'इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज', 'एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ', 'प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी', 'कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू सिविल प्रोसीजर कोड-1908', 'द डॉवरी पैराडॉक्स', 'मीडिया, प्राइवेसी एंड लॉ' तथा 'कॉन्टेम्पररी इश्यूज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स' सहित कई पुस्तकें लिख चुके हैं।

प्रो. सिंह के नाम चार पेटेंट तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20 से अधिक शोधपत्र भी दर्ज हैं। वर्तमान में वे टीएमयू के कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज के प्राचार्य होने के साथ-साथ विश्वविद्यालय के मुख्य अनुशासन अधिकारी (चीफ प्रॉक्टर) का दायित्व भी निभा रहे हैं।

अपने व्यापार का करें प्रचार प्रसार
दैनिक समाज जागरण में खबर और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।
न्यूज पोर्टल पर चलवायें मात्र 200 रुपये रोज में।

किसानों को घटिया उर्वरक व कीटनाशक देने वाली चीनी मिलों की जब्त हो सकती है बैंक गारंटी

गुणवत्ता को लेकर योगी सरकार सख्त, गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता

लखनऊ, 10 जुलाई। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा और खेती की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की सभी चीनी मिलें किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्ता परीक्षण से गुजरे उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं कीटनाशक ही उपलब्ध करा सकेंगी। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने इस संबंध में प्रदेश की सभी चीनी मिलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हर बैच की होगी एनबीएल लैब में जांच

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक बैच के कृषि निवेश की गुणवत्ता की जांच एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराना अनिवार्य होगा। केवल वही उत्पाद किसानों तक पहुंचेंगे जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, कीटनाशक अधिनियम 1968 व अन्य वैधानिक मानकों पर खरे उतरेंगे। इससे किसानों को नकली और घटिया कृषि उत्पादों से राहत मिलेगी।

प्रतिबंधित कीटनाशकों पर पूरी तरह रोक

निर्देश में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशकों का वितरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित कृषि निवेशों और फसल सुरक्षा उत्पादों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

गोरखपुर व कुशीनगर को 1283 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री

शनिवार को कुशीनगर में 525 करोड़ रुपये की 464 और गोरखपुर में 758 करोड़ रुपये की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे सीएम योगी

कुशीनगर में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यों से तीन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को होगा लाभ

गोरखपुर में सीएम योगी के हाथों जनता को समर्पित होगी करीब 690 करोड रुपए की लागत वाली भटहट-बांसस्थान फोरलेन सड़क

गोरखपुर/कुशीनगर, 10 जुलाई। शुक्रवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ शनिवार 11 जुलाई को गोरखपुर और कुशीनगर जिले को 1283 करोड रुपये की सौगात देंगे। वह कुशीनगर में 525 करोड़ रुपये की लागत वाली 464 और गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपये की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद पूर्वाह्न कुशीनगर जिले का दौरा करेंगे। वह टेकुआटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में तीन विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा और कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी 525 करोड़ रुपये की 464 परियोजनाओं का उपहार देंगे। लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के लिए दुल्हिन जगरनाथ कुंवरी इंटर कॉलेज परिसर में बने मंच से मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वह कार्यक्रम स्थल के पास विकास प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे।

शनिवार को ही दोपहर बाद सीएम योगी गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भटहट-बांसस्थान में फोरलेन सड़क सहित 758 करोड़ रुपये के 24 विकास कार्यों की सौगात देंगे।

वह भटहट-बासंस्थान फोरलेन सड़क समेत 697 करोड़ 49 हजार रुपये की लागत वाली 5 सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन से संबंधित 60 करोड़ 63 लाख 96 हजार रुपये की लागत वाले 19 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास के ये सभी कार्य पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आते हैं। मुख्यमंत्री जिन सड़कों का लोकार्पण करेंगे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भटहट-बांसस्थान फोरलेन मार्ग है। 11.6 किमी लंबे इस मार्ग के फोरलेन में चौड़ीकृत होने जाने से न केवल एक बड़ी आबादी के लिए आवागमन सुगमता बढ़ी है बल्कि इसका फायदा आयुष विश्वविद्यालय जाने वालों को भी मिल रहा है। फोरलेन कनेक्टिविटी हो जाने से प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय में आयुष पद्धतियों से इलाज कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।।शिलान्यास की परियोजनाएं सड़क और पर्यटन विकास पर केंद्रित हैं। आयुष विवि का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री

शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के पहले, महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। उनके द्वारा आयुष विश्वविद्यालय में पुरुष व महिला छात्रवास का लोकार्पण भी संभावित है। पुरुष छात्रावास का नामकरण ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की स्मृति में किया गया है, जबकि महिला छात्रावास का नाम राप्ती रखा गया है। उल्लेखनीय है कि आयुष विश्वविद्यालय, सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों और लोकार्पण 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कर कमलों से कराया था।

गोरखपुर में पौधरोपण महायज्ञ में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार 12 जुलाई को गोरखपुर में, प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ में सम्मिलित होंगे। वह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के किनारे 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधा लगाएंगे और जनसभा कर प्रदेशवासियों को पौधरोपण महायज्ञ में जिम्मेदारीपूर्वक हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। इस महाभियान के जरिये प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है।

सीमांचल में भूजल प्रदूषण की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।

सीमांचल क्षेत्र में भूजल में आर्सेनिक एवं यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्वों की मौजूदगी और कैंसर के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने जांच एवं समाधान के लिए विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप (विशेषज्ञ पैनल) गठित किया है। इसे किशनगंज के सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद द्वारा लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।

सांसद डॉ. जावेद आजाद ने संसद में प्रश्नकाल तथा नियम 377 के अंतर्गत इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके जवाब में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में सीमांचल क्षेत्र में मुंह, स्तन (ब्रेस्ट) और लिवर कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया था कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल सहित सीमांचल के कई जिलों के भूजल में आर्सेनिक एवं यूरेनियम की मौजूदगी चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस समस्या के कारणों की वैज्ञानिक जांच तथा स्थायी समाधान के लिए विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप गठित किया है।

अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 के बीच किए गए सर्वेक्षण में कैंसर के पुष्ट मामलों की संख्या इस प्रकार दर्ज की गई है– पूर्णिया में 323, कटिहार में 103, सुपौल में 75, अररिया में 74 तथा किशनगंज में 71 मामले सामने आए।

वहीं, जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 के बीच कैंसर मरीजों के उपचार के लिए राज्य सरकार ने पूर्णिया जिले के 2,407 मरीजों हेतु 16.27 करोड़ तथा किशनगंज जिले के 938 मरीजों हेतु 6.14 करोड़ की राशि स्वीकृत की।

सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर भी बढ़ी कार्रवाई

इधर, सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद द्वारा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण की मांग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र कुमार से इस संबंध में अनुरोध किया था।

पथ निर्माण मंत्री ने पत्र के माध्यम से सांसद को सूचित किया है कि उक्त प्रस्ताव को ग्रै० स० प्रे० सं०-998, दिनांक 10 जून 2026 के माध्यम से पथ निर्माण विभाग के सचिव के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

सांसद ने कहा कि सीमांचल के लोगों को सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत सड़क संपर्क उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट और सड़क निर्माण प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

टेऊसा में स्मैक का कथित संगठित नेटवर्क! नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो, किशनगंज।

किशनगंज जिले के टेऊसा पंचायत में स्मैक के कथित बढ़ते अवैध कारोबार ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों का कारोबार तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में सबसे अधिक युवा आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्मैक की लत के कारण कई परिवार आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट से जूझ रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार टेऊसा पंचायत स्थित नरसिंग डागा फार्म हाउस तथा उसके आसपास के इलाके में नशेड़ियों और कथित तस्करों का जमावड़ा लगा रहता है। उनका आरोप है कि खुलेआम नशा किए जाने से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि किशनगंज सीमावर्ती जिला होने के कारण बाहरी क्षेत्रों से नशीले पदार्थों की तस्करी की आशंका बनी रहती है। उनका आरोप है कि संगठित नेटवर्क के माध्यम से स्मैक की छोटी-छोटी पुड़ियाएं विभिन्न इलाकों तक पहुंचाई जा रही हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल छोटे स्तर के नशा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। उनका मानना है कि पुलिस और संबंधित एजेंसियों को तस्करी के पूरे नेटवर्क, सप्लायरों तथा वित्तीय स्रोतों तक पहुंचकर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि नशे की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।

युवा सबसे अधिक प्रभावित

ग्रामीणों के अनुसार बड़ी संख्या में युवा स्मैक की लत का शिकार हो चुके हैं। कुछ लोगों का दावा है कि

कई ई-रिक्शा (टोटो) चालक भी सार्वजनिक स्थानों पर नशा करते देखे जाते हैं। अभिभावकों का कहना है कि जिस उम्र में युवाओं को शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य के निर्माण में जुटना चाहिए, उसी उम्र में वे नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं।

महिलाओं और बच्चों में बढ़ी असुरक्षा

स्थानीय लोगों का कहना है कि नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों से महिलाओं और बच्चों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। सुबह और शाम कई स्थानों पर नशा करने वालों का जमावड़ा लगने से आम लोगों को आवागमन और दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विशेष अभियान चलाने की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, पुलिस तथा मादक पदार्थ नियंत्रण से जुड़े विभागों से क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने की मांग की है। उन्होंने कथित स्मैक सप्लायरों के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने, आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही नशे के संभावित अड्डों पर नियमित छापेमारी, सघन गश्त और निगरानी बढ़ाने की भी अपील की है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई तो नशे का यह कथित कारोबार आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि स्मैक केवल एक नशीला पदार्थ नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य, परिवारों की खुशियों और समाज की नींव को खोखला करने वाला घातक जहर बनता जा रहा है।

आरबीएसके व बाल हृदय योजना से दो बच्चों को मिली नई जिंदगी की उम्मीद

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) एवं बाल हृदय योजना के तहत किशनगंज जिले के जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित दो बच्चों को निःशुल्क ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अहमदाबाद रेफर किया गया है। गुरुवार को दोनों मरीजों को सदर अस्पताल से एम्बुलेंस द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना भेजा गया, जहां से उन्हें हवाई मार्ग से श्री सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल, अहमदाबाद ले जाया जाएगा।

रेफर किए गए मरीजों में किशनगंज प्रखंड के दिलवरगंज निवासी चंदन महतो की सात वर्षीय पुत्री आंचल कुमारी तथा ठाकुरगंज प्रखंड के जलमिलिक निवासी हबीबुर रहमान के 17 वर्षीय पुत्र सलमान रजा शामिल हैं। दोनों की विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में निःशुल्क ओपन हार्ट सर्जरी होगी।

सिविल सर्जन डॉ. राज कुमार चौधरी ने बताया कि आरबीएसके एवं बाल हृदय योजना के तहत बच्चों की पहचान, जांच, रेफरल, एम्बुलेंस, हवाई यात्रा, भर्ती, ऑपरेशन और उपचार की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा निःशुल्क की जाती है। जिले में स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से बच्चों की नियमित स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि जन्मजात बीमारियों की समय पर पहचान कर इलाज सुनिश्चित किया जा सके।

जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे के इलाज में बाधा नहीं बनने दी जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों में जन्मजात हृदय रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में जांच कराएं और आरबीएसके की निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठाएं।

कीचड़ में तब्दील सड़क बनी ग्रामीणों की परेशानी, स्कूली बच्चों का स्कूल जाना हुआ मुश्किल

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।

ठाकुरगंज।चुरली पंचायत के वार्ड-11 में बोर्डर सड़क से भैसलूटी जाने वाले मार्ग की बदहाल स्थिति पर ग्रामीणों में नाराजगी ठाकुरगंज (किशनगंज)। ठाकुरगंज प्रखंड की चुरली पंचायत के वार्ड संख्या-11 में बोर्डर सड़क से भैसलूटी जाने वाला संपर्क मार्ग इन दिनों पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गया है। सड़क की जर्जर स्थिति के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों को प्रतिदिन भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, सड़क पर जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए पूर्व में नाले की खुदाई कराई गई थी, लेकिन समय पर उसकी सफाई नहीं होने से उसमें मिट्टी और गाद भर गई। इसके चलते पानी की निकासी पूरी तरह बाधित हो गई और सड़क पर कीचड़ फैल गया, जिससे आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण समस्या लगातार बनी हुई है। उन्होंने संबंधित विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

स्कूल जाने वाले बच्चों ने बताया कि कीचड़ से भरे रास्ते पर चलते समय वे कई बार फिसलकर गिर जाते हैं। इससे उनकी किताबें और कॉपियां भीग जाती हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं और समय पर विद्यालय पहुंचना भी कठिन हो जाता है। वहीं, शिक्षकों सहित अन्य राहगीरों को भी प्रतिदिन इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अविलंब सड़क की मरम्मत कराई जाए, जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तथा नाले की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

दो गैरजमानतीय वारंटी को नबीनगर थाना पुलिस ने अलग-अलग जगहों से किया गिरफ्तार

समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)

नबीनगर (बिहार)नबीनगर थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय से निर्गत आजमानतीय वारंट के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि पुलिस टीम ने छापेमारी कर ग्राम-ईटवा से मिथिलेश सिंह एवं ग्राम देवराज बीघा से लल्लू सिंह थाना नबीनगर से दो आजमानतीय वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में लंबित वारंट के निष्पादन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

पटना के पालीगंज में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, गुस्साए परिजनों में मातम

समाज जागरण पटना जिला संवाददाताः– वेद प्रकाश

पटना/ जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रामपुर नगमा गांव के समीप तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से 45 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपुर नगमा गांव निवासी अवध बिहारी यादव (पिताः रामप्रसाद यादव) के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की दोपहर अवध बिहारी यादव पैदल सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान रामपुर नगमा स्थित अनुमंडल अस्पताल के पास एक अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अवध बिहारी उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत पास के अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना एम्स रेफर कर दिया। पटना ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एम्स पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पालीगंज पुलिस सक्रिय हो गई। परिजनों ने शव को वापस गांव लाया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया है और बाइक सवार दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अचानक हुई इस दुर्घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतक अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गया है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना ने एक बार फिर अनियंत्रित रफ्तार और सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र में यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

पटना के दुल्हिन बाजार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

चोरी के दो बाइक और समरसेबल मोटर के साथ पांच चोर गिरफ्तार

समाज जागरण

पटना/ दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के कूकरी बिगहा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर चोरी के बड़े गिरोह का पदार्फाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान पांच शातिर चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बरामदगी के तहत पुलिस ने चोरी की दो मोटरसाइकिल और एक समरसेबल मोटर जब्त की है। शुक्रवार की शाम पटना पश्चिमी नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि कूकरी बिगहा गांव निवासी बिंदा यादव का पुत्र कमलेश कुमार अपने पास चोरी की एक मोटरसाइकिल रखे हुए है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए दुल्हिन बाजार थानाध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तुरंत कूकरी बिगहा गांव में छापेमारी की और कमलेश कुमार को चोरी की बाइक के साथ दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार कमलेश कुमार ने अपने साथियों के बारे में कई अहम जानकारियां दीं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया, जहां से चार अन्य चोरों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कूकरी बिगहा निवासी कमलेश कुमार, नीरज कुमार (पिता राजा यादव), तथा पाठक मिल्की गांव निवासी रवि कुमार (पिता मिंटू यादव), विक्की कुमार (पिता नन्दू यादव) और रहीश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए चोरों के पास से चोरी की कुल दो मोटरसाइकिल और एक समरसेबल मोटर बरामद की गई है। इन चोरों के पकड़े जाने से क्षेत्र में वाहन चोरी और अन्य सामानों की चोरी की घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद है। गिरफ्तार पांचों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुट गई है। इस सफल छापेमारी से स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है।

तीन माह की ₹7,500 राशि एक साथ मिलने से खिले लाभुकों के चेहरे, मइयां सम्मान योजना से महिलाओं को मिली बड़ी राहत

पंकज कुमार पाठक, समाज जागरण

पदमाः झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के तहत तीन माह की लंबित सहायता राशि एक साथ लाभुकों के बैंक खातों में पहुंचने से महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। योजना की 21वीं, 22वीं एवं 23वीं किस्त की कुल ₹7,500 की राशि खाते में जमा होने के बाद लाभुकों के चेहरे खिल उठे हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

पिछले तीन माह से किस्त की राशि नहीं मिलने के कारण लाभुक महिलाएं भुगतान का इंतजार कर रही थीं। अब तीनों किस्तों की राशि एक साथ मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिली है। लाभुकों का कहना है कि यह राशि घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी खर्च तथा अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में काफी सहायक सिद्ध होगी।

पदमा प्रखंड सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में राशि पहुंचने के बाद लाभुकों ने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। योजना से जुड़ी महिलाओं का मानना है कि यह आर्थिक सहायता उनके परिवार की आय को मजबूती देने के साथ-साथ महिलाओं के सम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पटना के बिहटा में पूर्व मुखिया संजय यादव की संदिग्ध मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों किया सड़क जाम

समाज जागरण पटना जिला संवाददाताः– वेद प्रकाश

पटना/ जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में शुक्रवार की सुबह पूर्व मुखिया सह कारोबारी संजय यादव (55) का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक पिछले आठ माह से एक हथियार बरामदगी मामले में फरार चल रहे थे और जल्द ही न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की तैयारी में थे। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जमकर हंगामा किया और बिहटा-बिक्रम-औरंगाबाद मुख्य मार्ग को चार घंटे तक जाम कर दिया।

शुक्रवार सुबह ग्रामीण जब गांव के बधार (खेत) की ओर गए, तो बोरिंग के पास संजय यादव का शव पड़ा देख दंग रह गए। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुवार रात 11 बजे तक उनकी बातचीत संजय से हुई थी, तब वे पटना में थे। अचानक सुबह उनका शव गांव में मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। परिजनों का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर उनकी हत्या की गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने दोषियों की गिरफ्तारी और जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। राघोपुर तीन मोहानी के समीप हुए इस प्रदर्शन के कारण यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आश्वासन और निष्पक्ष जांच के भरोसे के बाद ग्रामीण शांत हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के लिए पटना से एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संकेत कुमार ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। पुलिस हर पहलू, विशेषकर पूर्व में दर्ज आपराधिक मामलों और जमीन विवाद, पर बारीकी से जांच कर रही है। देर शाम सांसद पप्पू यादव ने भी राघोपुर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में संजय यादव के घर से हथियारों की बरामदगी के बाद से वे फरार थे।

हिमांशु सिंह हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम: नामजद आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाना में किया आत्मसमर्पण

समाज जागरण चांद कुमार लायेक (ब्यूरो चीफ)

जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड की जांच के बीच शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जब मामले में नामजद आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाना पहुंचकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी के सरेंडर करने की खबर सामने आते ही शहर में इस मामले को लेकर एक बार फिर चचाओं का दौर तेज हो गया है।

जानकारी के अनुसार राहुल दुबे शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे अचानक बिष्टुपुर थाना पहुंचा और पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, पिछले कई दिनों से पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी और दबिश दी जा रही थी। शहर के विभिन्न संभावित ठिकानों पर पुलिस टीम कार्रवाई कर रही थी और मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जांच और गिरफ्तारी अभियान जारी था। माना जा रहा है कि लगातार बढ़ते दबाव और पुलिस कार्रवाई के बीच राहुल दुबे ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। हालांकि, कुछ स्तरों पर यह चर्चा भी सामने आई कि आरोपी ने संभावित पुलिस मुठभेड़ या कड़ी कार्रवाई की आशंका के कारण सरेंडर किया है, लेकिन इस संबंध में पुलिस या प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में इस प्रकार की चचाओं को फिलहाल केवल अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है।

आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने राहुल दुबे को अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि घटना के दौरान उसकी क्या भूमिका थी, वारदात की योजना किस प्रकार बनाई गई थी तथा इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि हिमांशु सिंह हत्याकांड ने पूरे जमशेदपुर को झकझोर कर रख दिया था। घटना के बाद शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई थी और विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। मामले को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन, बंद और जनआंदोलन भी देखने को मिले थे। कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा मामले की त्वरित जांच की मांग की थी।

हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष जांच टीम का गठन कर मामले की जांच तेज कर दी थी। इसके बाद लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया और मामले से जुड़े संदिग्धों एवं आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया। इसी क्रम में राहुल दुबे का आत्मसमर्पण जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। जांच के विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा रहा है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ और जांच के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से राहुल दुबे के आत्मसमर्पण को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उससे पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। शहरवासियों की नजर अब इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच और उसमें होने वाले अगले घटनाक्रम पर टिकी हुई है।

पटना में दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या, पति गिरफ्तार

समाज जागरण पटना जिला संवाददाताः– वेद प्रकाश

पटना/ जिले के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बी-एरिया में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कांटी निवासी रीना कुमारी (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतका के पिता के बयान पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति आदित्य नारायण को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता गणेश पासवान ने बताया कि रीना की शादी 2019 में जक्कनपुर निवासी आदित्य नारायण के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए रीना को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आदित्य और उसकी पांचों बहनें मिलकर रीना को दहेज के लिए अक्सर परेशान करते थे। इस दंपती की दो बेटियाँ हैं, जिनकी उम्र पांच साल और तीन साल है। पिता ने बताया कि गुरुवार दोपहर 3:15 बजे उनकी बेटी से अंतिम बार बात हुई थी। उस दौरान रीना रोते हुए कह रही थी कि ससुराल वाले उसे जान से मार देंगे और उसे बुरी तरह पीटा जा रहा है। बात करते-करते वह चिल्लाने लगी और अचानक फोन कट गया। इसके बाद जब उन्होंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। थोड़ी देर बाद ससुराल पक्ष की ओर से फोन आया कि "अभी मत आइए, यह आपस की बात है।" इसके कुछ देर बाद आरोपी पति आदित्य ने फोन कर झूठ बोला कि रीना ने खुदकुशी कर ली है। जब मायके वाले आनन-फानन में वहां पहुंचे, तो रीना का शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही जक्कनपुर पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुँचकर शव को कब्जे में लिया। थानाध्यक्ष ऋतुराज ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पति आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है। दहेज हत्या के इस मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त नई मूर्ति की हुए स्थापना

समाज जागरण रंजीत तिवारी

रामेश्वर वाराणसी।। कपसेठी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुरु में पॉलिटेक्निक के पास स्थित भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंची तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

इसके उपरांत सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब एवं उप जिलाधिकारी राजातालाब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के सहयोग से क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित कराई जा रही है।

घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात अभियुक्त की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर साक्ष्य संकलन सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

गुमटी का ताला तोड़ चोरों ने की चोरी

समाज जागरण रंजीत तिवारी

रामेश्वर वाराणसी। जंसा थाना क्षेत्र के रिंग रोड फेज-2 के किनारे हरसोस गांव के स्थित एक गुमटी का ताला तोड़कर चोर नगदी समेत हजारों रुपये का सामान उठा ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल कर लौट गई।

जानकारी के अनुसार, हरदासपुर गांव निवासी राकेश सिंह ने रिंग रोड किनारे गुमटी में दुकान संचालित कर रखी है। गुरुवार की देर रात तेज आंधी और बारिश शुरू होने पर वह गुमटी बंद कर अपने घर चले गए। शुक्रवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो गुमटी का ताला टूटा मिला। अंदर रखा करीब 1,700 रुपये नकद, डीप फ्रीजर, फाइबर की कुर्सियां, गैस सिलेंडर, चूल्हा, टेबल तथा गुटखा और सिगरेट समेत अन्य सामान गायब था।

घटना की सूचना पीड़ित ने तत्काल डायल-112 पर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पीड़ित राकेश सिंह ने जंसा थाने में लिखित तहरीर देकर चोरी का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तथा चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सुरक्षित मातृत्व दिवस पर 91 गर्भवती महिलाओं की हुयी जांच

06 मरीजों को किया गया जिला अस्पताल रेफर।

समाज जागरण अनिल कुमार

हरहुआ वाराणसी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरहुआ पर आज बृहस्पतिवार को सुरक्षित मातृत्व दिवस कार्यक्रम में कुल 91 गर्भवती महिलाओं की जॉच की गयी। 12 गर्भवती हाईरिस्क(उच्च जोखिम)में पायी गयी। 06 गर्भवती को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरहुआ डॉ0 संतोष कुमार ने बताया कि शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से हर महिने की 9 तारीख को सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। जिसमें बीपी, शुगर, एचआईवी,हीमोग्लोबिनआदि जांच की जाती है और मुफ्त अल्ट्रासाउंड कराया जाता है।।

डॉ. नन्दआसरे और डॉ0 मनु चतुवेर्दी ,अपर शोध अधिकारी ,कर्णिका सिंह, बीपीएम बसंतलाल श्रीवास्तव, स्टाफ नर्स अंजना सिंह ,संजू कुमारी ,रोजमेरी बोथा फार्मासिस्ट विद्या प्रकाश दुबे , फार्मासिस्ट राकेश कुमार ,सुपरवाइजर माखन शर्मा ,मनीष कुमार गुप्ता, संदीप कुमार भारती ,संतोष कुमार ,राकेश कुमार, कार्यालय सहायक पंकज कुमार सिंह, एएनएम सुचिता सिंह, इंद्रकला, भानुमति, मिलन सिंह , राजकुमारी, किरन लता, समस्त आशा संगिनी और आशा कार्यकर्ता शामिल रहे।

हरहुआ में किसानों के खेत पर क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल फार्म होगा विकसित

समाज जागरण अनिल कुमार

हरहुआ वाराणसी। हरहुआ ब्लाक के आयर ग्राम पंचायत में आज शुक्रवार को संयुक्त कृषि निदेशक शैलेन्द्र कुमार द्वारा किसानों के खेत पर एक क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल फार्म विकसित किये जाने का शुरूआत किया।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लाइमेट मॉडल में एकीकृत खेती प्रणाली को आधार बनाया गया है जिसमें कृषि के साथ पशुपालन औद्यानिक कृषि वानिकी की पक्षेत्र पर दशार्या गया है। किसानों को पेड़ वितरित किया गया।

किसानों के खेत पर पौधों का रोपण संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा किया गया। कहा कि पौधरोपण से

विकासशील देशों का टिकाऊ (सस्टेनेबल)विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगी । औद्योगिक देशों को उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।

इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी कृषि विवेक सिंह, धर्मेंद्र दुबे ,प्राविधिक सहायक कृष्ण कुमार मौर्य ,फॉर्मर योजना के तहत चयनित कृषक अजीत कुमार के खेत पर पौधों का रोपण किया गया। कृषक बालचरण ,राजेंद्र प्रसाद, रामजतन व अन्य किसान उपस्थित रहे।

विशेष लोक अदालत जागरूकता 'राष्ट्र मध्यस्थ अभियान'2.0 बैठक ब्लाक सभागार में हुई सम्पन्न

समाज जागरण अनिल कुमार

हरहुआ वाराणसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , नई दिल्ली तथा मेडिएशन एवं कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थ अभियान 2.0' जागरूकता कार्यक्रम ब्लाक सभागार हरहुआ में सम्पन्न हुआ।

मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश राजीव मुकुल पांडेय ने कहा कि स्पेशल लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामलों के निस्तारण को 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में लंबित मामलों को 'राष्ट्र मध्यस्थ अभियान 2.0' के माध्यम से सुलह समझौता द्वारा करा सकते हैं। वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना मामले, घरेलू हिंसा मामले, चेक बाउंस ,वाणिज्य विवाद ,सेवा संबंधित विवाद,उपभोक्ता विवाद , ऋण वसूली ,वेदखली ,भूमि अधिग्रहण ,अन्य उपयोग

दीवानी मामले शामिल है।

उन्होंने बताया न्याय ग्राम की ओर एक मुहिम छेड़ा है और समय एवं धन की बचत के लिए लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण के लिए आपसी संबंधों में सुधार एवं सद्भाव के लिए न्याय प्रक्रिया के बोझ में कमी के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों का आपसी सहमति एवं सुलह समझौते के आधार पर त्वरित सरल एवं प्रभावी निस्तारण करने के लिए आप सी भेदभाव को खत्म करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में समाधान समारोह सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडीओ छोटेलाल तिवारी ने किया।

इस कार्यक्रम में एडीओ सांख्यिकी शैलेन्द्र सिंह ,एडीओ पंचायत कमलेश सिंह,एडीओ ग्राम्य विकास धनन्जय सिंह,बीओपीआरडी विवेक सिंह समस्त ग्राम विकास अधिकारी ,आशा कार्यकर्ता, पीएलवी संदीप कुमार वर्मा, मनोज कुमार, दिनेश, कुसुम लता, मंजू पांडेय, किरण टंडन, बबीता, खुशबू ,विनोद ,मनीष , संजय, विकास व ग्रामीण उपस्थित रहे।

कोइराजपुर मॉडल शॉप मामले में जांच पर उठे सवाल, शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच की मांग की

*** आबकारी विभाग ने लगाई भ्रामक आख्या**
*** मांग श्रेणी बताकर शिकायत को किए निस्तारित**
*** क्षेत्रीय लोगों में बढ़ रही नाराजगी**

समाज जागरण अनिल कुमार

हरहुआ वाराणसी। पिंडरा तहसील के कोइराजपुर गांव में संचालित मॉडल शॉप को लेकर दर्ज जनसुनवाई शिकायत (संदर्भ संख्या- 40019726026072) के निस्तारण पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग ने मामले की निष्पक्ष जांच करने के बजाय भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत कर शिकायत का निस्तारण कर दिया।

शिकायत के अनुसार, संबंधित मॉडल शॉप राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से निर्धारित दूरी मानकों का पालन नहीं कर रही है। शिकायतकर्ता का दावा है कि दुकान हाईवे से लगभग 183 से 185 मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश आबकारी नीति के क्लॉज 1.2.2 (iii) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से शराब की दुकान की न्यूनतम दूरी 220 मीटर होना अनिवार्य है।

मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मॉडल शॉप के समीप संत जोसफ कॉन्वेंट स्कूल स्थित है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल परिसर के आसपास विद्यार्थियों की आवाजाही और स्कूल बसों का संचालन होता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।

शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार यादव का आरोप है कि जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत के निस्तारण में आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में कई तथ्यात्मक विसंगतियां हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट में यह दशार्या गया कि वे जांच प्रक्रिया में शामिल हुए और कार्रवाई से संतुष्ट हैं, जबकि यह पूरी तरह गलत है।

शिकायतकर्ता का दावा है कि शिकायत दर्ज होने के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक स्थल की आधिकारिक नापी नहीं कराई गई है। उनका आरोप है कि दूसरी रिपोर्ट में विभाग ने यह उल्लेख किया कि रिंग रोड राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) है या राज्य राजमार्ग (एसएच), इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। विभाग द्वारा एनएचएआई से पत्राचार किए जाने की बात कहते हुए शिकायत का निस्तारण कर दिया गया, जबकि एनएचएआई की रिपोर्ट अभी प्राप्त ही नहीं हुई है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शिकायत मॉडल शॉप से संबंधित थी, लेकिन विभागीय रिपोर्ट में इसे देशी शराब की दुकान से जुड़ा मामला बताकर प्रस्तुत किया गया, जिससे शिकायत के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया।

वाराणसी रिंग रोड की स्थिति को लेकर भी विवाद बना हुआ है। शिकायतकर्ता का कहना है कि संबंधित मार्ग केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में दर्ज है, लेकिन विभागीय रिपोर्ट में इस संबंध में स्पष्ट स्थिति नहीं बताई गई। इस मामले में शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की किसी सक्षम अधिकारी से भौतिक सत्यापन और दूरी की पुनः नापी कराकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

इस मामले को लेकर क्षेत्रीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बड़ी संख्या में एकजुट होकर रिंग रोड जाम करने के लिए मजबूर होंगे।

मृतका के परिजनों ने चौकी पुलिस पर अभद्रता का लगाया आरोप, एसीपी बोले - निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई......

समाज जागरण संवाददाता

मोहनलालगंज, लखनऊ। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के खुजौली गांव में विवाहिता गुड़िया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शुरूआती स्तर पर पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद पुलिस ने पति समेत नामजद ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

मृतका की मां दुर्गा निवासी गनेशखेड़ा, मजरा मऊ ने बताया कि उनकी पुत्री गुड़िया का विवाह करीब 12 वर्ष पूर्व खुजौली निवासी अनिल पुत्र स्वर्गीय बंसी के साथ विवाह हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से पति अनिल, जेठ सुनील कुमार, सास विमला, ननद कोमल तथा अन्य ससुरालीजन लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। कई बार मारपीट कर उसे मायके भेज दिया गया, लेकिन समझौते के प्रयासों के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी।परिजनों के अनुसार, बीते गुरुवार की सुबह करीब आठ बजे गुड़िया ने अपनी बहन को फोन कर रोते हुए कहा, "मुझे बचा लो", जिसके कुछ ही पल बाद फोन कट गया। परिजन जब उसकी ससुराल पहुंचे तो गुड़िया का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। उनका आरोप है कि पहले उसकी हत्या की गई और बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या की घटना का रूप देने का प्रयास किया गया।मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि खुजौली चौकी में तैनात उपनिरीक्षक अजय सिंह और चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उनका कहना है कि इस मामले से जुड़े वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हुए। परिजनों का दावा है कि इसके बाद ही पुलिस ने आनन-फानन में पति समेत नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।इस मामले में एसीपी मोहनलालगंज राजेश कुमार सिंह ने कहा कि, "मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की हर पहलू से निष्पक्ष और गहन जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर लगाए गए आरोपों में तथ्य पाए जाते हैं तो उनकी भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के परिजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान में 22 स्कूली वाहनों का चालान, 11 वाहन सीज

समाज जागरण

मीरजापुर / 10 जुलाई परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में दिनांक 01 जुलाई से 15 जुलाई, तक शिक्षण संस्थाओं के वाहनों का सघन जांच अभियान "मिशन सेफ फ्यूचर" संपादित किया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी विद्यालयों को नोटिस / सूचना तथा अनफिट वाहनों की जांच की गयी तथा दूसरे चरण में दिनांक 08 जुलाई २से 15 जुलाई तक अनफिट विद्यालयी वाहनों के विरूद्ध सतत चेकिंग कार्यवाही की जा रही है।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मीरजापुर के पर्यवेक्षण में जनपद के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रो में चेकिंग अभियान चलाकर नियमो की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों पर कार्यवाही की गयी। उक्त अभियान के अन्तर्गत 22 स्कूली वाहनों का चालान किया गया तथा जनपद मे विभिन्न थानों में 11 वाहनों की सीज किया गया। अवैध एवं डग्गामार संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 44 वाहनों का चालान करते हुए 34 वाहनों को निरूद्ध किया गया।

इस अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), प्रथम, यात्री/मालकर अधिकारी-प्रथम एवं यात्री / मालकर अधिकारी द्वितीय सहित पुलिस विभाग व परिवहन विभाग के प्रवर्तन पर्यवेक्षक व प्रवर्तन सिपाही सम्मलित रहें।

निगोहां में घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ व अपहरण के प्रयास का आरोप, चार नामजद पर मुकदमा दर्ज

समाज जागरण संवाददाता

निगोहां के एक गांव में घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ और उसे जबरन उठाकर ले जाने के प्रयास का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती और उसकी मां के साथ मारपीट की तथा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद उसने तत्काल निगोहां पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बाद में डीसीपी से गुहार लगाने और मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शुक्रवार शाम पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।पुलिस के मुताबिक निगोहां के एक गांव की रहने वाली युवती ने तहरीर देकर बताया कि गुरुवार रात करीब आठ बजे गांव के रिंकू बाजपेई, देवेन्द्र बाजपेई, सुरेन्द्र बाजपेई उर्फ ननकू और नरेन्द्र बाजपेई गाली-गलौज करते हुए उसके घर में घुस आए। मां के विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान वहां पहुंची युवती का हाथ पकड़कर उसका मुंह दबा दिया और जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया।युवती के शोर मचाने पर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने एफआईआर कराने पर उसके भाई-बहनों की हत्या करने की धमकी भी दी।पीड़िता का कहना है कि घटना के तुरंत बाद वह शिकायत लेकर निगोहां थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद वह परिजनों के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार शाम चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।निगोहां थाना प्रभारी रवींद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

युवा समाजसेवी अजय कुमार सिंह उर्फ छोटू पटेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ की सड़क को कराया दुरुस्त

5 वर्षों से सड़कों में जल जमाव से स्थानीय लोगों का जीना हुआ दुश्वार, छोटू पटेल ने सड़कों को कराया दुरुस्त।

समाज जागरण

मीरजापुर/ विकासखंड राजगढ़ के ग्राम पंचायत राजगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाले मुख्य मार्ग पर पिछले चार सालों से जलभराव की विकट समस्या बनी हुई थी। बारिश के बाद जमा पानी और कीचड़ के कारण मरीजों, स्कूली बच्चों और आमजन का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका था।

क्षेत्रीय जनता की परेशानी को देखते हुए क्षेत्र के जाने-माने समाजसेवी एवं शहनाई कंस्ट्रक्शन, रामपुर सक्तेसगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कुमार सिंह उर्फ छोटू पटेल ने स्वयं आगे बढ़कर समस्या के समाधान का बीड़ा उठाया। उन्होंने जेएसबी का चूड़ा गिराकर मार्ग से जलभराव की समस्या के कारण जो परेशानी थी उसे अस्थाई रुप से दूर करने का कार्य शुरू कराया। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद मार्ग से आवागमन संभव हो सका।

छोटू पटेल के इस सराहनीय कार्य से अब राहगीरों को आवागमन में सुविधा हो गई। जो कार्य ग्राम प्रधान को करवाना चाहिए वह काम युवा समाजसेवी अजय कुमार सिंह पूर्व छोटू पटेल ने कराया इसके अलावा उन्होंने लगभग तीन दर्जन से ज्यादा गांव में लगातार काम कर रहे हैं विकासखंड राजगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों चुनार क्षेत्र के जमुई में भी इन्होंने काम कराया। सबसे ज्यादा राहत CHC आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को मिली है। अजय कुमार सिंह उर्फ छोटू पटेल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी गांव में सर के खराब हो चुकी है चलने में दिक्कत हो रही है तो शहनाई परिवार के सदस्यों से संपर्क करें जल्दी समस्या का समाधान कराया जाएगा। लगभग 5 वर्षों से गांव में निशुल्क काम करा रहे हैं और यह अभियान लगातार चल रहा है। जहां भी सूचना मिल रही है वहां पर रास्ते को दुरुस्त कराया जा रहा है। जहां पर आने जाने वाले स्कूली बच्चों बुजुर्गों छात्र छात्राओं सभी को सहूलियत मिल सके अब एंबुलेंस और अन्य वाहन भी बिना किसी रुकावट के अस्पताल तक पहुंच सकेंगे।ग्रामीणों ने अजय पटेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। लोगों ने कहा कि ऐसे समाजसेवियों के कारण ही गांव की समस्याएं समय पर दूर हो पाती हैं। शहनाई परिवार से सत्येंद्र कुमारसिंह, अजय कुमार सिंह सिब्बू, अमरेश चंद्र, मनीष पटेल, स्थानीय शेखर करवल, कृष्णानंद केसरवानी, अमरेश दुबे, वीरेंद्र मौर्य, संजू मिश्रा, उपस्थित रहे।

भारत-ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते का लाभ उठाएं उद्यमी : आलोक

- जनपद के उद्यमी एवं निर्यातकों ने निर्यात सम्मेलन में की शिरकत
- मीरजापुर के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुलभ बनाना चाहता है उद्योग विभाग

समाज जागरण

मीरजापुर। जिले के उद्यमियों के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जनपद के एक होटल में केंद्र सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) व जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र व अन्य के संयुक्त तत्ववाधान में निर्यात सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योग से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा मीरजापुर के उद्यमियों को भारत-ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के बारे में विस्तार से बताते हुए इसका लाभ उठाने के टिप्स दिए गए। इस मौके पर संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार, सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार राजन जोशी, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र संदीप कुमार, सहायक निदेशक फियो आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक एमएसएमई-डीएफओ वैभव खरे , बीएम

ईसीजीसी लिमिटेड की ओर से मुरलीधर महतो , आईआईए के डिविजनल चेयरमैन मोहनदास अग्रवाल, आईआईए के चैप्टर चेयरमैन आशीष बुधिया, प्रतिनिधि लघु उद्योग भारती एवं निर्यातक आशीष सिंह, उद्यमी और ट्रेड एसोसिएशन के पदाधिकारी व अन्य अतिथि मौजूद रहे ।कार्यक्रम की शुरूआत संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई।

इस अवसर पर फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मुक्त व्यापार समझौता उत्तर प्रदेश और भारत के लिये नए अवसर खोलेगा जिससे यूनाइटेड किंगडम को समान और सेवाओ के निर्यात में भी फायदा होगा और इन्वेस्टमेंट के अवसर भी खुलेंगे। इसका उद्देश्य पेशेवर गतिशीलता को बढ़ावा देना, नियामक सहयोग को मजबूत करना और सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना है। भारतीय उत्पादों के निर्यात पर ब्रिटेन में शुल्क शून्य कर दिया गया है जिससे भारत के उत्पादों का एक बड़ा बजार ब्रिटेन होने वाला है

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मिजार्पुर ऐतिहासिक रूप से उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उद्योगों को नई दिशा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं। उन्होंने उद्योग एवं प्रशासन के द्वारा पूर्ण सहयोग देने पर बल दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश एम एस एम ई विभाग के बारे में जानकारी प्रदान की। सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार राजन जोशी ने निर्यातकों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बना रही है। उन्होंने उद्यमियों से डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं नई व्यापार नीतियों का लाभ उठाने का आह्वान किया। जोशी ने डीजीएफटी के द्वारा निर्यात में प्रदान की जा रही विभिन्न योजनाओं में बारे में बताया एवं जिला निर्यात हब योजना के अंतर्गत निर्यात बढ़ाने व नए बाजार उपलब्ध कराने, ब्रांडिंग, अन्य विषयों पर चर्चा की!

उपायुक्त उद्योग संदीप कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निर्यात प्रोत्साहन नीतियों एवं औद्योगिक योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को देश का अग्रणी निर्यातक राज्य बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग तथा विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सके। कार्यकम में जिले के 40 से अधिक उद्यमियों व निर्यातकों ने भाग लिया और कार्यकम को बहुत ही उपयोगी बताया साथ ही साथ भविष्य में इस तरह के और भी सम्मेलन आयोजित करने की इच्छा जताई।

चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को विधायक अनुराग सिंह ने वितरित किया नियुक्ति पत्र

समाज जागरण

मीरजापुर /जुलाई बाल विकास एवं पुष्टाहार, अनुभाग लखनऊ, पिछले वर्ष 17 सितम्बर, 2025, एवं निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ द्वारा समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया के तहत जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के अनुमोदन उपरान्त जनपद मीरजापुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना सीटी ग्रामीण में-22, पहाड़ी-38, मझवां-26, लालगंज-36 एवं हलिया-43 कुल 165 लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार विधायक मझवां सुचिस्मिता मौर्या के करकमलों द्वारा चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं के नियुक्ति पत्र का वितरण, विकास भवन सभागार किया

गया। विधायक, चुनार अनुराग सिंह, द्वारा तहसील चुनार सभागार में बाल विकास परियोजना- नरायनपुर-50, जमालपुर-25, सीखड़-17 कुल 92 चयनित सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया एवं उनके उज्वल भविष्य की कामना के साथ चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन-मानस तक पहुँचाने के लिए प्रेरित किया गया।

हादसों के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, हाईवे पर अवैध पार्किंग के खिलाफ पूर्व विंध्य विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने खोला मोर्चा

समाज जागरण

अनूपपुर। पूर्व विंध्य विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार गुप्ता ने जिले के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग को गंभीर जनसुरक्षा का विषय बताते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में भी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। श्री गुप्ता ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि जैतहरी-अनूपपुर मार्ग, चचाई-अनूपपुर मार्ग तथा कोतमा-अनूपपुर मुख्य मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों भारी मालवाहक वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। इससे यातायात बाधित होता है और विशेषकर रात्रि के समय दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों का निर्माण आमजन की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही के लिए किया गया है, लेकिन वर्तमान में ये मार्ग अवैध पार्किंग स्थल बनते जा रहे हैं।

उन्होंने विशेष रूप से आरोप लगाया कि जैतहरी स्थित एम.बी. पावर प्लांट से फ्लाई ऐश (राखड़) परिवहन में लगे सैकड़ों वाहन दुगार्दास चौक से लेकर अनूपपुर के तिपान नदी क्षेत्र तक सड़क किनारे लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और आम लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। अनिल कुमार गुप्ता ने हाल ही में एनएच-43 पर हुई उस दर्दनाक दुर्घटना का भी

उल्लेख किया, जिसमें पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के एक परिवार के चार सदस्यों की सड़क किनारे खड़े भारी वाहन से टकराने के कारण मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं प्रशासन के लिए चेतावनी हैं और इनसे सबक लेकर स्थायी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि किसी बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ दिनों तक अभियान चलाया जाता है, लेकिन बाद में स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। यह प्रशासनिक लापरवाही और जनहित के प्रति उदासीनता का परिचायक है। सड़क सुरक्षा केवल अभियान चलाने से नहीं, बल्कि नियमित निगरानी और कानून के सख्त पालन से सुनिश्चित होगी।

ज्ञापन में श्री गुप्ता ने मांग की है कि मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से पार्क किए जाने वाले भारी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर नियमित जांच की जाए, दोषी वाहन मालिकों एवं चालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो तथा भविष्य में इस प्रकार की अव्यवस्था रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल तथा पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन को भी प्रतिलिपि प्रेषित कर शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़ा यह विषय किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि जनहित और जनजीवन की सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिए प्रशासन को बिना विलंब प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।

बरगवां(अमलाई) की पानी टंकी निर्माण में लापरवाही के आरोप, सुरक्षा इंतजामों पर उठे गंभीर सवाल

60-70 फीट की ऊंचाई पर बिना सेफ्टी बेल्ट काम, अमृत 2.0 परियोजना में हादसे का इंतजार?

समाज जागरण

बरगवां (अमलाई)। नगर परिषद बरगवां (अमलाई) के वार्ड क्रमांक 9 में अमृत 2.0 योजना के तहत निमार्णाधीन पानी की ऊंची टंकी (ओवरहेड वाटर टैंक) में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किए जाने के आरोप सामने आए हैं। निर्माण स्थल पर लगभग 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर 8 से 9 मजदूर कार्य करते दिखाई दिए, लेकिन मौके पर अधिकांश मजदूरों के पास आवश यक सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस, हेलमेट तथा अन्य ऊंचाई पर कार्य करने के अनिवार्य सुरक्षा संसाधन उपयोग में नहीं दिखे। इससे निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मजदूरों से लगातार ऊंचाई पर कार्य कराया जा रहा है, जबकि मौके पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कोई जिम्मेदार सुरक्षा अधिकारी या संबंधित अधिकारी

उपस्थित नहीं मिला। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की जान जोखिम में पड़ सकती है। निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन मजदूर स्वयं उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि श्रम सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल उपकरण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होता। कार्यस्थल पर नियोक्ता और निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि बिना सुरक्षा उपकरण के किसी भी श्रमिक को ऊंचाई पर कार्य न करने दिया जाए तथा सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

श्रम सुरक्षा से जुड़े नियमों एवं डीजीएमएस(Directorate General of Mines Safety) सहित अन्य सुरक्षा मानकों की भावना भी यही है कि जोखिम वाले कार्यों में श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण पहनाना और उनका उपयोग सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी है। यदि कोई श्रमिक सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं करता है तो उसे तब तक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक वह निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन न करे।

इस निर्माण कार्य को लेकर एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहा है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जिस क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, वह पूर्व में भूमिगत कोयला खनन(अंडरग्राउंड कॉलरी) से प्रभावित क्षेत्र रहा है। ऐसे क्षेत्रों में किसी भी बड़े निर्माण से पहले संबंधित खनन कंपनी एवं सक्षम प्राधिकरण से तकनीकी परीक्षण और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। सूत्रों का यह भी दावा है कि संबंधित एनओसी की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे निर्माण की तकनीकी सुरक्षा पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि इस संबंध में संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना शेष है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली अमृत 2.0 योजना की इस महत्वपूर्ण परियोजना में गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना या जनहानि होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन, नगर परिषद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा संबंधित निर्माण एजेंसी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, सुरक्षा मानकों का तत्काल पालन सुनिश्चित कराने तथा निर्माण स्थल पर सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही यदि निर्माण से पूर्व

आवश्यक तकनीकी स्वीकृतियां एवं एनओसी प्राप्त नहीं की गई हैं तो उनकी भी जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है।

"रक्सा-कोलमी परियोजना बनी विकास की नई पहचान:

किसानों को रोजगार, क्षेत्र को मिलेगी नई उड़ान; कंपनी ने भ्रामक दावों को बताया निराधार"

समाज जागरण विजय तिवारी

अनूपपुर। जिले के रक्सा-कोलमी क्षेत्र में प्रस्तावित ऊर्जा परियोजना को लेकर चल रही चचाओं के बीच कंपनी ने पहली बार विस्तार से अपना पक्ष सामने रखा है। कंपनी का कहना है कि परियोजना का उद्देश्य केवल औद्योगिक निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देना और प्रभावित परिवारों को नियम नुसार लाभ उपलब्ध कराना भी है। कंपनी के अनुसार परियोजना क्षेत्र के आसपास के अनेक ग्रामीणों एवं किसानों को आवश्यकता और उपलब्ध कार्य के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि कार्य के अनुरूप उचित भुगतान किया जा रहा है तथा भुगतान में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से निगरानी करते हैं और समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कंपनी का कहना है कि परियोजना के निर्माण कार्य के आगे बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। निर्माण कार्य, परिवहन, मशीन संचालन, सुरक्षा सेवाएं, रखरखाव, खानपान, सामग्री आपूर्ति और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। कंपनी का कहना है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

स्वामित्व में बदलाव, दायित्वों में नहीं

कंपनी का कहना है कि स्वामित्व संरचना में हुए परिवर्तन के बावजूद परियोजना से जुड़े वैधानिक दायित्व समाप्त नहीं होते। कंपनी के अनुसार लागू कानूनों, वैध अनुबंधों और संबंधित प्रावधानों के तहत जो भी जिम्मेदारियां निर्धारित हैं, उनका पालन किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि उसका उद्देश्य सभी प्रक्रियाओं को नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना है।

₹211 करोड़ के संबंध में कंपनी का स्पष्टीकरण

हाल के दिनों में सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर ₹211 करोड़ के कथित कॉर्पोरेट लेन-देन को लेकर कई प्रकार की चचाएं सामने आई हैं। इस संबंध में कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सुशील कांत मिश्रा ने कहा कि कंपनी के अनुसार इस विषय में कई जानकारियां अधूरी अथवा संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत की जा रही हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यावसायिक लेन-देन या कॉर्पोरेट प्रक्रिया को समझने के लिए आधिकारिक दस्तावेजों, नियामकीय अभिलेखों और अधिकृत सूचनाओं को ही आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपुष्ट दावों और सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के आधार पर निष्कर्ष न निकालें।

"अफवाहों से बचें, अधिकृत जानकारी पर भरोसा करें"

असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सुशील कांत मिश्रा ने कहा कि परियोजना को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जिनसे स्थानीय लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंपनी के अधिकृत अधिकारियों अथवा संबंधित सरकारी विभागों से ही पुष्टि करें। उन्होंने कहा कि कंपनी स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का प्रयास है कि परियोजना के प्रत्येक चरण में नियमानुसार कार्य करते हुए स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल सकती है नई गति

कंपनी का कहना है कि बड़े औद्योगिक निवेश के साथ क्षेत्र में परिवहन, छोटे व्यापार, किराये के वाहन, निर्माण सामग्री, होटल, भोजनालय, मशीनरी, श्रम सेवाओं और अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी नई गति मिलने की संभावना है। इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। कंपनी ने अंत में दोहराया कि वह परियोजना को कानून के अनुरूप, पारदर्शी प्रक्रिया और स्थानीय समुदाय के सहयोग के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा लोगों से अपील की कि वे किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें।

रेलवे निर्माण घोटाले की खबर पर जांच शुरू,अब जांच दल की निष्पक्षता पर उठे सवाल

समाज जागरण

उमरिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल के अंतर्गत कटनीझबिलासपुर मुख्य रेलखंड के बंधवावारा-घुनघुटी सेक्शन (किमी 922 से 924) के बीच करोड़ों रुपये की लागत से कराए जा रहे नाली निर्माण एवं सेस रिपेयर कार्यों में कथित घटिया निर्माण, निम्न गुणवत्ता की सामग्री के उपयोग तथा वित्तीय अनियमितताओं को लेकर समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित खबरों के बाद रेलवे प्रशासन ने विजिलेंस जांच प्रारंभ कर दी है। किंतु जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर अभी से गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच के लिए पहुंचे रेलवे विजिलेंस निरीक्षक ने जांच स्थल की जांच के पहले ही उन संबंधित अधिकारियों के संपर्क में रहकर जांच कर रहे हैं,जो इस गुणवत्ता के लिए दोषी माने जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों एवं रेल कर्मचारियों के बीच जांच की पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों में लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। स्थानीय नागरिकों एवं रेल कर्मचारियों के बीच दबे स्वर में यह चर्चा भी है कि जांच दल प्रारंभ से ही संबंधित अधिकारियों के प्रभाव में कार्य कर रहा है। उनका कहना है कि यदि जांच वास्तव में निष्पक्ष एवं प्रभावी होती, तो मंडल में करोड़ों रुपये की लागत वाले निर्माण कार्यों में इतनी गंभीर वित्तीय अनियमितताएं एवं रेल संरक्षा से जुड़े कथित मामले लगातार सामने नहीं आते। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन चचाओं ने जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्व सनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। जानकारों का कहना है कि रेलवे विजिलेंस निरीक्षक मूल रूप से रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (SSE) संवर्ग के अधिकारी होते हैं, जिन्हें सीमित अवधि के लिए विजिलेंस विभाग में प्रतिनियुक्त किया जाता है। निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के बाद वे पुनः मंडल में लौटकर इंजीनियरिंग विभाग में कार्य करते हैं तथा सहायक मंडल अभियंता (ADEN) एवं वरिष्ठ मंडल अभियंता (Sr. DEN) के प्रशासनिक नियंत्रण में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसी व्यवस्था में, जब जांच उन्हीं अधिकारियों या उसी प्रशासनिक तंत्र से जुड़े मामलों की हो, तो हितों के टकराव Conflict of Interest) की आशंका को लेकर प्रश्न उठना स्वाभाविक माना जा रहा है। इसी आधार पर स्थानीय नागरिकों एवं जागरूक मीडिया ने मांग की है कि इस मामले की जांच बिलासपुर मंडल की स्थानीय विजिलेंस टीम के स्थान पर किसी अन्य जोनल रेलवे की विजिलेंस टीम अथवा रेलवे बोर्ड विजिलेंस से कराई जाए, ताकि जांच की निष्पक्षता, पारदर्शिता

और विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे तथा वास्तविक तथ्य सामने आ सकें। लोगों का कहना है कि यदि करोड़ों रुपये के रेलवे निर्माण कार्यों में लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच भी पूर्णतः स्वतंत्र एजेंसी से नहीं कराई गई, तो जनता का विश्वास प्रभावित होगा और रेल संरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे। स्थानीय नागरिकों ने रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय से मांग की है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र उच्च स्तरीय विजिलेंस एवं तकनीकी समिति से कराई जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, जिससे दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

साइबर ठगी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, चार मोबाइल और सात बैंक पासबुक बरामद

समाज जागरण -ब्रजमोहन सिंह

फिरोजाबाद। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दक्षिण पुलिस ने चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन और सात बैंक पासबुक बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी अलग-अलग खातों के माध्यम से लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे साइबर बज्र अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना दक्षिण पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करबला क्षेत्र से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में संजय सिंह सुमन पुत्र वीर सिंह सुमन निवासी करबला गली नंबर-10 थाना दक्षिण, हेमंत कुमार पुत्र धर्मेंद्र कुमार निवासी पीपल मंडी करबला, सूरज राठौर पुत्र बीरी सिंह निवासी गली नंबर-5 करबला थाना दक्षिण और हामिद पुत्र नौशाद निवासी कश्मीरी गेट थाना रामगढ़ शामिल हैं।

पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन और सात बैंक पासबुक बरामद की हैं।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों द्वारा अपने विभिन्न बैंक खातों का इस्तेमाल कर लोगों से लाखों रुपये की ठगी की गई है। इस मामले में थाना दक्षिण में मुकदमा संख्या 713/2026 के तहत धारा 318(4)/317(2) बीएनएस में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक योगेंद्रपाल सिंह, निरीक्षक अपराध अजय सिंह, उपनिरीक्षक सिंहराज सिंह, उपनिरीक्षक राजकुमार गौतम सहित थाना दक्षिण पुलिस टीम शामिल रही।

अमलाई पोस्ट ऑफिस बचाने भाजपा का हस्तक्षेप, जीएम ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

अमलाई कॉलरी पोस्ट ऑफिस नहीं शिफ्ट होगा अन्यत्र*।

समाज जागरण

अमलाई ,अनूपपुर। अमलाई कॉलरी स्थित डाकघर (पिन कोड 484 116) को बंद होने या अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की आशं काओं के बीच क्षेत्रवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पूर्व में प्रकाशित समाचार के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पोस्ट ऑफिस को बचाने, जर्जर भवन की मरम्मत कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर नई बिल्डिंग उपलब्ध कराने की मांग लेकर सुहागपुर एरिया के महाप्रबंधक (जीएम) श्री जेना से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में नगर परिषद बरगवां-अमलाई के उपाध्यक्ष डॉ. राज तिवारी, भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी अखिलेश सिंह, बूथ अध्यक्ष सौरभ सिंह, अधिवक्ता अरविंद साहनी, वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी, सुनील तिवारी, मनोज पांडे, गौतम सर तथा अमलाई पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर श्री टोप्पो शामिल रहे। ज्ञापन में बताया गया कि 484116 पिन कोड वाला अमलाई पोस्ट ऑफिस वर्षों से क्षेत्र के हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, पेंशनधारकों एवं व्यापारियों के लिए संचार और डाक सेवाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। वर्तमान भवन अत्यंत जर्जर हो चुका है, जिससे कर्मचारियों

और आम नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। इसलिए भवन की तत्काल मरम्मत कराई जाए अथवा किसी सुरक्षित रएउछ भवन में पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित कर उसी क्षेत्र में संचालित रखा जाए।

प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से लेते हुए जीएम श्री जेना ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली और तत्काल आवश यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोस्ट ऑफिस की सेवाएं क्षेत्र में ही सुचारू रूप से जारी रहेंगी। भवन की मरम्मत अथवा वैकल्पिक सुरक्षित भवन की व्यवस्था की जाएगी तथा पोस्ट ऑफिस को क्षेत्र से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

जीएम के इस सकारात्मक आश्वासन से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों, समाजसेवियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए भाजपा प्रतिनिधिमंडल और जीएम श्री जेना का आभार व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि इस निर्णय से वर्षों पुराना अमलाई पोस्ट ऑफिस (पिन कोड 484116) सुरक्षित रहेगा और क्षेत्र की जनता को भविष्य में भी निर्बाध डाक एवं बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा।।

हां या पोस्ट ऑफिस पहले भी कोल इंडिया के सहयोग से बनाया गया था और इसको यहां से ट्रांसफर नहीं होने दिया जाएगा पुराने भवन का निर्माण या जरूरत पड़ने पर नई बिल्डिंग बनाकर इस पोस्ट ऑफिस को कोल इंडिया के सहयोग से संचालित किया जाएगा मैं तत्काल इंजीनियर साहब को आदेश देकर करवाई शुरू करवाता हूं ।

मीटिंगों से नहीं थम रही ढाबों पर अवैध शराबखोरी! प्रभारी एसपी ने दी सख्त चेतावनी, फिर भी सवालों के घेरे में जमीनी अमल

शहडोल-उमरिया मुख्य मार्ग के ढाबा संचालकों की बैठक, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश; स्थानीय लोगों का दावा—हर बार चेतावनी, लेकिन हालात जस के तस

समाज जागरण

उमरिया। शहडोल-उमरिया मुख्य मार्ग पर संचालित ढाबों में कथित तौर पर अवैध शराब परोसने और बैठाकर मदिरापान कराने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उमरिया के प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने जिले के ढाबा संचालकों की बैठक आयोजित की। बैठक में सभी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि न होने दें तथा निर्धारित समय के अनुसार ही ढाबों का संचालन करें। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी ढाबे पर अवैध शराब की बिक्री, शराब पिलाने की व्यवस्था, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा या अन्य गैरकानूनी गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध वैधानिक धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी को नियमों का पालन करने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की हिदायत दी गई। हालांकि, स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय सूत्रों का कहना है कि शहडोल-उमरिया मुख्य मार्ग पर कई ढाबों में लंबे समय से अवैध रूप से शराब परोसने की शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप है कि कई स्थानों पर वाहन चालक और राहगीरों को खुलेआम बैठाकर शराब पिलाई जाती है, जिसके बाद वे नशे की हालत में अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाते हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पुलिस और प्रशासन समय-समय पर ढाबा संचालकों की बैठक लेकर चेतावनी देते हैं, लेकिन इन बैठकों का अपेक्षित असर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। कुछ दिनों तक सख्ती के बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है और अवैध गतिविधियों की शिकायतें दोबारा सामने आने लगती हैं। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि केवल बैठकें आयोजित करना पर्याप्त नहीं होगा। यदि मुख्य मार्ग पर नियमित निरीक्षण, आकस्मिक छापेमारी और नियमों का उल्लंघन करने वाले ढाबों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए, तभी अवैध शराबखोरी पर अंकुश लगाया जा सकेगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी ढाबा संचालक को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार प्रशासन की चेतावनी धरातल पर कितना असर दिखाती है और मुख्य मार्ग पर संचालित ढाबों में अवैध गतिविधियों पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है।

50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में एफआईआर, व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

समाज जागरण

उमरिया। जिले के चर्चित कारोबारी एवं कबीर बिल्डकॉन के संचालक विनोद आहूजा से कथित रूप से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने जांच के बाद गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, व्यापारी विनोद आहूजा ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर आरोप लगाया था कि विकास सचदेव लंबे समय से उनके खिलाफ लगातार झूठी एवं मनगढ़ंत शिकायतें विभिन्न विभागों में कर रहा था। शिकायत में कहा गया कि इन शिकायतों की शासन स्तर से लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत हुई जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया और किसी भी जांच में उनके विरुद्ध कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिससे आरोप सिद्ध होते हों। व्यापारी का आरोप है कि इसके बावजूद विकास सचदेव ने शिकायतों का सिलसिला बंद नहीं किया। शिकायत के अनुसार, एक दिन रात के समय विकास सचदेव ने उनसे संपर्क कर कथित रूप से 50 लाख रुपये की मांग की और कहा कि यदि यह राशि दे दी जाए तो वह उनके विरुद्ध की गई सभी शिकायतें वापस ले लेगा तथा आगे किसी प्रकार की शिकायत नहीं करेगा।

विनोद आहूजा ने इसे सीधी रंगदारी और धमकी बताते हुए अपनी तथा अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा पर भी खतरा जताया। उन्होंने इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज पुलिस अधीक्षक को सौंपते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने शिकायत की जांच के दौरान उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, साक्ष्यों और अन्य तथ्यों का परीक्षण किया। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध रंगदारी (एक्सटॉर्शन) से संबंधित प्रावधानों सहित अन्य लागू धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच जारी है। जांच के दौरान यदि और साक्ष्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, इस कार्रवाई के बाद जिले के व्यापारिक वर्ग में मामले को लेकर व्यापक चर्चा बनी हुई है।

मासूम बालक की हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा।

समाज जागरण -ब्रजमोहन सिंह

फिरोजाबाद। मासूम बालक आरव की जमीन पर पटक - पटक कर हत्या करने के मामले में घटना के 40 दिन बाद शुक्रवार को दोषी विराज उर्फ जितेंद्र को मृत्यु दंड (फांसी) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

थाना अरांव क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाली रति की ससुराल बदायूं जनपद में है। महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था, इस कारण वह कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी। 30 मई को रति अपने डेढ़ वर्षीय बेटे आरव के साथ थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अन्तर्गत अपने एक रिश्तेदार के यहां थी, तभी महिला के रिश्ते का देवर विराज उर्फ जितेंद्र वहां पहुंच गया। विराज बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और रास्ते में मासूम आरव की जमीन पर पटककर हत्या करने के बाद शव को नाली में फेंककर भाग गया था। महिला का आरोप था कि हत्यारोपित

विराज उससे शादी करने का दवाब बना रहा था। इसी के चलते उसने उसके मासूम बेटे की हत्या की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपित विराज उर्फ जितेन्द्र पुत्र विजेन्द्र पाल निवासी शेखूपुर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं को मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने जांचोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने की। उन्होंने बताया कि न्यायालय में 13 गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए।

न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के दोषी विराज उर्फ जितेंद्र को दोषी पाते हुए उसे मृत्यदंड (फांसी) की सजा सुनाई है।

सोनभद्र में पौधरोपण को जनभावनाओं से जोड़ने की अनूठी पहल

महर्षि चरक औषधि, समरस और समृद्धि वन समेत बनेंगे कई नए वन

समाज जागरण/ आदिवासी सुनील त्रिपाठी

सोनभद्र। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट मे बैठक की गयी बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के क्रम में प्रदेश में वृक्षा रोपण महायज्ञ 2026 अभियान के तहत प्रदेश में 35 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य 12 जुलाई को रखा गया है जिसके अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में 1 करोड़ 67 लाख 91 हजार सौ पौध रोपण किया जायेगा जिसमें 28 विभागों की वृहद स्तर पर पौध रोपण कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है, पौध रोपण अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जुगैल में आयोजित कार्यक्रम मे सम्मलित होगें

व मण्डलायुक्त विन्ध्यांचल मंण्डल नोडल श्री राजेश प्रकाश रेनूकूट पिपरी में आयोजित पौध रोपण कार्यक्रम में सम्मलित होगें। उन्होनें कहा कि सभी अधिकारी अपने लक्ष्य के अनुरूप पौध उठान की कार्यवाही समय से पूर्ण कर लें।

उन्होंने कहा कि इस अभियान में सरकार ने जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए पौधरोपण महाअभियान की की शुरूआत की गयी है। उन्होने कहा कि अभियान के तहत रोपे गए पौधों को शत-प्रतिशत सुरक्षित रखा जाए और आम-जन को पौधरोपण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरुक भी किया जाए। इसी कड़ी में जनपद में पौधरोपण अभियान को तीज-त्यौहारों व संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के वनों की स्थापना के साथ ही विशिष्ट प्रकार के आयोजन भी किए जाए। जिससे आमजन पौधरोपण के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी जागरुक हो सकें। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कहा कि पौधरोपण महाभियान- 2026 के तहत जिले में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए मानसून में 5 वनों व 1 वाटिका की स्थापना वन विभाग व कई अन्य विभागों द्वारा की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक औषधि वन स्थापित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों का रोपण होगा। इसके अलावा समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन और ऊर्जा वन भी बनाए जाएंगे। इस आयोजन के जरिए लोगों को फलदार पौधे रोपने के लिए जागरुक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष पौधरोपण को सीधे तौर पर जन-भावनाओं और हमारे प्रमुख त्योहारों से जोड़ा जा रहा है। नवीन विशिष्ट वन और मिशन छाया जैसे प्रयास पर्यावरण के प्रति लोगों में एक नई जागरूकता लाने के लिए हैं। वन विभाग की पूरी तैयारी है कि तय तिथियों पर आमजन, छात्र-छात्राओं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ इन विशिष्ट वनों को सफलतापूर्वक स्थापित किया जाए, ताकि जिले में हरियाली का एक स्थायी और समृद्ध वातावरण तैयार हो सके। बताया कि इसलिए जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रीन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिसके माध्यम से आमजन को पौधे लगाने से होने वाले लाभ व पेड़ों की कटान से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि हीटवेट के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश सरकार ने सड़कों के किनारे दोनों तरफ ज्यादा से ज्यादा छायादार पौधे लगाने की योजना बनाई है। इसे मिशन छाया नाम दिया गया है। बताया कि इस मिशन के तहत सड़कों के किनारे छायादार पौधों का रोपण करने के साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।

सड़कों के किनारे रोपे गए पौधे जब बड़े होकर वृक्ष बनेंगे तो सड़कों का तापमान कम रहेगा। जिससे हीटवेट का खतरा कम होगा। इस मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट, प्रभागीय वनाधि कारी ओबरा,

प्रभागीय वनाधिकारी रावर्टसगंज, जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सी0एम0 डैशबोर्ड के रैंकिंग में विकास कार्यों में सोनभद्र को मिला प्रदेश में दूसरा स्थान

जिलाधिकारी के कुशल निर्देशन से हासिल हुई उपलब्धि

समाज जागरण/ अवधेश कुमार गुप्ता

सोनभद्र। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की ओर से किए जा रहे प्रयासों का असर धरातल पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश स्तर पर जारी जून माह की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में विकास कार्यों के मामले में सोनभद्र को प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के कुशल निर्देशन व प्रभावी नेतृत्व के चलते जनपद सोनभद्र ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में सफलता पाई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जून माह के जारी आंकड़ों के मुताबिक सोनभद्र ने विकास कार्यों में जनपद में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों की गणना के लिए निर्धारित 63 सूचकांकों के सापेक्ष जनपद को 59

सूचकांकों में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। सोनभद्र ने विकास कार्यों के मामले में 630 अंकों में 610 अंक प्राप्त कर उकृष्ट प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि सभी विभागों के बेहतर समन्वय, नियमित अनुश्रवण एवं जनहित के प्रति प्रतिबद्ध कार्यशैली का परिणाम है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता सभी के सामूहिक प्रयास, टीम भावना तथा शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप किए गए सतत कार्यों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के मानक के अनुरूप सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा, पारदर्शिता व जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते रहें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप जनशिकायतों एवं विभिन्न विभागीय प्रकरणों का समयबद्ध, संवेदनशील एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग नियमित मॉनिटरिंग करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से जनपद भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में और बेहतर स्थान प्राप्त करेगा।

अखिलेश यादव पर टिप्पणी के विरोध में सपा का प्रदर्शन, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल का फूंका पुतला

समाज जागरण/ अवधेश कुमार गुप्ता

सोनभद्र। समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं ने शुक्रवार को स्वर्ण जयंती चौक पर भाजपा सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकताओं ने मंत्री का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। सपा नेताओं का आरोप है कि राज्य मंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसे पार्टी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री और विधायक लगातार दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के प्रति अपमान जनक बयान दे रहे हैं। उनका आरोप था कि अखिलेश यादव पर की गई कथित टिप्पणी राजनीतिक मयार्दा के विपरीत है और इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं में भारी नाराजगी है। प्रमोद यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न बढ़ा है। उन्होंने मेरठ की

एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि दलित समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि सरकार इस पर मौन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेता राम मंदिर और अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की मूल समस्याओं का समाधान करने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है। कार्यकताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और चेतावनी दी कि यदि विपक्षी नेताओं और पीडीए समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयानबाजी जारी रही तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ता चुप बैठने वाले नहीं। प्रमोद यादव ने कहा भाजपा नेता जाकर बिहार में बिहार सरकार को गाली देने का काम करे जहां पर भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। इस दौरान सुरेश अग्रहरि, शिवा कुमार यादव, कैलाश पटेल, जयप्रकाश भारती, नंदू भारती, बचाऊ बियार, आशीष यादव, मोहन यादव, सियाराम, गोपाल गुप्ता, प्रकाश भारती सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अल्प संख्यक सभा के जिला उपाध्यक्ष जुनैद अंसारी ने किया।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वन ट्रिलियन डॉलर (ओटीडी) सेल की समीक्षा बैठक सम्पन्न

समाज जागरण/ अवधेश कुमार गुप्ता

सोनभद्र। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वन ट्रिलियन डॉलर (ओटीडी) सेल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जनपद का सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 46,929 करोड़ रुपये रहा, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 5,084 करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रकार जनपद ने 12.10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

जनपद की प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 1.55 प्रतिशत की सहभागिता तथा प्रति व्यक्ति आय 1,69,563 रुपये दर्ज की गई, जो प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य एवं वन विभाग सहित प्राथमिक क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण, विद्युत उपभोग एवं स्थानीय निकायों द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति की समीक्षा की गई। विगत दो वर्षों में भवन मानचित्र स्वीकृति में आई कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसमें सुधार के निर्देश दिए गए। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जीएसटी संग्रह, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटल एवं वाहन पंजीकरण तथा वित्तीय सेवाओं की प्रगति की समीक्षा कर आर्थिक गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

डाला में सरकारी पैसे पर पानी के लिए फिरा पानी! 10 लाख का जल पंप तीन साल से बेकार

समाज जागरण/ अनिल कुमार अग्रहरी

डाला/सोनभद्र। जनपद के डाला नगर पंचायत के वार्ड नंबर-10 स्थित लक्ष्मण नगर में लगभग 10 लाख रुपये की लागत से स्थापित सौर ऊर्जा आधारित जल पंप योजना तीन वर्ष बाद भी पूरी तरह विफल साबित हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस दिन से यह जल पंप लगाया गया, उसी दिन से यह बंद पड़ा है और आज तक क्षेत्र के लोगों को दुर्गन्ध की वजह से एक बूंद भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका। वार्ड सदस्य बिंदु सिंह ने बताया कि यह जल पंप सुखसागर पुत्र स्वर्गीय हंसराज की भूमि पर लगाया गया है। उनका कहना है कि इसी स्थान पर पहले से हैंडपंप था, जिससे हमेशा दुर्गंधयुक्त पानी निकलता था। उन्होंने निर्माण से पहले ही नगर पंचायत अध्यक्ष को इस स्थान पर जल पंप नहीं लगाने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी आपत्ति को नजरअंदाज कर कार्य पूरा करा दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार वार्ड के लगभग 50 परिवार इस योजना से लाभान्वित होने वाले थे, लेकिन तीन साल बीतने के बाद भी उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला। लोगों ने आरोप लगाया कि जल पंप अध्यक्ष के

रिश्तेदार के यहां लगाया गया, ताकि भविष्य में सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जा सके। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वार्ड सदस्य का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित शिकायत, टेलीफोन और व्यक्तिगत रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष तथा अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में डाला नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि समस्या की जानकारी है। नए स्थान पर बोरिंग कराने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही जल पंप को स्थानांतरित कर चालू कराया जाएगा। हालांकि, स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब पहले से ही संबंधित स्थान पर जल स्त्रोत और बदबू आने की समस्या की जानकारी थी, तो आखिर 10 लाख रुपये की सरकारी राशि वहां खर्च क्यों की गई। लोगों का कहना है कि यदि योजना तकनीकी जांच के बिना बनाई गई, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही लोगों ने यह भी मांग उठाई कि डाला, चोपन और ओबरा तीनों नगर पंचायतों का प्रभार एक ही अधिशासी अधिकारी के पास होने के कारण स्थानीय समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मांग

की कि अधिशासी अधिकारी सप्ताह में कम से कम चार दिन तय पोस्टिंग स्थान डाला नगर पंचायत में रहकर जनसमस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें।

दो मासूम बहनों की दर्दभरी रात, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

समाज जागरण/ अवधेश कुमार गुप्ता

सोनभद्र। किशोरावस्था की छोटी-छोटी नाराजगी कभी-कभी बड़े हादसों का रूप ले सकती है। दुद्धी क्षेत्र की दो नाबालिग सगी बहनों के साथ घटी घटना ने न केवल परिवारों को झकझोर दिया, बल्कि जिम्मेदार तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुद्धी क्षेत्र से मां की डांट से आहत होकर घर छोड़ने वाली दो नाबालिग सगी बहनों की कहानी ने हर किसी को भावुक कर दिया। दुद्धी रेलवे स्टेशन के समीप सेक्टर नंबर-2 पावर हाउस स्थित काशीराम आवास निवासी महेंद्र की पुत्रियां सीता (17 वर्ष), जो कक्षा 10 की छात्रा है, और मीना (16 वर्ष), कक्षा 6 की छात्रा, मां की डांट से आहत होकर घर छोड़कर निकल गईं। दोनों बहनें रात करीब नौ बजे म्योरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचीं। वहां उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद जीआरपी कर्मी को साफ-साफ बताया कि वे घर से नाराज होकर आई हैं और अपने परिवार से अलग हैं। आरोप है कि इतनी संवेदनशील जानकारी मिलने के बावजूद न तो परिजनों को सूचना दी गई, न ही बाल कल्याण समिति या बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया गया। दोनों बच्चियां पूरी रात रेलवे स्टेशन पर असुरक्षित अवस्था में रहीं। सुबह करीब पांच बजे उन्होंने यह सोचकर ट्रेन पकड़ ली कि वह दुद्धी जाएगी, लेकिन ट्रेन गलत दिशा में होने के कारण वे रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन पहुंच गईं। रॉबर्ट्सगंज स्टेशन से दोनों बहनें पैदल बढ़ौली चौराहे तक पहुंचीं। वहां एक राहगीर के मोबाइल से उन्होंने अपने परिजनों को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के साथ-साथ प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर बाल संरक्षण इकाई की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों को सुरक्षित संरक्षण में लिया। आवश्यक पूछताछ के बाद उन्हें परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई। बड़ी बहन सीता ने बताया कि पिता राजगीर मिस्त्री का काम करते हैं। मां की डांट से दुखी होकर उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और छोटी बहन भी उसके साथ निकल गई। यह घटना केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि यह सवाल भी है कि यदि समय रहते जिम्मेदार एजेंसियां संवेदनशीलता से कार्रवाई करतीं, तो दो मासूम बच्चियों को पूरी रात असुरक्षित हालात में भटकना नहीं पड़ता। अब इस मामले में जीआरपी की भूमिका और कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं तथा जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब की अपेक्षा की जा रही है।

आकाशीय बिजली से दुधारु पशु गाय की मौत, पशुपालक चिंतित, परेशानहाल

समाज जागरण/ अवधेश कुमार गुप्ता

सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के सलखन के मुनगा टोला में बीती रात्रि गुरुवार को तेज गरज,हो रही वर्षा के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से पशुपालक विष्णु शर्मा पुत्र स्व.रामचरित वर्मा निवासी सलखन मुनगा टोला की एक

दुधारू गाय की मौत हो गयी।जिसके संबंध में ग्रामप्रधान, पशु चिकित्सक समेत लेखपाल को अवगत करा दिया गया है। पशुपालक ने बताया कि गुरुवार की शाम को गाय को चारा पानी देने के पश्चात शाम को घर के बगल में पशु को बाध कर सभी लोग घर में सोने चले गये थे। इसी दौरान रात में बरसात के साथ आकाशीय बिजली गिरने से गाय की मौत हो गयी। इससे पशुपालक काफी चिंतित एवं परेशानहाल है।

ममता की गोद हुई सूनी, अवैध अस्पताल की कथित लापरवाही ने छीनी मां और नवजात की सांसें

समाज जागरण/ अवधेश कुमार गुप्ता

सोनभद्र। जिला मुख्यालय पर कथित रूप से बिना वैध पंजीकरण संचालित निजी अस्पतालों की लापरवाही एक बार फिर एक परिवार पर भारी पड़ गई। उरमौरा स्थित सिंह हेल्थ केयर में प्रसव के दौरान कथित चिकित्सीय लापरवाही से 32 वर्षीय मीना देवी और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। इस घटना ने न केवल एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं, बल्कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और निजी अस्पतालों की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बेलखुरी गांव निवासी राजेश अपनी पत्नी मीना देवी को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल के बाहर सक्रिय कथित दलालों ने उन्हें बहला-फुसलाकर उरमौरा स्थित सिंह हेल्थ केयर में भर्ती करा दिया। यहां ऑपरेशन के बाद मृत शिशु का जन्म हुआ और कुछ ही देर बाद प्रसूता की हालत भी बिगड़ गई। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने अपनी

जिम्मेदारी से बचने के लिए मीना देवी को गंभीर हालत बताकर वाराणसी रेफर कर दिया। लेकिन वाराणसी पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक अस्पताल का डॉक्टर और पूरा स्टाफ ताला लगाकर फरार हो चुका था। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। निजी अस्पताल पंजीयन के नोडल अधिकारी डॉ. गुलाब शंकर यादव ने अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सिंह हेल्थ केयर कथित रूप से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। जच्चा-बच्चा की मौत के बाद अस्पताल को सीज कर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मृतका के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और जिला अस्पताल के बाहर सक्रिय कथित दलालों के नेटवर्क पर सख्ती की मांग की है। वहीं, यह घटना एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर बिना मानकों वाले अस्पताल लंबे समय तक कैसे संचालित होते रहे।

टीबीएम दुर्गा ने कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर सफल ब्रेकथ्रू हासिल किया, जोका-एस्प्लेनेड कॉरिडोर पर भूमिगत संपर्क को मिली नई गति

यह कॉरिडोर कोलकाता में पूर्व-पश्चिम संपर्क को सुदृढ़ करेगा और यात्रा में लगने वाले समय तथा सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करेगा

कोलकाता मेट्रो ने आज पर्पल लाइन पर टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) दुर्गा के सफल ब्रेकथ्रू के साथ एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही जोका-एस्प्लेनेड मेट्रो कॉरिडोर पर खिदिरपुर और विक्टोरिया के बीच भूमिगत सुरंग के एक हिस्से का निर्माण पूरा हो गया। आज प्राप्त यह उपलब्धि कोलकाता के शहरी जन परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा शहर की सबसे महत्त्वपूर्ण मेट्रो विस्तार परियोजनाओं में से एक को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम

है।

प्रमुख अंशः

टीबीएम दुर्गा ने विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन पर सफलतापूर्वक ब्रेकथ्रू हासिल किया। 10 जुलाई 2025 को शुरू हुए सुरंग निर्माण कार्य के साथ खिदिरपुर-विक्टोरिया भूमिगत सुरंग का निर्माण पूरा हुआ यह उपलब्धि इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, सटीक योजना और सभी हितधारकों के बीच उत्कृष्ट समन्वय की परिचायक है। सुरंग निर्माण कार्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए तथा सतही यातायात में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए संपन्न किया गया। जोका-एस्प्लेनेड मेट्रो कॉरिडोर शहर के दक्षिणी क्षेत्रों को केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र से जोड़ते हुए कोलकाता में पूर्व-पश्चिम संपर्क में उल्लेखनीय रूप से सुधार करेगा।

इस कॉरिडोर से तेज, सुरक्षित एवं अधिक स्थायी सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे यात्रा में लगने वाला समय कम होगा और सड़कों पर यातायात का दबाव घटेगा।

टीबीएम दुर्गा का सफल ब्रेकथ्रू कोलकाता मेट्रो द्वारा पिछले 50 दिनों के दौरान हासिल की गई अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है।

इससे पहले कोलकाता मेट्रो ने कवि सुभाष-एयरपोर्ट (ऑरेंज लाइन) कॉरिडोर पर चिंगड़ीघाटा में 62 मीटर लंबे महत्त्वपूर्ण वायाडक्ट गैप को सफलतापूर्वक पाट कर निर्माण कार्य की एक बड़ी बाधा को दूर किया था, जिससे इस लाइन को शीघ्र पूरा करने की दिशा में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद, कोलकाता दौरे के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मेट्रो विस्तार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जय हिंद विमानबंदर स्टेशन से नोआपाड़ा स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की, सहयात्रियों से संवाद कर उनकी यात्रा के अनुभव और मेट्रो सेवाओं के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानी तथा मेट्रो कर्मियों से भी मुलाकात की। मंत्री महोदय ने चिंगड़ीघाटा परियोजना स्थल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने हाल ही में पूर्ण हुए वायाडक्ट निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और परियोजना के तेजी से हुए निष्पादन की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अगले 4-5 वर्षों में लगभग 60 नई पीढ़ी की मेट्रो

ट्रेनों को शामिल किए जाने की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2014 के बाद से कोलकाता और उसके आसपास 45 किलोमीटर नए मेट्रो नेटवर्क का संचालन शुरू किया गया है, जबकि वर्ष 2014 से पहले यह आँकड़ा 28 किलोमीटर था।

सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाले औषधि फॉमूर्लेशन के विनियमन को कड़ा करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया।

अधिक अल्कोहल युक्त दवाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी और इन्हें केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही दिया जाएगा 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त दवाएं अब अनुसूची के छूट के अंतर्गत नहीं आतीं; इन्हें अनुसूची एच1 के अंतर्गत शामिल किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियामक निगरानी को मजबूत करने और अधिक मात्रा वाली अल्कोहल औषधीय उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एथिल अल्कोहल युक्त फॉमूर्लेशन के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से मौजूदा छूट (अनुसूची के) को हटा दिया है। कुछ औषधीय उत्पादों, जिनमें इलायची, अदरक और अन्य सुगंधित औषधियों के टिंचर शामिल हैं, को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची 'के' के अंतर्गत लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इनमें से कुछ औषधियों में एथिल अल्कोहल की उच्च सांद्रता होती है, कुछ मामलों में 80-90 प्रतिशत तक, जिससे इनका दुरुपयोग नशा करने के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों से भी संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त सभी उत्पादों को अनुसूची के अंतर्गत दी गई छूट का लाभ नहीं मिलेगा। परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादों को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस संशोधन के तहत इन उत्पादों को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एच1 में स्थानांतरित कर दिया गया है जिसके तहत पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों के पर्चे पर ही इनकी बिक्री अनिवार्य है और रिकॉर्ड रखने के लिए

बस की टक्कर से गोवंश घायल, हिंदू संगठनों में रोष; कार्रवाई की मांग

समाज जागरण
कांधला।(फुरकान जंग)

कस्बे की बड़ी नहर पुल पर एक निजी बस की टक्कर से एक गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है।हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। कस्बे की बड़ी नहर पुल के समीप एक निजी बस के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक गोवंश को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गोवंश सड़क पर गंभीर रूप से घायल होकर

गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद बस चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया। गोवंश की दुर्दशा पर हिंदू संगठनों में रोषबना हुआ है। मामले में कस्बा निवासी अक्षय शर्मा और अनुज कश्यप ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तत्काल सुरक्षित कर बस और चालक की पहचान की जाए, ताकि साक्ष्य नष्ट न हो सकें। और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।और आरोप लगाया गया है कि संबंधित बस से जुड़े कुछ लोगों द्वारा बड़ी नहर की पटरी के आसपास सार्वजनिक स्थान पर अवैध कब्जा कर शोर-शराबा और अभद्रता की जाती है। इस मामले की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

खंद्रावली रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर अज्ञात युवक की मौत

समाज जागरण कांधला।

थाना क्षेत्र के खंद्रावली रेलवे स्टेशन के समीप सहारनपुर से दिल्ली की ओर जा रही एक ट्रेन की चपेट में आने से करीब 30 वर्षीय अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक का शव कई हिस्सों में बिखर गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था। इसी दौरान सहारनपुर से दिल्ली की ओर तेज गति से जा रही ट्रेन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को कुछ दूरी पर रोक दिया और तत्काल रेलवे अधिकारियों व जीआरपी को घटना की सूचना दी।सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीआरपी पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष प्रतीत हो रही है। उसके पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। जीआरपी पुलिस आसपास के थानों को सूचना देने के साथ-साथ मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

बरसात में टापू बना काजीपुरा, पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे

समाज जागरण कांधला।

विकासखंड क्षेत्र के गांव अम्बेहटा के मजरा काजीपुरा में लगातार विगत तीन दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पूरा गांव जलभराव की चपेट में आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव टापू में तब्दील हो गया है और लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने गांव की जल निकासी और विकास कार्यों को लेकर कई बार ग्राम प्रधान एवं विकासखंड अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लापरवाही के चलते बारिश का पानी गांव की गलियों और रास्तों में भर गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया हैसोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्कूली बच्चे पीठ पर बस्ता लटकाए घुटनों तक भरे पानी से होकर स्कूल जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बच्चे जोखिम उठाकर

पानी के बीच से गुजरते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ग्रामीणों ने प्रशासन से समाधान की मांग की है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते जल निकासी और सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य कराए गए होते तो आज उन्हें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

उन्होंने प्रशासन से गांव का निरीक्षण कराकर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत, बोले- अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

समाज जागरण
कांधला।(फुरकान जंग)

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य मोहित बेनीवाल का क्षेत्र के कस्बा एलम पहुंचने पर कार्यकताओं नें स्वागत किया। पूर्व चेयरमैन पति अश्विन पंवार के नेतृत्व में आयोजित स्वागत समारोह में उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहित बेनीवाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और स्वामित्व योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा

है।कार्यक्रम के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों से उनका शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया।इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

रालोद संसदीय बोर्ड सदस्य सुखबीर सिंह गठीना का स्वागत

समाज जागरण

कांधला। क्षेत्र के दिल्ली-सहारनपुर मार्ग स्थित जिला पंचायत सदस्य अरविंद पंवार के प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय लोकदल के संसदीय बोर्ड सदस्य चौधरी सुखबीर सिंह गठीना का क्षेत्र के कार्यकताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया।इस दौरान पूर्व शामली विधानसभा प्रत्याशी बिजेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री एवं रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के प्रयासों से शामली जनपद को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम तथा विभिन्न सड़क निर्माण कार्य कराए गए हैं, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिली है।चौधरी सुखबीर सिंह गठीना ने कहा कि उन्हें चौधरी परिवार की तीनों पीढ़ियों के साथ

काम करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी युवा, शिक्षित और दूरदर्शी नेता हैं, जो किसानों, मजदूरों और युवाओं के हितों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद रालोद अपनी विचारधारा पर कायम है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और कोल्हू संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ना कोल्हू ड्राफ्ट बिल को वापस कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिससे संभावित नुकसान टल गया।कार्यक्रम में विनोद प्रधान, दुष्यंत शर्मा, हरेंद्र मास्टर, विनोद पंवार, विक्रम पंवार, जय कुमार, रविंद्र मलिक, देशपाल, गुलजार, इरफान तुर्की, महावीर कश्यप, भूपेंद्र चौधरी, कपिल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बारिश के चलते मजदूर के मकान की छत गिरी

समाज जागरण

कैराना। क्षेत्र में बारिश के चलते एक मजदूर के मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय घर में मौजूद परिजन बाल-बाल बच गए, लेकिन घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया। क्षेत्र में कई दिनों से रुक-रुक

कर हो रही बारिश के चलते गांव रामड़ा निवासी मजदूर मुकरिम के मकान की कच्ची छत शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे अचानक गिर गई। बताया जाता है कि लगातार पानी पड़ने से छत पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। छत गिरने के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी मलबे की चपेट में नहीं आया। हालांकि, मकान के अंदर रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग की है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को दुरुस्त करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (सीएसआईआर-टीकेडीएल) तक पहुंच संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और आईपी ऑस्ट्रेलिया ने 9 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान सीएसआईआर के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (सीएस आइआर-टीकेडीएल) तक पहुंच के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथोनी अल्बानीज एमपी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। टीकेडीएल पहुंच समझौता शिखर सम्मेलन के दौरान हुई द्विपक्षीय चचाओं के अठारह प्रमुख नतीजों में से एक है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिल्म निर्माण, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया था। भारत ने गलत पेटेंट आवंटन की वजह से अपने समृद्ध पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी तरह का पहला पूर्व-कला डेटाबेस, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) विकसित किया है। इस समझौते के तहत, आईपी ऑस्ट्रेलिया को टीकेडीएल डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त होगी ताकि ऑस्ट्रेलिया के पेटेंट कानूनों और जांच प्रक्रियाओं के अनुसार पेटेंट आवेदनों की जांच करते समय प्रासंगिक पूर्व-कला की पहचान की जा सके। यह समझौता अधिक जानकारीपूर्ण और कुशल पेटेंट जांच को सुगम बनाएगा तथा भारत की प्रलेखित पारंपरिक विरासत का हिस्सा बन चुके ज्ञान पर पेटेंट के आवंटन को रोकने में मदद

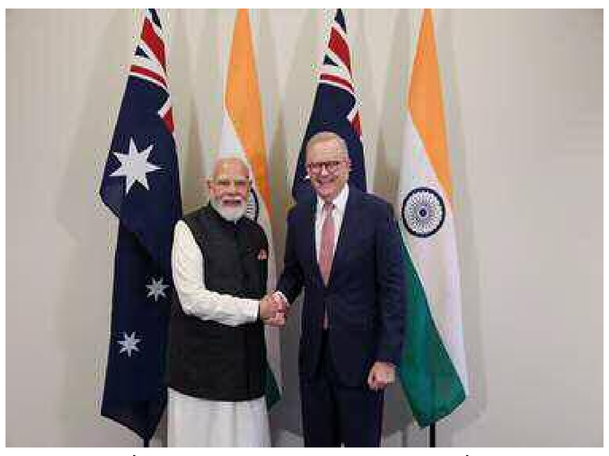

करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही समृद्ध स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, पारंपरिक प्रथाओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के भंडार हैं जो सदियों से विकसित हुई हैं और दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हैं। समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों की पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने और प्रलेखित पूर्व कला के प्रभावी उपयोग के माध्यम से बौद्धिक संपदा प्रणालियों को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख आईपी ऑस्ट्रेलिया के पेटेंट आयुक्त श्री एंड्रयू विल्किंसन; सीएसआईआर की महानिदेशक और डीएसआईआर की सचिव डॉ. एन. कलैसेल्वी; और सीएसआईआर-टीकेडीएल इकाई की वैज्ञानिक-एच और प्रमुख डॉ. विश्वजननी जे. सत्तिगेरी करेंगे।

टीकेडीएल के बारे में

भारत सरकार ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (सीएस आई आर-टीकेडीएल) की स्थापना वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और आयुष मंत्रालय की संयुक्त पहल के माध्यम से वर्ष 2001 में की थी। यह पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए समर्पित विश्व का पहला डेटाबेस है। भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित पेटेंटों के गलत अनुदान को रोकने के उद्देश्य से विकसित सीएस आई आर-टीकेडीएल में अभी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और योग से संबंधित 5.2 लाख से अधिक सूत्रों और प्रथाओं की जानकारी शामिल है। इसका पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं - अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश में अनुवाद किया गया है, ताकि विश्व भर के पेटेंट परीक्षकों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके। आईपी ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर के साथ अठारह पेटेंट कार्यालयों को अब गोपनीयता समझौतों (एनडीए) के तहत डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त है।

सीएसआईआर-टीकेडीएल ने भारत के पारंपरिक ज्ञान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और डेटाबेस से प्राप्त पूर्व कला साक्ष्यों के आधार पर दुनिया भर में 375 से अधिक पेटेंट आवेदनों को रद्द, अस्वीकृत, संशोधित, वापस लिया या त्याग दिया गया है।

मुखबिरी के शक में घर में घुसकर हमला, चार घायल

समाज जागरण

कैराना। गांव तितरवाड़ा में मुखबिरी के शक में घर में घुसकर लाठी–डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें भाई बहन और उनकी मां घायल हो गई। दूसरे पक्ष से भी एक महिला घायल हुई।। पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया। गुरुवार को पुलिस ने गांव तितरवाड़ा निवासी महिला मानो को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। उसके मकान के सामने रहने वाले सादा ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि शुक्रवार सुबह करीब दस बजे उनके महिला के परिवार के लोग लाठी–डंडे और धारदार हथियार लेकर उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उन पर मुखबिरी कर महिला को पकड़वाने का आरोप लगाया। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी–डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उसका बेटा जावेद, बेटी सना तथा पत्नी सलमो बुरी तरह घायल हो गई। झगडे के दौरान दूसरे पक्ष की महिला परवीन भी घायल हो गई। पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी चारों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

तमंचे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

समाज जागरण

कैराना। गुरुवार रात पुलिस शामली बाईपास के निकट चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक को रोककर तलाशी ली, जिसके कब्जे से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया। मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नदीम निवासी मोहल्ला आर्यपुरी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके चालान कर दिया।

जुआ खेलते हुए दो आरोपी गिरफ्तार

समाज जागरण

कैराना। गुरुवार शाम पुलिस पानीपत बाईपास के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पानीपत बाईपास फ्लाईओवर के निकट एक ट्यूबवेल पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से जुआ खेल रहे राजू निवासी मोहल्ला खैलकलां इमाम गेट व इमरान निवासी मोहल्ला पीरजादगान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1360 रुपये की नकदी और ताश की गड्डी बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कोयंबटूर स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान-सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया; मानव-वन्यजीव संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल का भी शुभारंभ किया

संघर्ष के बजाय सह-अस्तित्व और सद्भाव पारिस्थितिक स्थिरता का मूलमंत्र होना चाहिए: श्री भूपेंद्र यादव

मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए चुनौतियों, नवाचार
और सहयोगात्मक समाधानों पर विचार-विमर्श हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज कोयंबटूर में मानव-वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देश भर के वरिष्ठ नीति निमार्ता, वन प्रबंधक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और संरक्षण कार्यकर्ता एक राष्ट्रीय कार्यशाला में मानव-वन्यजीव संघर्ष को घटाने की प्रभावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए जुटे। समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य भाषण में श्री यादव ने कहा कि पयार्वास के विखंडन, भूमि उपयोग की बदलती प्रवृत्तियों और मानवीय गतिविधियों के विस्तार के चलते लोगों और वन्यजीवों के बीच बढ़ते अंतसंबंध ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को भारत की प्रमुख संरक्षण और विकास चुनौतियों में से एक बना दिया है। उन्होंने कहा कि हमें समस्या-केंद्रित होने के बजाय समाधान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आधुनिक तकनीकी प्रगति का उपयोग करना चाहिए।

श्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान की गई घोषणा के अनुसार, यह नया उत्कृष्टता केंद्र मानव-वन्यजीव संघर्ष के वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अनुसंधान, नवाचार, नीतिगत समर्थन, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम नियमों के प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि यह संस्थान बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों, तेंदुओं और हाथियों के साथ मानव संघर्षों के प्रबंधन हेतु नीति निर्माण की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्षों से निपटने के तरीकों के बारे में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मिशन-आधारित जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण में मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट और प्रजाति-विशिष्ट उपाय शामिल होने चाहिए। इससे समाज में व्याप्त भय को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। श्री यादव ने देशभर के वन विभागों से आग्रह किया कि वे ऐसे संघर्षों और मानव बस्तियों एवं फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए

सक्रिय निवारक उपाय करें। उन्होंने कहा कि संबंधित समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करके और बहु-हितधारक परामर्श के माध्यम से मुद्दों का समाधान करके ये उपाय किए जाने चाहिए। वन्यजीव संरक्षण में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए नवीन और सर्वोत्तम पद्धतियों को विकसित कर इन्हें व्यापक रूप से लागू किए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन के समापन में कहा कि संघर्ष के बजाय सह-अस्तित्व और सद्भाव पारिस्थितिक स्थिरता का मूलमंत्र होना चाहिए।

श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभावी वन्यजीव संरक्षण की सफलता से मानव-वन्यजीव अंतसंबंध में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप संरक्षण के मुद्दे के साथ-साथ एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हुई है, जो दीर्घकालिक रूप से आजीविका को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर दीर्घकालिक समाधान खोजने की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह उत्कृष्टता केंद्र अधिकारियों और समुदाय की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र वन्यजीव संरक्षण और शांतिपूर्ण मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए, आंकड़ों के दस्तावेजीकरण में उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग में बहुत सहायक होगा।

उद्घाटन सत्र के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल का भी शुभारंभ किया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे देश भर में संघर्ष को कम करने के लिए डेटा प्रबंधन, ज्ञान साझाकरण और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ' भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष की वर्तमान स्थिति: एक अवलोकन' शीर्षक से प्रकाशित प्रकाशनों की श्रृंखला का पहला संस्करण भी जारी किया गया। इसमें देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित वर्तमान स्थिति, रुझानों और उभरती चुनौतियों का व्यापक आकलन प्रस्तुत किया गया है।

कार्यशाला के तकनीकी सत्रों के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष पोर्टल का लाइव प्रदर्शन किया गया। इसके बाद विशेषज्ञों की प्रस्तुतियां और पैनल चचाएं हुईं, जिनमें निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

मानव–हाथी संघर्ष;

मनुष्यों और बाघ, तेंदुए, शेर के बीच संघर्ष और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार इन विचार-विमर्श से मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन पर राष्ट्रीय रणनीतियों को मजबूत करने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार लाने और लोगों तथा वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी। इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भारत सरकार की जैव विविधता संरक्षण और मानव जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की निरंतर प्रतिबद्धता को दशार्ती है, जिसके लिए विज्ञान आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और समुदाय-उन्मुख दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, वन महानिदेशक और विशेष सचिव, एडीजी (वन्यजीव), भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक, मंत्रालय के
वरिष्ठ अधिकारी, राज्य वन विभाग, शैक्षणिक संस्थान और सहयोगी संगठन शामिल थे।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम – प्रश्नोत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 23 जून, 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसमें भ्रामक सूचनाओं को दूर करते हुए तथ्यात्मक स्पष्टीकरण दिए गए थे। वाहन निमार्ता कंपनियों ने भी 4 जुलाई, 2026 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्यक्रम के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए। इन स्पष्टीकरणों के बावजूद, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। निम्नलिखित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) इन चिंताओं के तथ्यात्मक और साक्ष्य-आधारित उत्तर प्रदान करते हैं। प्रश्न 1: ब्राजील जैसे देशों को इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्यों को हासिल करने में दशकों लग गए, तो भारत ने ऐसा करने में जल्दबाजी क्यों दिखाई? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है ।हमने इथेनॉल का आविष्कार नहीं किया है। एक सदी से भी अधिक समय पहले हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी को इथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन किया था और ब्राजील तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के अनेक देश दशकों से इथेनॉल मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं। यह भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शुरू नहीं हुआ था। इस पहल का एक लंबा संस्थागत इतिहास और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं (ये सभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं- कुछ अनुलग्नक-1 में दी गई हैं)। वर्ष 2001 में एक प्रायोगिक इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसकी औपचारिक घोषणा 2004 में की गई और वर्ष 2006 तक कई राज्यों में ई 5 (पांच प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण) को लागू किया गया। इस नीतिगत ढांचे को बाद में संप्रग सरकार के दौरान जनवरी 2013 में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

भारत विकास परिषद के 64 वे स्थापना दिवस पर शाखा कालांवाली द्वारा विशाल मेडिकल फ्री कैंप आयोजित

समाज जागरण

कालांवाली (सुरेश जोरासिया) भारत विकास परिषद के 64 वे स्थापना दिवस पर 10 जुलाई 1963 सेवा पखवाडे के अन्तर्गत शाखा कालां वाली द्वारा विशाल मेडिकल फ्री कैंप एवं पंचकर्म थेरेपी-आयुर्वेद उपचार कैंप, 10 जुलाई,2026 सुबह 9.00 से 1.00 बजे तक,तेरापंथ जैन भवन नजदीक शिवबाडी मंदिर, कालां वाली में आयोजित किया गया। इस कैंप का उद्घघाटन श्री सिकंदर बाहिया, नगर पार्षद व उपाध्यक्ष-नगर पालिका द्वारा किया गया। श्री सुभाष शर्मा, नगर पार्षद विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए।

इस कैंप में आँखों की जांच *श्री गुरू नानक (आई) अस्पताल के डॉक्टर कश्मीर सिंह द्वारा सेवाएँ दी

गईं , डैंटल चैकअप कैम्प में मोंगा डैंटल क्लीनिक के डॉ॰ विशाल मोंगा दाँतों की जांच की गई,जरूरतमंद मरीजों का मुफ्त एक्स-रे व दवाईयां प्रदान की गई। शुगर, पत्थरी, रसोली, स्त्री रोग व अन्य रोगियों की जांच, आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ होम्यो पैथिक जैन अस्पताल, कालां वाली के डॉ॰ सोहन सिंह, ज्योति रानी ने अपनी टीम के साथ सेवाएँ प्रदान की। होम्योपैथिक दवाईयां भी मुफ्त प्रदान की गई। शुगर व अन्य जांच पब्लिक कंप्यूटराइज्ड लैब के श्री अविनाश गर्ग द्वारा की गई। पंचकर्म थेरेपी एवं आयुर्वेदिक प्राकृतिक उपचार, अर दास हॉस्पिटल एवं पंचकर्म सेंटर के डॉ॰ केशव शर्मा व डॉ॰ प्राची शर्मा (चण्डीगढ़ वाले) की टीम द्वारा अपनी सेवाएँ प्रदान की। इस कैंप में 65 मरीजो ने चैक-अप करवाकर सेवा का लाभ उठाया। स्थापना दिवस समारोह में संस्थापक अध्यक्ष श्री दिनेश गर्ग जैन ने बताया कि परिषद की स्थापना 63 वर्ष पूर्व डॉ. सूरज प्रकाश द्वारा नई दिल्ली में धनी व बुद्धिजीवों को जोड़ने के लिए की गई। परिषद द्वारा आज देश भर में सेवा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का शसक्त माध्यम बन चुका है। कालांवाली शाखा भी 24 वर्षों से सेवा संस्कार के कार्यों द्वारा प्रांत व क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान रखती है। चेयरमैन चरण दास चन्नी ने बताया कि इस समारोह में समाज सेवा के लिए डॉ कश्मीर सिंह, डॉक्टर केशव-प्राची शर्मा, डॉ विशाल मोंगा, डॉ सोहन सिंह व अविनाश गर्ग ,नीलम शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस समारोह में संस्थापक अध्यक्ष दिनेश गर्ग जैन, संरक्षक मोहन लाल बांसल, अध्यक्ष अजय गर्ग जैमको, सचिव सतीश राजपाल, परिकल्प संयोजक चरणदास चन्नी, राकेश जैन सह संयोजक, भूषण जैन, नरेश गर्ग पटवारी व तुषार गर्ग व अन्य सदस्यों की गरिमामयी सेवायें रही। समारोह के अंत में राष्ट्रगान जन गण मन..... के सामूहिक गायन के साथ संपन्न हुआ।

परिवार पहचान पत्र में आय संशोधन के लिए स्वयं घोषणा पत्र ही पर्याप्त : अतिरिक्त उपायुक्त

समाज जागरण

सिरसा/कालांवाली 10 जुलाई (सुरेशजोरासिया) अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने बताया कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में आय संशोधन के लिए आवश्यक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर किसी भी प्रकार की नोटरी अथवा स्टाम्प पेपर खरीद की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग अनावश्यक रूप से नोटरी या स्टाम्प पेपर बनवाने की सलाह देकर आमजन का समय और धन दोनों व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसे किसी भी भ्रामक प्रचार पर ध्यान न दें। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि परिवार पहचान पत्र में आय संशोधन

के लिए केवल निर्धारित सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही बिना नोटरी या स्टाम्प पेपर के जमा करें।

बलोद, छत्तीसगढ़ का जनभागीदारी मॉडल कैच द रेन अभियान को नई गति मिली

जन भागीदारी योजना के जरिए जेएसजेबी 2.0 के तहत बलोद में 2.84 लाख से अधिक जल संरक्षण तालाबों का निर्माण हुआ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 135वें संस्करण के दौरान #

कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने का आह्वान किया था। इस आह्वान के जवाब में छत्तीसगढ़ का बलोद जिला जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 के तहत समुदाय-संचालित जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों और जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से, बलोद जिला ने वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए कई तरह की परियोजनाएं लागू की हैं, जिनके ठोस परिणाम वर्तमान मॉनसून के दौरान दिखाई दे रहे हैं। बलोद जिले ने जून 2025 से मई 2026 के बीच 2,84,917 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं, जिससे वर्षा जल को एकत्रित और संरक्षित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, नाश्ता दुकान, चाट एवं फुल्की संचालकों के लिए आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम

समाज जागरण जिला संवाददाता उदय सिंह लोधी

दमोह। जिले में सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, नाश्ता दुकान तथा चाट-फुल्की संचालकों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयो जित किया। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि नियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए व्यापारियों को खाद्य स्वच्छता (फूड हाइजीन) के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य व्यापारियों को अखबार के कागज में खाद्य सामग्री पैक या परोसने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी

दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान खाद्य सुरक्षा प्रशासन के जिला अधिकारी राकेश अहिर वाल एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने बताया कि अखबार की स्याही में लेड सहित कई हानिकारक रसायन एवं हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, जो गर्म या तैलीय खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर भोजन में मिल जाते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करने से पेट संबंधी बीमारियां, पाचन तंत्र की समस्याएं, लीवर एवं किडनी पर दुष्प्रभाव तथा लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य सामग्री को अखबार के कागज में पैक या परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। व्यापारियों से अपील की गई कि वे केवल फूड ग्रेड पेपर एवं सुरक्षित पैकिंग सामग्री का ही उपयोग करें ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्रम में चाट एवं फुल्की विक्रेताओं को मेटानिल येलो एवं टाट्राजींन जैसे प्रतिबंधित रंगों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही खाद्य सामग्री तैयार करने एवं तलने में उपयोग होने वाले खाद्य तेल का दो बार से अधिक उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई। होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले खाद्य तेल, घी एवं वनस्पति की जानकारी नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले के उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे अखबार में पैक या परोसी गई खाद्य सामग्री का सेवन करने से बचें तथा स्वच्छ एवं फूड ग्रेड पैकिंग में उपलब्ध खाद्य सामग्री को ही प्राथमिकता दें। यदि कोई खाद्य व्यापारी खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी सूचना खाद्य सुरक्षा प्रशासन को देने की अपील भी की गई।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट, नाश्ता दुकान तथा चाट-फुल्की संचालकों ने भाग लेकर सुरक्षित खाद्य प्रबंधन एवं स्वच्छता संबंधी आवश्यक जानकारियां प्राप्त कीं।

65 लाख की लागत से बने उप-स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण, अब ग्रामीणों को गांव में मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

समाज जागरण जिला संवाददाता उदय सिंह लोधी

जबेरा (दमोह)। जबेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिलतरा में लंबे इंतजार के बाद 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित उप-स्वास्थ्य केंद्र का शुक्रवार को प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री श्री लोधी ने कहा कि इस उप-स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने से न केवल बिलतरा ग्राम बल्कि आसपास के अनेक गांवों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अब सामान्य उपचार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। राज्यमंत्री श्री लोधी ने बताया कि इस भवन का निर्माण लगभग दो वर्षों तक केवल इसलिए रुका रहा क्योंकि ग्राम में शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं थी। ऐसे समय में ग्राम के रजक परिवार ने समाजहित को सर्वोपरि रखते हुए सड़क से लगी अपनी निजी भूमि दान में दी, जिसके बाद निर्माण कार्य पूरा हो सका। उन्होंने रजक परिवार के इस सराहनीय योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी हैं और जनसेवा की सच्ची मिसाल प्रस्तुत करते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। नए स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को उसके गांव के निकट ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने भी उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा, विशेषकर गर्भवती महि लाओं, बच्चों और बुजुर्गों को समय पर उपचार उपलब्ध हो सकेगा।

समारोह के दौरान जनप्रतिनिधियों ने उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया तथा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

गोबर और गोमूत्र आधारित उत्पादों से आत्मनिर्भर बनें गौशालाएं : राज्यमंत्री लखन पटेल

तेंदूखेड़ा की दयोदय गौशाला में जिला स्तरीय कार्यशाला , गौशाला संचालकों को दिए आत्मनिर्भरता के गुर

समाज जागरण जिला संवाददाता उदय सिंह लोधी

दमोह। जिले की गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को तेंदूखेड़ा स्थित दयोदय गौशाला में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले की विभिन्न गौशालाओं के संचालकों ने भाग लेकर अपने अनुभव साझा किए तथा गौशालाओं के बेहतर संचालन और आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल एवं संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित

रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गौसंरक्षण और गोसेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार गौमाता के भरण-पोषण के लिए प्रति गाय 1200 रुपये प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध करा रही है। साथ ही विभिन्न जनक ल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को भी निरंतर लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए शासन हर संभव सहयोग दे रहा है।

राज्यमंत्री लखन पटेल ने कहा कि दमोह जिले में संचालित 56 गौशालाओं को केवल सरकारी सहायता पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने गौशाला संचालकों से आह्वान किया कि गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, जैविक खाद तथा गोमूत्र से फिनाइल, जैविक कीटनाशक एवं अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार कर उनका व्यवस्थित विपणन करें। इससे गौशालाओं की आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और गौशालाएं इस क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं तलाश सकती हैं। कार्यक्रम में आनंदधाम के पीठा धीश्वर रंजीतानंद स्वामी ने गौसंरक्षण के सामाजिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गौमाता भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि स्वार्थवश गौवंश को सड़कों पर छोड़ देना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति को गौसंरक्षण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान हो सके। स्वामी अखलें द्रनाथ ने कहा कि यदि प्रत्येक परिवार कम से कम एक गौमाता

के पालन का संकल्प ले, तो निराश्रित गौवंश की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। उन्होंने गौसेवा को समाज और संस्कृति की सेवा बताते हुए लोगों से इस दिशा में आगे आने का आह्वान किया।

दमोह में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, थोक तेल एजेंसियों और फूड स्टोर्स पर औचक निरीक्षण

रिफाइंड सोयाबीन तेल, दूध पाउडर और शक्कर के नमूने जांच के लिए भेजे गए, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

समाज जागरण जिला संवाददाता उदय सिंह लोधी

दमोह। जिले में खाद्य पदार्थों की गुण वत्ता सुनिश्चित करने और उपभो क्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न थोक खाद्य तेल विक्रेताओं एवं रिटेल फूड स्टोर्स पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया। यह कार्रवाई कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गठित खाद्य सुरक्षा जांच दल द्वारा की गई। निरीक्षण के दौरान टीम सबसे पहले चरहाई बाजार स्थित फर्म देवीप्रसाद बाबूलाल पहुंची। यहां विक्रय के लिए संग्रहित किंग्स ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना लेकर विधिवत सीलबंद किया गया। इसके बाद जांच दल ने मीट मार्केट क्षेत्र स्थित फर्म गणेशलाल तांतुलाल एवं के.के. ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। यहां संग्रहित सोयल ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन तेल तथा शक्कर के नमूने

गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिए गए। अभियान के दौरान टीम ने वृद्धाश्रम के पास स्थित रौनक ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया। यहां से नोवा ब्रांड दूध पाउडर का नमूना लेकर परीक्षण के लिए सुरक्षित किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि सभी नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीलबंद कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिया गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ता संबंधी कमी अथवा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि जिले में मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित मानकों का पालन करने तथा उपभोक्ताओं से खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता और पैकिंग पर विशेष ध्यान देने की अपील की है।

धागा व्यवसायियों के साथ व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित, पतंग के धागे की आड़ में चाइनीज मांझे के व्यापार पर रोक लगाने का आह्वान।

समाज जागरण

फिरोजाबाद शासन के निदेर्शानुसार जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 जुलाई, 2026 को अपराह्न 1:00 बजे वाणिज्य कर भवन सभागार में धागा (Threads) निर्माण एवं व्यापार से जुड़े व्यापारियों के साथ व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना, वैध व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा पतंग के सामान्य धागे की आड़ में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने के लिए व्यापारियों को जागरूक करना था। वैसे तो फिरोजाबाद में इस ट्रेड के रजिस्टर्ड व्यापारी नगण्य हैं फिर भी जो छोटे -बड़े व्यापारी इस व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें आमंत्रित किया गया और उन्हीं के साथ बैठक की गई ' कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त राज्य कर श्री धर्मेंद्र बहादुर द्वारा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त राज्य कर श्री असित कुमार सिंह, राज्य कर अधिकारी श्री बृजेश कुमार, राज्य कर अधिकारी श्री शेखर चौरसिया, सहायक आयुक्त राज्य कर सुश्री सृष्टि जैन, सहायक आयुक्त राज्य कर श्री राधा स्वामी मौर्य सहित अन्य राज्य कर अधिकारी उपस्थित रहे।

व्यापारी वर्ग की ओर से श्री सुनील अग्रवाल, श्री राजेश जैन,श्री शमशेर अली, श्री फिरोज खान, श्री अतौर

रहमान, श्री खालिद एवं श्री तारीख सहित धागा निर्माण एवं व्यापार से जुड़े अनेक व्यापारी एवं प्रतिनिधि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि पतंग के सामान्य धागे की आड़ में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का निर्माण एवं विक्रय समाज के लिए अत्यंत घातक है। चाइनीज मांझे के कारण विगत वर्षों में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को गंभीर क्षति पहुँची है तथा कई मामलों में जनहानि भी हुई है। अतः मानव जीवन एवं जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे हानिकारक चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय से पूर्णतः दूर रहने तथा इसके विरुद्ध जनजागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया।

व्यापारी प्रतिनिधियों ने विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि वे प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के निर्माण एवं व्यापार में किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं रखेंगे तथा अपने व्यापारिक समुदाय को भी इसके दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही व्यापारियों द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों पर विभागीय अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा करते हुए उनके यथासंभव त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित व्यापारियों ने सुरक्षित,

वैध एवं उत्तरदायी व्यापार को बढ़ावा देने तथा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया।

मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन में अधिकारियों व कर्मचारियों को सौंपे पौधे, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश।

समाज जागरण

फिरोजाबाद। जनपद में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की गई है। मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने विकास भवन कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम के तहत वहां तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पौधे वितरित किए। पौधों को सौंपते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने सभी उपस्थित अधिकारीगण और कर्मचारियों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण

बेहद आवश्यक है। केवल पौधा लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक अभिभावक की तरह उसकी देखभाल करना और उसे वृक्ष के रूप में विकसित करना हम सभी का नैतिक दायित्व है।

उन्होंने विकास भवन के समस्त स्टाफ से अपील की कि वे इन पौधों को अपने घरों व आसपास रोपित कर उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लें। इस अवसर पर विकास भवन के अधिकारी और कर्मचारी हाथों में पौधे लेकर पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने मुख्य विकास अधिकारी के इस संदेश की सराहना की और रोपे गए पौधों की सुरक्षा व पोषण करने की प्रतिबद्धता जताई।

कोर्ट जाते समय पिता-पुत्र पर फायरिंग, हत्या के मुकदमे की रंजिश में हमला

दाहिने हाथ में गोली लगने से युवक घायल, घर में घुसकर बचाई जान, चार नामजद समेत सात-आठ लोगों पर आरोप।

समाज जागरण

मक्खनपुर। दबरई स्थित कोर्ट में तारीख पर जा रहे पिता-पुत्र पर शुक्रवार को दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। गोली युवक के दाहिने हाथ में लगी। जान बचाने के लिए वह पास के एक मकान में घुस गया। ग्रामीणों के जुटते ही हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के पीछे वर्ष 2025 के हत्या के मुकदमे की रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने घायल का ट्रामा सेंटर में मेडिकल कराया है। वहीं, तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। थाना

नसीरपुर क्षेत्र के गांव मढ़ैया नंदराम निवासी मनोज (28) शुक्रवार को अपने पिता दिनेशचंद्र के साथ बाइक से कोर्ट में तारीख पर जा रहा था। आरोप है कि धौरऊ चौराहे के पास पहुंचते ही एक सफेद रंग की अपाचे बाइक और एक बोलेरो में सवार हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान मनोज के दाहिने हाथ में गोली लग गई, जिससे वह बाइक से गिर पड़ा। घायल मनोज किसी तरह भागकर धौरऊ निवासी सत्यवीर सिंह के मकान में घुस गया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार हो गए। घायल मनोज ने इलाका पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भेजा और मेडिकल कराया है। पीड़ित मनोज ने आरोप लगाया 2025 का हत्या का मामला चला आ रहा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित की तहरीर में चार नामजद और तीन-चार अज्ञात लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।